3 | राजधानी
लापरवाही में चिकित्सकों पर गिरी गाज

6 | अभिमत
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार

11 | विदेश
चीनी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर

12 | स्पोर्ट्स
तुषारा भारत के खिलाफ टी20 शृंखला से बाहर

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 273
लखनऊ, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षिका की भूमिका में आईं नजर

राष्ट्रीय-10

पीएम का दौरा, जम्मू कश्मीर हाईअलर्ट पर

मोहित कंडारी। जम्मू/नई दिल्ली

चिनार कोर की अग्रिम चौकियों का निरीक्षण करते हुए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान नियंत्रण रेखा पर भी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

द्रास में शुक्रवार को 25वें कारगिल विजय दिवस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद इस क्षेत्र में पीएम की यह पहली यात्रा होगी और इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में कुछ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी होंगी, जिनमें से दो की अध्यक्षता खुद पीएम करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, जो बृहस्पतिवार सुबह श्रीनगर पहुंचे, ने घुसपैठ विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ आगे के इलाकों का दौरा किया।

बाद में सेना प्रमुख व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए कारगिल के लिए रवाना हुए। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट जिले के एक गांव में सात संदिग्ध आतंकवादियों को देखे जाने के बाद जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। एहतियात के तौर पर जम्मू क्षेत्र और राजमार्ग के किनारे स्थित सेना प्रतिष्ठानों के कई स्कूलों को 29 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। संदिग्धों का पता लगाने के लिए कठुआ (जम्मू) और पठानकोट के सीमावर्ती इलाकों में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री वस्तुत: शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किमी लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू - पदुम - दारचा रोड पर लगभग (शेष पेज 9)

ममता के आश्रय देने संबंधी बयान पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बृहस्पतिवार को ढाका से एक नोट प्राप्त होने की पुष्टि की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त की गई है, जिसमें उस देश में हिंसक झड़पों से प्रभावित लोगों को आश्रय देने की पेशकश की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने इससे पहले देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के लोगों को 'आश्रय' की पेशकश करने की बनर्जी की हालिया टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बनर्जी की टिप्पणियों को अस्वीकार करते हुए कहा कि जो मामले संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, वे केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं। कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने संबोधन में बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि वह पड़ोसी देश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय प्रदान करेंगी। बांग्लादेशी मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि ढाका ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। (शेष पेज 9)

बलिया पुलिस की वसूली मामले में एसपी और एएसपी हटाए गए, सीओ निलंबित

- आरोपी पुलिस अधिकारियों की संपत्तियों की विजिलेंस करेगी जांच
- बिहार सीमा पर ट्रकों से पुलिस हर रात कर रही थी पांच लाख की वसूली

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बलिया में पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली करने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन ने एसपी बलिया देव रंजन वर्मा और एडिशनल एसपी दुर्गा तिवारी को हटाते हुए दोनों को प्रतीक्षारत कर दिया है। वही संबंधित सर्किल के सीओ शुभ सुचित को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सीओए थानाध्यक्ष नरही और चौकी प्रभारी कोरंटाडीह की संपत्तियों की खुली विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत यूपी पुलिस ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सटीक सूचना के आधार पर खुद एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने पुलिस टीम के साथ बीती रात छापेमारी कर बलिया पुलिस द्वारा संगठित गिरोह के साथ मिलकर ट्रकों से बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध वसूली का खुलासा किया। मौके से दो पुलिस कर्मी गिरफ्तार किए गए जबकि तीन सिपाही भागने में सफल रहे। टीम ने 16 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। एडीजी और डीआईजी के निर्देश पर वसूली में संलिप्त थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिस कर्मियों के आवासों को भी सील कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान थानाध्यक्ष नरही अपने थाने से फरार हो गया। जिसकी तलाश की जा रही है। विवेचना के क्रम में आरोपी पुलिस कर्मियों के सील किए गए आवासीय परिसर की अहम सर्च एवं सीजर में वसूली के धन से सम्बन्धित कैश की भी जांच की जाएगी।

आजमगढ़ रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर बक्सर, बिहार से जनपद बलिया (यूपी) में आने वाली ट्रकों से थाना नरही के भरौली तिराहा पर पुलिस कर्मियों द्वारा कुछ दलालों के माध्यम से अवैध वसूली कराई जा रही है। इस सूचना पर डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोर्डिया और डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण को सूचना सत्यापित करने और सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने सादे वस्त्रों में पुलिस टीम के साथ बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो वहां पुलिस कर्मियों द्वारा क्षेत्र से गुजरने वाले ट्रकों से संगठित गिरोह के साथ अवैध वसूली की जा रही थी। छापेमारी से हड़कंप मच गया। टीम ने एक सिपाही हरदयाल सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जबकि एक हेडकांस्टेबल विष्णु यादव और दो अन्य सिपाही दीपक मिश्रा और बलराम सिंह फरार हो गए। टीम ने मौके से 16 दलालों रविशंकर यादव, विवेक शर्मा, जितेश चौधरी, वीरेन्द्र राय, सोनू सिंह, (शेष पेज 9)

थानाध्यक्ष सहित 19 पुलिस कर्मी निलंबित

इस प्रकरण में डीआईजी आजमगढ़ रेंज के पीआरओ इंस्पेक्टर सुशील कुमार यादव की ओर से थानाध्यक्ष नरही पन्नेलाल, चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह राजेश कुमार प्रभाकर सहित 7 पुलिसकर्मी यथा मुख्य आरक्षी हरिदयाल सिंह, मुख्य आरक्षी विष्णु यादव, आरक्षी सतीश गुप्ता, आरक्षी दीपक मिश्रा, आरक्षी बलराम सिंह एवं 16 दलालों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसकी विवेचना डीजीआई आजमगढ़ रेंज द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दी गई है। प्रथम दृष्टया पर्यवेक्षण में दोषी पाये जाने पर थानाध्यक्ष नरही पन्नेलाल, को निलम्बित किया गया है। इसके अलावा चौकी प्रभारी कोरंटाडीह राजेश कुमार प्रभाकर को निलम्बित किया गया है एवं सम्पूर्ण कोरंटाडीह पुलिस चौकी के 8 पुलिस कर्मी, जिनमें चौकी प्रभारी के अतिरिक्त 2 मुख्य आरक्षी-चन्द्रजीत यादव व औरंगजेब खॉ एवं 5 आरक्षी-परविन्द यादव, सतीश चन्द्र गुप्ता, पंकज कुमार यादव, ज्ञानचन्द्र व धर्मवीर पटेल सम्मिलित है, को भी निलम्बित किया गया है। थाना नरही के थाना प्रभारी के अतिरिक्त एक उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद (रात्रि दिवसाधिकारी, एक मुख्य आरक्षी विष्णु यादव, 5 आरक्षी-हरिदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर व प्रशान्त सिंह एवं 1 आरक्षी चालक ओम प्रकाश को निलम्बित किया गया है। इस प्रकार थानाध्यक्ष नरही एवं चौकी प्रभारी कोरंटाडीह सहित 3 उपनिरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी एवं 1 आरक्षी चालक को निलम्बित किया गया है।

राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है और संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधाई अधिकार है। इस फैसले से झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय से केंद्र द्वारा खदानों और खनिजों पर अब तक लगाए गए हजारों करोड़ रुपए के करों की वसूली पर फैसला करने का आग्रह किया था। राज्यों ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि केंद्र से करों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि दलीलों का कड़ा विरोध किया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र और

राज्यों से इस पहलू पर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और कहा कि वह 31 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला करेगी। उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर नहीं है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने और पीठ के सात न्यायाधीशों के फैसले को पढ़ा जिसमें कहा गया कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। बहुमत के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं है जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है। (शेष पेज 9)

बजट पर चर्चा के बजाय पीएम पर निशाना साध रहा विपक्ष: रिजिजू

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र ने बृहस्पतिवार को विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि उन्होंने दस्तावेज़ के बारीक पहलुओं पर बोलने के बजाय संसद में केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सहारा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से कुछ विपक्षी नेताओं ने अपने भाषण दिए, वह सदन का अपमान करने और बजट सत्र की गरिमा को कम करने जैसा है। रिजिजू ने एक प्रेस वार्ता में कहा, आइए हम लोगों के जनादेश का सम्मान करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। अगर कोई लोगों के फैसले का अपमान करने की कोशिश करता है तो उन्हें चुनाव में दंडित किया जाएगा।

उनकी यह टिप्पणी विपक्ष के इस दावे के एक दिन बाद आई है कि केंद्रीय बजट गैर-एनडीए शासित राज्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री पर अस्थिर और कमजोर गठबंधन सरकार चलाने का आरोप लगाया। बुधवार को लोकसभा में 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान, विभिन्न विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर प्रमुख सहयोगियों जेडी-यू और टीडीपी को रियायतें देने का आरोप लगाया, जो क्रमश: बिहार और आंध्र प्रदेश पर शासन करते हैं, ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके। अपने गठबंधन सहयोगियों से कोई बाधा नहीं आती। रिजिजू ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब ध्यान विकसित भारत की दिशा में काम करने और केंद्रीय बजट पर रचनात्मक चर्चा करने पर होना चाहिए। रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब समय राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर देश के लिए मिलकर काम करने का है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदस्यों से सम्मान बनाए रखने और ऐसी टिप्पणी नहीं करने को कहा (शेष पेज 9)

तकनीक से परीक्षा सुरक्षा बढ़ाएगा यूपीएससी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

यूपीएससी और सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षाओं सहित इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित कई विवादों के बाद, आयोग अब आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, चेहरे की पहचान प्रणाली और एआई जैसे उन्नत तकनीकी समाधानों को शामिल करके अपने परीक्षा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव, यूपीएससी परीक्षाओं की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से, हाल ही में एनईईटी जैसी कुछ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धोखाधड़ी के व्यापक आरोपों के बाद किया गया है। आयोग ने एक वास्तविक समय उपस्थिति निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव दिया है जिसमें यह पुष्टि करने के लिए जीपीएस निर्देशांक शामिल हैं कि नामांकन निर्दिष्ट पाली के भीतर होता है।

यूपीएससी निर्दिष्ट करता है कि एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड, जिसमें उम्मीदवार का रोल नंबर शामिल है, को एप्लिकेशन डेटाबेस से उम्मीदवार की जानकारी स्वचालित रूप से पुनर्प्राप्त करने के लिए स्कैन किया जाना चाहिए। यदि क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया जा सकता है, तो उम्मीदवार का रोल नंबर एडमिट कार्ड से मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। यूपीएससी देश भर में विभिन्न केंद्रों और स्थानों पर उम्मीदवारों और परीक्षा कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण क्षमताओं के साथ सीसीटीवी/वीडियो निगरानी लागू करने की भी योजना बना रहा है। सेवा प्रदाता को प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी रंगीन कैमरे स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिससे प्रत्येक 24 उम्मीदवारों के लिए कम से कम एक कैमरा सुनिश्चित किया जा सके। प्रवेश और निकास द्वारों और नियंत्रण कक्षों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे जहां परीक्षा से पहले और बाद की संवेदनशील सामग्री संभाली जाती है। यूपीएससी ने अपनी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से बोलियां मांगी हैं। यह कदम प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े विवाद के बाद उठाया गया है, जिन पर सीएसई में 12 बार उपस्थित होने के लिए जाली दस्तावेज रखने का आरोप है, जो प्रयासों की स्वीकृत संख्या से अधिक है। यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। यूपीएससी ने कहा, आयोग का इरादा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक विवरणों का मिलान और क्रॉस-चेक करने और परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी, अनुचित साधनों और प्रतिरूपण को रोकने के लिए उम्मीदवारों की विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीक का उपयोग करने का है।

यूपीएससी प्रतिरूपण को रोकने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत डेटा और छवियां सेवा प्रदाता को प्रदान करेगा। इस डेटा का उपयोग परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान प्रणालियों के लिए किया जाएगा। उम्मीदवारों की पहचान सटीक रूप से सत्यापित हो यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण तैनात किए जाएंगे। यूपीएससी भारत सरकार के भीतर समूह ए और समूह बी पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (शेष पेज 9)

उप्र पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान

- 23 से 25 अगस्त और 30 व 31 अगस्त को दो-दो पालियों में होगी लिखित परीक्षा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों में लगे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार द्वारा हाल ही में निरस्त की गई पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा अब 23,24,25 अगस्त एवं 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों की मांग पर यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यह परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के अनुसार पुन: आयोजित कराई जाए। प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं, जिनमें परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 जून 2024 को जारी किए गए है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार आयोजित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा निर्धारित तिथियों में आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। इन तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी तथा प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य (शेष पेज 9)

रील बनाने वालों पर दिल्ली मेट्रो का शिकंजा

- रील बनाने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर 1647 के खिलाफ केस दर्ज

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

शहर की लाइफ लाइन दिल्ली मेट्रो में रीलर्स पर लगाम कसनी शुरू हो गई है। इन्होंने ट्रेन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइक और व्यूज के लिए वीडियो बनाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अप्रैल से जून महीने के दौरान मेट्रो परिसर में रील बनाने सहित अन्य नियम उल्लंघन करने को लेकर 1,600 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले इस वर्ष मामलों की संख्या में तीन फीसदी की वृद्धि हुई है। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ रील बनाने को लेकर कितने लोग नामजद किए गए हैं, इसका कोई अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नियम उल्लंघन की दूसरी घटनाओं में ट्रेन के फर्श पर बैठना और ट्रेन के भीतर खाना खाने समेत अन्य अपराध शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत 1,647 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान यह संख्या 1,600 रही थी।

आंकड़ों के मुताबिक, डीएमआरसी ने अप्रैल, मई और जून में क्रमश 610, 518 और 519 मामले दर्ज किए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 528, 485 और 587 रही थी। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि इन लोगों पर मेट्रो परिसर में नियमों के उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, हम अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेट्रो परिसर में इस तरह की घटनाएं न हों। हमारे यहां दंड का प्रावधान है। अगर कोई मेट्रो परिसर में नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उसे दंडित कर सकते हैं। (शेष पेज 9)

राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप

- अशोक हॉल का भी नाम बदला अब कहलाएगा अशोक मंडप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल (बाएं) और अशोक हाल (दाएं), जिनका नाम अब बदल दिया गया है।

राष्ट्रपति के ऐतिहासिक निवास और कार्यस्थल राष्ट्रपति भवन के परिसर में प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' करने के एक साल बाद इस प्रतिष्ठित इमारत को एक गणतंत्र के रूप में भारत की स्थिति के साथ संरेखित करने और भारत में गहराई से निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के प्रयास जारी हैं। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक निवास और कार्यस्थल के दो ऐतिहासिक हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल को क्रमश: गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप नाम दिया गया है।

राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का प्रतीक और देश की एक अमूल्य धरोहर है। बयान में कहा गया, लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। इसमें कहा गया कि इसी क्रम में राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल - दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमश: गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रसन्नता है। राष्ट्रपति भवन के मध्य गुंबद के नीचे स्थित दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और कार्यक्रम के आयोजन का स्थान है। बयान में कहा गया, दरबार शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश अदालतों तथा सभाओं को संदर्भित करता है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद दरबार की प्रासंगिकता खत्म गई। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है। गणतंत्र मंडप आयोजन स्थल के लिए एक उपयुक्त नाम है। (शेष पेज 9)

343 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी यूपी एसएसएफ द्वितीय वाहिनी की हाईटेक बिल्डिंग

● गोरखपुर के ताल जहदा में 50 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी वाहिनी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

खास स्थानों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) की द्वितीय वाहिनी गोरखपुर में है। अभी यह वाहिनी अपना कामकाज पीएसी कैम्पस से कर रही है लेकिन आने वाले समय में इसकी खुद की हाईटेक बिल्डिंग होगी। शासन की तरफ से यूपी एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के अत्याधुनिक और सभी सुविधाओं से युक्त भवन के लिए करीब 343 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह बिल्डिंग गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र स्थित ताल जहदा में 50.136 हेक्टेयर भूमि पर बनेगी। इसके लिए प्रक्रियात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बरसात का सीजन समाप्त होते ही इसका निर्माण शुरू हो जएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर, 2020 में न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया था। जिसके बाद जून, 2021 में यूपी एसएसएफ की पांच वाहिनी गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर शामिल हैं। इसके बाद छठवीं वाहिनी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए गठित की गई। गोरखपुर के लिए गठित एसएसएफ की द्वितीय वाहिनी गोरखपुर और कुशीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रही है। जल्द ही इसके जिम्मे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी आएंगे। यूपी एसएसएफ के गठन के बाद से ही योगी सरकार इसे सूबे की सबसे एडवांस फोर्स बनाने में जुटी है। इस फोर्स को अत्याधुनिक असलहों से लैस करने के साथ ही इसकी बटालियन के लिए हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए करीब 343 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। गोरखपुर में यूपी एसएसएफ की द्वितीय वाहिनी के आवासीय भवनों के लिए योगी सरकार ने 186 करोड़ 33 लाख 43 हजार रुपये तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 156 करोड़ 39 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। कार्यदायी संस्था के रूप निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड (भवन) को दी गई है। कार्यदायी संस्था की तरफ से निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड (भवन) के अधिशासी अभियंता अर्जुन मित्रा का कहना है कि बरसात के बाद निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू करा दिया जाएगा।

ताल जहदा में यूपी एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के परिसर में लिफ्ट युक्त टाइप ए, बी और टाइप फोर व फाइव के बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा लिफ्ट युक्त प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड, पार्किंग, संतरी पोस्ट, अस्पताल, इंडोर जिम, डॉग कैनेल, टॉयलेट ब्लॉक और 400 की क्षमता का बैरक बनाया जाएगा। यहां सलामी मंच के साथ भव्य परेड ग्राउंड का विकास भी होगा। सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ इसके परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम होगा।

परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिएः मुख्य सचिव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह एवं पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों , जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षाओं को नकलविहीन, पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने स्तर से इन सभी परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा और परीक्षार्थियों के बैठने के लिये फर्नीचर एवं पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जांच करायें, कोई अव्यवस्था होने पर संबंधित केन्द्र के प्रमुख से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें।

उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पूरी सतर्कता बरती जाए। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा भ्रमणशील रहकर विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये। सभी जिलाधिकारियों से कहा कि ईवीएम मशीनों की भांति परीक्षा प्रश्न पत्रों की निगरानी व सुरक्षा सुनिश्चित करायें।

पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कड़ी सुरक्षा में पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न होनी चाहिए। परीक्षा में नकल माफिया सक्रिय न हो, इस पर विशेष तौर पर नजर रखी जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी नाम के स्थान पर पदनाम से लगाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड डीजी राजीव कृष्ण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यात्रियों की शिकायत का विवरण प्रतिदिन मुख्यालय कराए उपलब्धः परिवहन मंत्री

● 10 हजार परिचालकों की जल्द भर्ती के दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने परिचालकों की कमी के दृष्टिगत 10 हजार परिचालकों की जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिचालकों की कमी से परिवहन निगम की बहुत सी बसें आफरूट हो रही है, इससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने के निर्देश भी दिये।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी की बसें लोगों को मुहैया हो सके, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य करने की जरूरत है। वर्कशाप में बसों की अच्छी ढंग से मरम्मत कार्य किया जाए, जिससे कि बसों की छत टपकने की समस्या दूर हो सके। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते समय लोगों को सुखद एवं आरामदायक यात्रा की अनुभूति हो सके। इसके लिए बसों की सीटें, शीशे इत्यादि बेहतर कंडीशन में हो। उन्होंने आनलाइन बुकिंग की व्यवस्था पर और बेहतर करने पर जोर दिया। साथ ही चालक/परिचालक वर्दी में हो, नेम प्लेट लगा होना चाहिए। बस स्टेशनों एवं डिपो पर एक हेल्पलाइन नम्बर की व्यवस्था की जाए, जिसपर यात्री किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकें। परिवहन मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्रों में संचालित बसों की लोड फैक्टर, फ्यूल एवरेज एवं आय की समीक्षा की। उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद, चित्रकूट एवं बरेली के प्रबंधकों को बेहतर कार्य एवं प्रदर्शन के लिए बधाई दी। जबकि मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों को खराब प्रदर्शन करने पर चेतावनी दी और कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिये। अलीगढ़, आजमगढ़, झांसी, मेरठ एवं देवीपाटन के क्षेत्रीय प्रबंधकों को उनके यहां अनुपयोगी बसों की संख्या ज्यादा पाये जाने पर चेतावनी दी। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने एवं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधकों को यात्रियों की शिकायतों का विवरण प्रतिदिन मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। परिवहन मंत्री ने उत्तराखंड एवं उप्र के निगम बसों के पार्किंग फीस में अंतर को समाप्त करने के निर्देश दिये। उत्तराखंड परिवहन निगम अपने यहां पार्किंग फीस 550 रुपए रखा है जबकि उप्र परिवहन निगम अपने यहां पार्किंग फीस मात्र 220 रुपए रखा है। इससे परिवहन निगम की बसों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने टिकट/डीजल चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैमरों के माध्यम से मॉनीटरिंग किया जाए। परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित ढांबों पर साफ-सफाई बेहतर रखें एवं शौचालय की व्यवस्था उत्तम रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो भी अनुबंधित ढ़ाबा उक्त व्यवस्थाओं को पूरा करने में विफल रहता है उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाए।

ग्रेटर नोएडा में होगी 'सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी' बेस्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना

● 79.57 करोड़ रुपए की लागत से होगा ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू की तैयारियां

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश की प्रगति व उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर उसे उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में विकास को गति देने के लिए दो प्रमुख योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना व संचालन के साथ ही गंगा जल प्रोजेक्ट से संबंधित परियोजनाओं को गति देने का कार्य शुरू हो गया है।

सीएम योगी के विजन अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 में में सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना निर्धारित है। 79.57 करोड़ की लागत से बनने वाले 45 एमएलडी कैपेसिटी युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व वॉटर रीक्लेमशन फैसिलिटी की स्थापना, संचालन व टेस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार, 85 क्यूसेक कैपेसिटी वाले गंगा जल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 जोनल रिजरवॉयर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व अन्य सिविल वर्क्स को जल्द पूरा करने के लिए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस कार्य में कुल मिलाकर 11.44 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इन दोनों ही कार्यों को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से प्रक्रिया शुरू हो गई है और सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के समेकित विकास के लिए सीएम योगी के विजन में तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 में 79.57 करोड़ रुपए की लागत से सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) टेक्नोलॉजी युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का विकास किया जाएगा। यह 45 एमएलडी कैपेसिटी वाला एसटीपी होगा जिसे एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन के बाद 15 महीनों में पूरा किया जाएगा। वहीं, ऑपरेशन व मैनेजमेंट के लिए 120 महीनों की कार्यावधि निर्धारित की गई है। इस प्लांट के निर्माण को लेकर पहले एजेंसी द्वारा साइट एनवॉयरमेंट प्लान (एसईपी) तैयार किया जाएगा। सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न मानकों का ध्यान रखा जाएगा जिसमें वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के स्तर को भी मॉनिटर करते हुए कम से कम रखा जाएगा। यह ट्रीटमेंट प्लांट वॉटर रीक्लेमेशन फैसिलिटी भी होगा। प्लांट के संचालन के लिए 3 महीने का ट्रायल पीरियड भी निर्धारित किया गया है जिसमें इसके संचालन के विभिन्न मानकों को मॉनिटर करते हुए क्रियान्वित किया जाएगा। इस दौरान, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की समयावधि 12 महीने निर्धारित की गई है। प्लांट का डिस्पोजल चैनल हिंडन नदी के किनारे स्थित होगा। प्लांट को सौर ऊर्जा युक्त भी किया जाएगा और इसके हाइड्रोलिक पंपों का संचालन सौर ऊर्जा के जरिए किए जाने की योजना है।

प्लांट में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीवरेज आउटकम को गहरे गुरुत्वाकर्षण आउटफॉल सीवर द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जो रॉ सीवेज को एक रिसीविंग चैंबर में डिस्चार्ज करेगा, जहां से इसे डाउनस्ट्रीम मोटे स्क्रीन में ले जाया जाएगा। सीवेज के साथ आने वाली सामग्रियों को हटाने के लिए उसे गीले कुएं के ऊपर मोटे स्क्रीन चैनल में छाना जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद सीवेज वेट वेल में प्रवेश करेगा। प्लांट वेट वेल युक्त होगा जिसकी क्षमता औसत और पीक फ्लो स्थितियों के दौरान पर्याप्त हाइड्रोलिक प्रतिधारण करने की होगी।

व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठों को बनाया जाए और अधिक प्रभावी

● डीजीपी ने व्यापारियों व उद्यमियों से सम्मानजनक शिष्टतापूर्ण व सहयोगात्मक व्यवहार करने के पुलिस कर्मियों को दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों में गठित व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठों को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में व्यापारियों, उद्यमियों, निर्यातकों की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए शासन के निर्देश पर समस्त कमिश्नरेट और जिलों में अपर पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीजीपी ने निर्देशित किया है कि व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण तथा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह नियमित बैठकें आयोजित कराकर समस्याओं एवं शिकायतों को पूर्णत: गम्भीरता से लेकर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ सम्मानजनक, शिष्टतापूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। सर्राफा व्यापारियों, अन्य व्यापारियों/ उद्यमियों के आवागमन के दौरान उनके संगठन द्वारा निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड/ परिचय-पत्र एवं सम्बन्धित कागजात दिखाये जाने हेतु उनके साथ परिमार्जित ढंग से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय। परिचय-पत्र एवं सम्बन्धित कागजात सही पाये जाने पर उन्हें कदापि प्रताड़ित न किया जाए। सर्राफा व्यापारियों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए तथा मुख्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यस्त बाजारों तथा सर्राफा मार्केट आदि स्थलों पर समुचित एवं पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाए तथा पुलिस पेट्रोलिंग भी कराई जाए। समय-समय पर थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे स्थानों पर लगाए गए पुलिस बल की चेकिंग कर उन्हें अपनी ड्यूटी पर सदैव सतर्क रहने के लिए ब्रीफ किया जाए।

मसालों की खुशबू से महकेगी बुद्ध के महापरिनिर्वाण की धरा

● कुशीनगर में हल्दी के साथ ही अब जीरा, सौंफ, मंगरैल, धनिया और अजवाइन की खेती का बढ़ेगा दायरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ कुशीनगर

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की धरती। कभी इसी धरती से सत्य और अहिंसा के संदेश से दुनिया का बड़ा हिस्सा आलोकित हुआ था। अब उसी धरती से उपजे मसालों की खुशबू शुरू में स्थानीय और बाद में देश-दुनिया में रहने वाले हर भारतीय के किचन के भोजन की लज्जत बढ़ाएंगे। इसमें वर्षों से कुशीनगर में होने वाली हल्दी की खेती का योगदान तो होगा ही, धनिया जीरा, सौंफ, मंगरैल, सौंफ और अजवाइन की खेती इसका दायरा बढ़ाएंगे। इस बावत डबल इंजन (मोदी और योगी) की सरकार पहल भी कर चुकी है।

राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर की मदद से इस साल रबी की फसलीय सीजन में सीमित संख्या में कुछ किसानों के खेतों में मसाले की कुछ प्रजातियों की खेती शुरू होगी। कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर के प्रभारी अशोक राय के अनुसार कुशीनगर में हल्दी की खेती की परंपरा पुरानी है। कुशीनगर और आसपास की जलवायु बीजीय मसालों के लिए भी अनुकूल है। इसलिए यहां इसकी अच्छी संभावना है। यहां के किसान भी जागरूक हैं। इसलिए अपेक्षाकृत अधिक लाभ वाले मसालों की खेती की संभावना और बेहतर हो जाती है।

किसानों के बीच टाटा ट्रस्ट और अजीमजी प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से कई वर्षों से हल्दी की खेती पर फोकस होकर काम करने वाले सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के बीएम त्रिपाठी मसालों की खेती के लिए भी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अनुसंधान केंद्र का भी मेथी, सौंफ, जीरा और अजवाइन के फ्लेवर और औषधीय गुणों के कारण इनके प्रसंस्करण पर खासा जोर है। इनको मिलेट के साथ मिलाकर और पौष्टिक बनाया जा सकता है। कालांतर में कुशीनगर के किसानों को भी अगर मसाले की खेती रास आई तो उनके लिए भी ये सारी संभावनाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हित के प्रति जिस तरह प्रतिबद्ध हैं उसमें कोई एफपीओ खेती से लेकर प्रसंस्करण इकाई लगाने और मार्केटिंग की अगुआई कर सकता है। योगी सरकार की यही मंशा भी है। भारत को मसालों की धरती भी कहा जाता है। पुर्तगाली जब पहली बार भारत आए तो उनका मूल उद्देश्य भारतीय मसालों के कारोबार से कमाई करना ही था। भारत में करीब 18 लाख हेक्टेयर जमीन पर मसालों की खेती होती है। जीरा गुजरात और राजस्थान की मुख्य फसल है तो बाकी तमाम मसाले अधिकांशत: दक्षिण भारत में होते हैं। मसाले भारतीय भोजन की जान होते हैं। देश दुनिया में जहां भी भारतीय हैं वहां बिना मसाले के उनके किचन की कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ती बीमारियों और औषधीय खूबियों के कारण मसालों का क्रेज और बढ़ा है। खासकर कोविड के बाद तो और भी। इसलिए इसकी खेती की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन संभावनाओं को आने वाले समय में और चार चांद लगाएगा।

50 फीसदी से अधिक राजस्व वृद्धि करने वाले नगर निगमों को मिलेगा 100 करोड़ तक का अनुदान

● पंचवर्षीय विजन प्लान के तहत तैयार होगी वार्षिक कार्ययोजना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में नगरों के सर्वांगीण विकास और नगरीय स्थानीय निकायों के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नगर विकास विभाग ने राज्य की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य मिशनों को 'मिशन टू मूवमेंट' के रूप में विस्तारित कर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत नगर निगमों में न्यूनतम 25 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले नगर निगमों को न्यूनतम 2.5 करोड़ और अधिकतम 50 करोड़, नगर पालिका परिषदों व जिला मुख्यालयों (एक लाख से अधिक जनसंख्या) में न्यूनतम 15 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले निकायों को न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 20 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद व जिला मुख्यालय (एक लाख से कम जनसंख्या) व नगर पंचायतों में न्यूनतम 10 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले निकायों को न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व वृद्धि करने, नवोन्मेषी परियोजनाएं, राजस्व उत्पादक परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए प्रति नगर निगम अधिकतम 100 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी एसओपी में इसका प्राविधान किया गया है। योजना के तहत, सेल्फ रेवेन्यू कलेक्शन को आधार वर्ष 2022-23 की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाएगा, जो पात्रता मानदंड होगा। यह योजना 2024-25 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। 2024-25 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के समस्त 762 नगरीय स्थानीय निकायों को आच्छादित किया जाएगा। यह योजना राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सतत आर्थिक वृद्धि, समानता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए 3ई दृष्टिकोण अपनाएगी। योजना के प्रयोजन के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के प्रकार, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-1 में नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या), श्रेणी-2 में नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय (1 लाख से अधिक जनसंख्या) और श्रेणी-3 में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें और जिला मुख्यालय (1 लाख से कम जनसंख्या) को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के तहत विभिन्न परियोजनाएं अनुमन्य की गई हैं।

योजना के लिए उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए आवंटित संरचना श्रेणी-1 के लिए आवंटन का 40 प्रतिशत, श्रेणी-2 के लिए कुल आवंटन का 40 प्रतिशत एवं श्रेणी-3 के लिए कुल आवंटन का 20 प्रतिशत तक आरक्षित किया गया है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए अनुमोदित बजट आवंटन की धनराशि में मंत्री नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

पायनियर वर्गीकृत

बेदखली सूचना

मैं वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गोकरन सिंह निवासी खदरा, मडियॉव लखनऊ, वर्तमान निवास भदौरिया टिम्बर, अस्ती रोड़, बीकेटी,लखनऊ। अपने पुत्र आलोक सिंह भदौरिया व पुत्रवधु नीलम सिंह को उनके गलत हरकत एवं खराब व्यवहार के चलते अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ, भविष्य में इनके कोई भी कृत्यों से मेरा व मेरी पत्नी का कोई सरोकार नही होगा। वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गोकरन सिंह

सूचना

मैं कमला प्रसाद पुत्र स्व० नायक राम निवासी म०न० 775 रक्षा खण्ड, उद्यान II आर्शीवाद, सेक्टर 3 रायबरेली रोड, लखनऊ मेरे पुत्र शैलेश प्रताप भास्कर के नाम से प्लाट नं०-D-284 डीएलएफ गार्डेन सिटी, पुरसेनी लखनऊ मे है । मेरे पुत्र का निधन - 19-05-२०२० को हो गया है। उक्त प्लाट न० D-284 डीएलएफ का उत्तराधिकारी कमला प्रसाद तथा मेरी पत्नी रमावती देवी हैं। उपरा. उक्त सम्पति के बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आज से 21 दिन के अन्दर आपत्ति दे सकता है।
कमला प्रसाद
फोन न.-9838545126

घुप अंधेरा, तेज बहाव, 40 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन और 4 को मिली नई जिंदगी

● संकट की घड़ी में साथी बन कुशीनगर जिला प्रशासन के देवदूतों ने बड़ी गंडक नदी के तेज बहाव में फंसे चार लोगों की बचाई जान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ कुशीनगर

बुधवार देर रात कुशीनगर जिला प्रशासन ने खड्डा तहसील की बड़ी गंडक नदी में अचानक बढ़े हुए जलप्रवाह के बीच फंसे चार लोगों को अदम्य साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू किया। टीम ने देर रात घुप अंधेरे और तेज बहाव के बीच महज कुछ मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए सभी को सुरक्षित बचा लिया। इस पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन की काफी तारीफ की। बता दें कि वर्ष 2003 में यहां पर तेज बहाव की वजह से 16 लोगों की जान चली गयी थी। राहत आयुक्त जीएस नवीन के मुताबिक बुधवार रात आठ बजे कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि खड्डा तहसील के एसडीएम ऋषभ पुंडीर और एडीएम एफआर वैभव मिश्रा ने बड़ी गंडक नदी में अचानक तेज बहाव की वजह से एक नाव पलटने की सूचना दी। इस हादसे में चार लोग पुनियावन पुल के पास तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन की परमीशन मांगी। इस पर तत्काल परमीशन देते हुए एसडीआरएफ के कमांडेंट को रेस्क्यू का आदेश दिया। एडीएम एफआर वैभव मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन की परमीशन मिलते ही एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। एडीएम एफआर ने बताया कि घुप अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाने में असमर्थता जतायी। इसपर तत्काल प्रकाश की व्यवस्था कराई गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। एडीएम एफआर वैभव मिश्रा, एसडीएम खड्डा ऋषभ पुंडीर और एसडीआरएफ की टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते में हुए कड़ी मशक्कत के बाद महज 40 मिनट में पानी के तेज बहाव में फंसे चारो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया। वहीं डॉक्टर्स के क्लीयरेंस के बाद सभी को गाड़ी से उनके घर पहुंचाया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि बड़ी गंडक नदी के तेज बहाव में फंसे चारो लोग बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि चारो लोग देर रात नदी में मछली पकड़ने गये थे। इस दौरान अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और नाव पलट गयी।

वहीं नदी में तेज बहाव होने की वजह से वह बहते हुए पुनियाहवा पुल के पास फंस गये। ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर एसडीएम खड्डा ऋषभ ने एडीएम एफआर वैभव मिश्रा को रात 8 बजे जानकारी दी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और 40 मिनट में सफलतापूर्वक सभी को सुरक्षित बचा लिया गया।

राज्यसभा में उठी लखनऊ विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग

● प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा ने उठाई सभापति के समक्ष मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के पुरातन विश्वविद्यालय में शामिल लखनऊ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग एक बार फिर उठी है। हालांकि यह मुद्दा काफी पुराना है और शिक्षक संघ कई बार इसे उठा चुका है। लेकिन इस बार विवि को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा ने राज्यसभा में उठाया है। गुरुवार को राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह के समक्ष एलयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि यह प्रदेश के पुरातन विश्वविद्यालय में शामिल है। यहां पर कई देशों के छात्र आकर अध्ययन करते हैं। साथ ही इस विवि ने कई नामचीन हस्तियों को दिया है। जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. शंकर दयाल शर्मा से लेकर कई लोगों के नाम शामिल है। इस विवि ने देश को कई राजनेता, शिक्षाविद् और साइंटिस्ट दिये हैं। इसके साथ ही यहां से पढ़कर निकले छात्र कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतना ही विवि का विस्तार कई जिलों में होने से यहां पर लाखों छात्र अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही विवि ने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की है। ऐसे में विवि को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए।

शिक्षक संघ ने की सराहना

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं राज्य सभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा के द्वारा आज संसद में 103 वर्ष पुराने लखनऊ विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की माँग को राज्यसभा में उठाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यह वर्षों से माँग कर रहा है। इस माँग को दिनेश शर्मा द्वारा राज्यसभा में जिस तरह से उठाया गया उसके लिए शिक्षक संघ उनकी केवल सराहना करने के साथ ही उनका आभार भी व्यक्त करता है।

डॉ अनित्य गौरव
महामंत्री
लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ

मंडलायुक्त ने किया आलमबाग क्षेत्र का भ्रमण गंदगी पर जेडएसओ को लगाई कड़ी फटकार

● आशा कार्यकत्री, ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जनपद में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के तहत मंडलायुक्त द्व ारा आलमबाग क्षेत्र का भ्रमण किया गया। मंडलायुक्त द्वारा वार्ड गौतमपल्ली में नालियां चोक और गंदी पाए जाने पर जेडएसओ और जोनल अधिकारी से कड़ी नाराजगी जताई गयी। उल्टी, दस्त बीमारी न फैले इसके लिए जेडएसओ को फटकार लगाते हुए सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

जनपद में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने में मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब निकली फील्ड पर, सर्वप्रथम उन्होंने गीतापल्ली आलमबाग पहुँच कर दस्तक अभियान ने किये जा रहे कार्यों की जानकारी लिया। गीता पल्ली वार्ड में निरीक्षण के दौरान उपस्थित आम जनमानस से वार्ता करके उनकी समस्या को गहनता पूर्वक सुनने के उपरांत तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नालियों में जमें शिल्ट तत्काल साफ कराते हुए नियमित रूप से फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे। टूटे.फूटे नालियों की मरम्मत तत्काल करा लिया जाए। खुले में कूड़ा डंप ना होने पाये साथ ही कूड़े शिफ्टिंग का कार्य ससमय कराते रहे। वार्ड 54 आजाद नगर में नालिया चौक व नालियों में गंदगी मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी नंदकिशोर एवं जेएड एसओ राजेश को लगाई कड़ी फटकार और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य मे लापरवाही व शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आशा कार्यकत्री, ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करते रहे।

5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का दें घोल

मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें नि:शुल्क जाँच एवं उपचार और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छह माह से पाँच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाना है।

आस पास पानी जमा न होने दें

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की बरसात का मौसम संचारी रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, कुछ सावधानियां बरतकर इन रोगों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि साफ सफाई रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने को कहें। घर के आस पास पानी जमा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जानकारियां डोर टू डोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए।

यूपीटीएसी काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर एलयू में होंगे सीधे दाखिले

● 24 अगस्त तक डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कार्यालय में जमा करना होगा फॉर्म

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 के तहत बीटेक, बीफार्मा और एमसीए में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। इसी तरह बीटेक व एमसीए लेट्रल इंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में भी सीधे एडमिशन लिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग (यूपीटीएसी) 2024 से रिक्त रहने वाली सीटों पर विवि अपने स्तर से दाखिले लेगा। इस संबंध में विवि की आधिकारिक वेबसाइट के एडमिशन पेज पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। जहां से अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद विवि वित्त नियंत्रक के नाम पर 500 रूपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा। जिसे आवेदन पत्र के साथ 24 अगस्त तक अधिष्ठाता अभियांत्रिकीय व तकनीकी संकाय के कार्यालय में जमा कर सकेंगे। विवि के प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जेईई 2024, सीयूईटी यूजी या पीजी में कोई परीक्षा पास होने चाहिए। उनका कहना है कि 24 अगस्त तक रिक्त सीटों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद विवि की ओर से मेरिट सूची जारी की जाएगी। जिसके अनुसार प्रवेश होंगे। एलयू में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई स्ट्रीम में बीटेक कार्यक्रम संचालित है। बीटेक में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 12वीं पास होना अनिवार्य है। एमसीए में एडमिशन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी की डिग्री होना जरूरी है। जबकि बीफार्मा में प्रवेश के लिए साइंस ग्रुप से 12वीं परीक्षा पास होना चाहिए।

पाठ्यक्रमों की प्रति सेमेस्टर फीस

- बीटेक- 60,130 रूपये
- एमसीए- 56,130 रूपये
- बीफार्मा- 60,130 रूपये

(नोट- प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले छात्रों को पंजीकरण शुल्क 1000 रूपये और कॉशन मनी 5000 रूपये भी जमा करना होगा।)

एनएचएम कर्मियों को मिलेगा बीमा का लाभ, आदेश जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को अब बीमा लाभ मिलेगा। एनएचएम प्रशासन ने बीती मार्च से कर्मचारियों को बीमा लाभ का आदेश जारी कर दिया है। एनएचएम की ओर से जारी आदेश को लेकर कर्मचारी खुश हैं।

सरकारी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, वेलनेस सेंटर आदि में ड्यूटी कर रहे हैं। एनएचएम मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना का लाभ 27 मार्च 2024 से मिलेगा। योजना का उद्देश्य एनएचएम के तहत राज्य, मंडल व जनपद स्तर पर कार्यरत संविदाकर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में परिवार की मदद के लिए बीमा कवर देना है। बीमा की धनराशि एनएचएम की ओर से जमा की जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु पर 30 लाख का ग्रुप टर्म बीमा योजना (मृत्यु लाभ) मिलेगा। एनएचएम की ओर से प्रदेश भर के कर्मचारियों को बीमा देने के आदेश के साथ प्रोफार्मा दिया जा रहा है। इस प्रोफार्मा पर संविदा स्टाफ के योगदान का विवरण देना होगा कि कर्मचारी कब, कहां और किस पद पर काम कर रहा है। प्रोफार्मा के मुताबिक ब्योरा देना होगा। जिसे मंडल का अपर निदेशक या सीएमओ सत्यापित करेगा। साथ ही ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रोफार्मा को भी कर्मचारी को खुद ही भरकर, फोटो आदि लगाकर भरना होगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उप्र. के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि फरवरी में 12 हजार एनएचएम कर्मचारियों ने बीमा समेत अन्य मांगों के लिए मुख्यमंत्री को अभियान के तहत पत्राचार कर हजारों पत्र भेजे गये थे।

स्वास्थ्य विभाग में नए पद उपकरणों की होगी स्थापना

● डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश, नवनिर्मित चिकित्सालयों के लिए वित्तीय स्वीकृति

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

स्वास्थ्य विभाग को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। नवनिर्मित चिकित्सालयों में नवीन पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही नए उपकरणों को भी स्थापित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आमजन को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नवनिर्मित 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, विजय नगर (डूडूहेडा) गाजियाबाद, 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, बांसगांव, गोरखपुर, 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, बांसी, सिद्धार्थनगर को क्रियाशील किए जाने हेतु प्रत्येक अस्पताल में 38 पदों के हिसाब से कुल 174 पदों एवं लखनऊ के नवनिर्मित 50 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग गोसाईंगंज एवं काकोरी की स्थापना हेतु प्रति अस्पताल 42 पदों के हिसाब से कुल 84 पदों को सृजित किए जाने का अनुमोदन किया गया है। वहीं, लखनऊ स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में विभिन्न विभागों में आधुनिक उपकरण एवं संयत्र स्थापित किए जाने हेतु 150 करोड़ एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आधुनिक उपकरण एवं संयत्रों को स्थापित किए जाने हेतु 1.99 करोड़ रुपये एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में आधुनिक उपकरण एवं संयत्रो को स्थापित किए जाने हेतु दो करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

लापरवाही में चिकित्सकों पर गिरी गाज, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग में लगातार कार्रवाई जारी है। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही एवं प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामले में वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र में तैनात डॉ. माधुरी सिंह की वेतनवृद्धि रोकते हुए परिनिंदा प्रविष्टि प्रदान की गई है। वहीं, गोरखपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पिपरौली में तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. नीतू कुमारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कौड़िया में तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष कुमार चौरसिया द्वारा रोगियों से अभद्र व्यवहार करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना करने एवं ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में विभागीय अनुशासनिक जांच के आदेश जारी किए गए हैं। उधर, डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में तैनात आपातकालीन चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक चतुर्वेदी पर गलत तरीके से मेडिकोलीगन किए जाने का मामला संज्ञान में आने पर डॉ. चतुर्वेदी को तत्काल आरोप पत्र दिए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को दिए गए हैं।

केंद्रीय टीम के औचक निरीक्षण में फिट मिलीं प्रदेश की स्वास्थ्य इकाइयां

● अब तक 281 स्वास्थ्य इकाइयों को मिल चुका है एनक्वास

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

हाल ही में प्रदेश की जिन स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्वास) प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वह बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। हाल ही में झांसी जिला अस्पताल के हुए औचक निरीक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है। वहां पर ओपीडी, मातृत्व वार्ड, लैब, सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) मानक के अनुरूप काम करते मिले हैं।

प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य इकाइयों को केंद्र सरकार द्वारा एनक्वास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि केंद्र सरकार एनक्वास प्राप्त हर प्रदेश की 10 प्रतिशत स्वास्थ्य इकाइयों का हर साल इस उद्देश्य से औचक निरीक्षण करती है कि इस सर्टिफिकेट पाने के बाद वहां मानकों के अनुरूप मरीजों का इलाज हो रहा है या नहीं। इसमें केंद्रीय टीम निरीक्षण करती है और स्वास्थ्य इकाई को 72 घंटे पहले ही निरीक्षण की सूचना दी जाती है। झांसी जिला अस्पताल प्रशासन को भी 72 घंटे पहले ही सूचना दी गई और केंद्रीय टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एनक्वास प्रमाणित स्वास्थ्य इकाई में जो मानक होने चाहिए वह सब झांसी जिला अस्पताल में फालो हो रहे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉ. निशांत कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य इकाइयों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। अब तक 281 स्वास्थ्य इकाइयों को एनक्वास मिल चुका है।

पांच और आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एनक्वास मिला

महाप्रबंधक डॉ. जायसवाल ने बताया कि हाल ही में पांच और आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एनक्वास प्रमाण पत्र मिला है। इसमें लखनऊ का छितवापुर, संत रवीदास नगर का पिपरगऊ और वाराणसी के कोरौताई व थाथारा, अमीनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं। इनको मिलाकर प्रदेश में अब तक 281 स्वास्थ्य इकाइयां एनक्वास प्रमाणित हो गई हैं।

यूथ फार्मेसिस्ट फेडरेशन का रक्तदान शिविर 27 जुलाई को लोकबंधु में

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

रक्त का कोई विकल्प नहीं, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान कर किसी न किसी की जान बचाने में अपना योगदान देना ही चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर फार्मासिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का यूथ विंग 27 जुलाई को लोक बंधु चिकित्सालय कानपुर रोड के रक्त कोष में 11 बजे से एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कृष्ण, सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि यूथ फेडरेशन के संरक्षक उपेंद्र का जन्मदिन भी 27 जुलाई को है । फार्मासिस्ट फेडरेशन लगातार आम जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारियां उपलब्ध कराता रहा है तथा रक्तदान सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमो के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास करता रहा है । फेडरेशन का यह मानना है कि यदि चिकित्सक, फार्मेसिस्ट सहित चिकित्सा जगत के सभी लोग स्वयं रक्तदान के लिए आगे आएंगे तो आम जनता में रक्तदान के प्रति फैले हुए भ्रम को दूर कर रक्तदान के लिए जागरूकता पैदा किया जा सकता है। फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस महादान के लिए युवाओं के आगे आने से जनता को नवजीवन देने में फार्मेसिस्ट का योगदान अब और बढ़ जायेगा।

इनोवेशन स्टार्टअप की आत्मा के समान

● यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से स्टार्टअप मूल्यांकन रूपरेखा कार्यशाला का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में गुरूवार को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट और आईटी एंड इलेक्ट्रानिक्स एवं इनोवेशन हब की ओर से स्टार्टअप मूल्यांकन रूपरेखा कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न स्तरों पर स्टार्टअप के मूल्यांकन की रूपरेखा तय करने पर मंथन हुआ। जिससे की रिफाइन होकर स्टार्टअप आगे आ सके। ताकि उनके सफल होने के ज्यादा संभावनाएं रहेंगी।

कार्यशाला में विशेष सचिव यूपीएलसी राहुल सिंह ने कहा कि प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्टार्टअप इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टार्टअप की आत्मा इनोवेशन होता है। इनोवेशन के जरिये स्टार्टअप को सफल बनाया जा सकता है। स्टार्टअप के मूल्यांकन की रूपरेखा तय किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। यूपीडेस्को की एमडी नेहा जैन ने वेस्ट मैनेजमेंट में स्टार्टअप्स को कार्य करने का सुझाव दिया। डीन इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रो बीएन मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में पूरी दुनिया स्टार्टअप इको सिस्टम के जरिये प्रगतिशील बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने भी अब इस बारे में तेजी से कदम बढ़ाये हैं। हमारा प्रदेश स्टार्टअप इको सिस्टम को लेकर लगातार प्रयास और प्रतिबद्धता दिखा रहा है। स्टार्टअप को सहयोग देने के साथ ही फंड से लेकर अन्य तरह की सुविधाएं दी जा रही है। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे के निर्देशन में विश्वविद्यालय की ओर से स्टार्टअप को लेकर किये जा रहे प्रयास पर भी प्रकाश डाला। कहा कि स्टार्टअप के मूल्यांकन की रूपरेखा पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। वेंचर फंड के कैलाशनाथ और सार्थक विश्वास ने स्टार्टअप मूल्यांकन की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं अपने उत्पादों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाली दो कंपनियों की केस स्टडी पर चर्चा की। इस मौके पर यूपीएलसी के जॉइन्ट मैनेजर विष्णु मोहन, इनोवेशन हब के हेड महीप सिंह, मैनेजर वंदना शर्मा सहित स्टार्टअप, इन्क्युबेशन मैनेजर्स मौजूद रहे।

डीएम की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर बैठक

डीएम ने दिए ऐतिहासिक इमारतों की सजावट, चौराहों एवं पार्कों में सफाई कराने के निर्देश

पायनियर समाचारसेवा। लखनऊ

आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी का सभी विभागीय अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के पर्व को आयोजित करने तैयारी 5 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। डीएम द्वारा ऐतिहासिक इमारतों की सजावट, चौराहों एवं पार्कों में सफाई कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों में निबन्ध, खेलकूद वाद विवाद प्रतियोगिता कराने के लिए भी कहा गया है।

गुरुवार को आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस को होने वाले समारोह को परम्परागत, भव्य एवं गरिमामय मनाने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से सम्बन्धित नोडल अधिकारी सभी तैयारियों से सम्बन्धित जानकारी 5 अगस्त तक अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी को उपलब्ध करायें तथा आयोजनो की बैठक भी कर लें। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की महत्ता से सभी व्यक्ति परिचित है इस लिए हम सबका दायित्व है कि व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर बेहतर ढंग से इसका आयोजन किया जाये। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह .2024 के अवसर पर सभी विभाग अपनी.अपनी जिम्मेदारी के साथ तैयारियां पूरी करें। उत्साह जनक और शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ 15 अगस्त का यह राष्ट्रीय पर्व मनाए। कार्यक्रम को भव्य रूप बनाने में सभी अपनी.अपनी सहभागिता निभाएं। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी विभागों को निर्देशित किया कि दिए गए दायित्वों को जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करें। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वार्डो में आयोजित होने वाली प्रभात फेरियों में नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डेन ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करायें। उन्होने ऐतिहासिक ईमारतों की साफ सफ ाई एवं सजावट, चौराहों एवं पार्कों में सफ ाई एवं सजावट चैराहो में स्थापित मूर्तियों की सफ ाई विद्यालयों में निबन्ध, खेलकूद वाद विवाद प्रतियोगिताए आदि का आयोजन पूरी तैयारी एवं भव्यता के साथ विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें।

उन्होने कहा कि विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता आपसी सद्भाव, एवं राष्ट्रीय विचारधारा को बढावा देने विषयक नाटक, निबन्ध, गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाए। उन्होने कहा कि गत वर्षो से अधिक भव्य एवं उत्कृष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये ताकि राष्ट्रीय पर्व की गरिमा व महत्व की जानकारी जन.जन तक पहुंचे और राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की भावना में वृद्धि हो। उन्होने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक के पास गांधी भवन मे सायं 5 बजे से 06:30 बजे तक शहीदों के प्रति सर्वधर्म प्रार्थना सभा और 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जायेगा एवं पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 के समस्त आयोजन भव्य एवं आकर्षक किये जाये और यदि किसी कार्य में कठिनाई परिलक्षित हो तो अवगत करायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार, नगर मजिस्ट्रेट सद्धार्थ, सभी उप जिलाधिकारीए सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट, नगर निगम, एलडीए, नागरिक सुरक्षा संगठन, शिक्षा, जल संस्थान, एसएसएबी, सीआरपीएफ , होमगार्डस आदि विभागों के अधिकारी, धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

शासन महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धः मुख्य सचिव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उदयती फाउंडेशन (टीयूएफ) एवं उत्तर प्रदेश के योजना विभाग, आपसी सहयोग से लखनऊ में आयोजित 'यूपी में महिला समावेशी विकास को बढ़ावा देना: प्रमुख अनिवार्यताएं और प्रगति' विषय पर एक बहु-हितधारक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह इसे यूपी की आर्थिक वृद्धि का स्तम्भ समझती है। बैंक सखी योजना ने वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बैंक सखी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के द्वारा बैंक सखियों ने कमीशन के रूप में 70 करोड़ रुपये कमाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि, सेवा क्षेत्र और तेजी से बढ़ते उद्योगों के साथ जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जोड़ने से उनकी पूरी क्षमता का उपयोग होगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ेगी और समग्र विकास सुनिश्चित होगा। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करके, हम महिलाओं के योगदान का सहयोग कर सकते हैं और एक अधिक समावेशी और समृद्ध समाज को बढ़ावा दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना, जिसने लगभग 250 बिलियन डॉलर से बढ़कर वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश को देखते हुए कई राज्यों ने वन ट्रिलियन डॉलर पर कॉन्सेप्ट नोट्स और स्ट्रेजेडी पेपर लिखे। उत्तर प्रदेश की कैपिटा इनकम देश की तुलना में आधे पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 25 लाख करोड़ रुपये की आसपास है। जमीन, जलवायु और जल संसाधन यूपी को पॉवरहाउस बनाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतर प्रदेश एक पॉवरहाउस है। यूपी में 75 फीसदी क्षेत्रों में खेती होती है। खेती का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट सिंचाई होता है। अगर एक-एक खेत को सिंचित कर दिया जाए, तो हर एक परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं।

प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने कहा कि लैंडस्केप स्टडी रिपोर्ट में प्रस्तुत डेटा भविष्य की कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप है। महिला आर्थिक सशक्तीकरण पर एक संचालन समिति की स्थापना और एक महिला आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक का शुभारंभ प्रगति को ट्रैक करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा। स्पष्ट बेंचमार्क सेट करके और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सशक्तीकरण में पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं।

कार्यक्रम में मिशन यू.एन.एन.ए.टी.आई. (उत्तर प्रदेश नारी - नई आकांक्षा, तरक्की और इच्छाएं) की नींव रखी गई, जो उत्तर प्रदेश सरकार के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप महिलाओं को प्रभावित करने वाले जीवन-चक्र के मुद्दों को संबोधित करने और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसे 'उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना' शीर्षक से एक व्यापक अध्ययन द्वारा आगे बढ़ाया गया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार, निदेशक-स्वास्थ्य, इंडिया कंट्री ऑफिस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अलकेश वाधवानी, संस्थापक व सीईओ, द कन्वर्जेंस फाउंडेशन आशीष धवन, उदयती फाउंडेशन की सीईओ सुश्री पूजा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को मिला व्यावसायिक प्रशिक्षण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों का 22वें व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को नगरीय निकायों के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं के सवालों के जवाब दिए और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग अमृत अभिजात की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में प्रशिक्षुओं को नगर विकास की विभिन्न योजनाओं और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव ने उन्हें स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभों के विषय में विस्तार से जानकारी दी।उन्होंने बताया कि कैसे ये योजनाएं शहरी क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान कर रही हैं और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं। प्रशिक्षुओं ने इस सत्र को अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक पाया। उन्होंने कहा कि इस सत्र से उन्हें नगरीय विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर समझने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। नगर विकास विभाग इस प्रकार के सत्रों का आयोजन कर नव-प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रोत्साहित करने और शहरी विकास की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सत्र में प्रमुख सचिव के साथ विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, अजय कुमार शुक्ल, सचिव नगर विकास, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, विशेष सचिव, नगर निकाय निदेशक अनुज कुमार झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने पार्टी मुख्यालय में किया वृक्षारोपण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पाण्डेय ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण मे वृक्षारोपण किया। इस पुनीत अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय तथा नेता कांग्रेस विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद रहीं।

ज्ञातव्य हो कि पिछले दिनों रायबरेली प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने शहीद उपवन रायबरेली में 'राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान' के तहत एक पीपल का वृक्ष रोपित किया था। इसी क्रम में अमेठी में नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा ने एक समय में पूरे जनपद में 17 हजार वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया था। रायबरेली जनपद में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी ने 20 हजार वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पिछले 1 माह में अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में वृक्षारोपण को महत्व देते हुए वृक्षारोपण को महत्व दे रहे है। मिशन मोड में शुरू किये गये 'राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान' की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर निरन्तर रिर्पोटिंग की जा रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि वर्षा ऋतु के समाप्त होते-होते प्रदेश के सभी 1 लाख 62 हजार बूथों पर इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जाए। इस कार्यक्रम में प्रभारी महासचिव अविनाश पाण्डेय ने प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों, जागरूक नागरिकों के साथ-साथ शैक्षिक संगठनों से अपील की है कि आपस में सामंजस्य बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के इस पुनीत यज्ञ को जन-जन तक पहुंचाएं और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करे। अविनाश पाण्डेय ने कहा कि विकास के नाम पर केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकारों ने लाखों पेड़ कटवा दिये हैं, जिसका नतीजा यह है कि गर्मी के प्रकोप से पूरा देश एवं प्रदेश झुलस रहा है। मानसून का भी समय पर न आने का मुख्य कारण वृक्षों का काटा जाना अर्थात उनकी संख्या का कम होना ही है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस यातना से निजात केवल वृक्षारोपण से ही मिल सकता है इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी 'राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान' के जरिए इस पुनीत कार्य को कर रही है। पाण्डेय ने कहा कि हमें ना सिर्फ पेड़ लगाने हैं बल्कि अगले तीन वर्षों तक उनका संरक्षण भी करना है।

भाजपा फिर से समाज में दूरियां पैदा करने के लिए ले रही है फैसलेः अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कारोबार लोगों को जोड़ता है लेकिन भाजपा वोट और सत्ता के लिए नफरत फैलाती है। भेदभाव करती है। समाज को लड़ाती है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अयोध्या में हार गई। भाजपा को पता चल गया है कि साम्प्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है। वह फिर से समाज में दूरियां पैदा करने के लिए फैसले ले रही है। यादव ने कहा कि लोग नौकरी, तरक्की, खुशहाली चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी से निजात चाहते हैं लेकिन भाजपा किसानों, नौजवानों, गरीबों के मुद्दे पर बात नहीं करती है। भाजपा सरकार झूठे वादे करती है। बड़ी-बड़ी बाते करती है लेकिन वो उसके फैसलों में दिखाई नहीं देता है। भाजपा ने पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीना, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पहले पुलिस चोर पकड़ती थी, भाजपा सरकार में पुलिस-पुलिस को पकड़ रही है। भाजपा सरकार के अपराध का भंडाफोड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त है। गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फुटपाथ पर है। भाजपा सरकार जनता की जान बचाने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। तहसील थानों से लेकर विभागों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गयी है। भाजपा के नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं। प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं था।

चौक स्थित कंचन मार्केट के सामने हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर लगने वाली अवैध फूलमंडी को ध्वस्त करते बुलडोजर

बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज-2024 का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से प्रदेश में बाढ़ आपदा के प्रति 44 अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील जनपदों में बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन योजना भवन स्थित सभागार में किया गया। मॉक एक्सरसाइज़ के तृतीय एवं अन्तिम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, पीवीएसएम, एवी.एसएम वीएसएम (से.नि.) की अध्यक्षता में बाढ़ आपदा के प्रति 44 अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील जनपदों में भौतिक रूप से मॉक एक्सरसाइज़ का अभ्यास कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राम केवल ने बताया कि मॉक एक्सरसाइज़ की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। सबसे पहले राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से सभी जनपदों को बाढ़ अलर्ट की सूचना दी गयी। इसके बाद जनपदों ने एसओपी के अनुसार कार्यवाही शुरू की।

सभागार से सचिव एवं राहत आयुक्त जी. एस. नवीन कुमार, राज्य स्तरीय अधिकारियों एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों की प्रक्रिया का सजीव चित्रण देखा एवं उनके कार्यों की समीक्षा की। मॉक एक्सरसाइज़ के दौरान जनपदों ने विभिन्न स्थलों पर राहत एवं बचाव प्रक्रिया की कार्यवाही नदी एवं तालाब में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की कार्यवाही की।

नव प्रवेशित छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नवयुग कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को बीए प्रथम वर्ष की नव प्रवेशित छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। जिसमे प्राचार्या प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने सभी नवागंतुक छात्राओं का महाविद्यालय परिवार की ओर से औपचारिक स्वागत किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। छात्रों को महाविद्यालय के अनुशासन और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों से परिचित कराया। उन्हें नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहने , महाविधालय परिसर को साफ सुथरा रखने,पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने, महाविद्यालय में संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया डॉ सोशल मीडिया और मोबाइल को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को समझाया कि आवश्यकता पर ही आप मोबाइल का प्रयोग करें । महाविद्यालय में विभिन्न सेमिनार और वर्कशॉप समय -समय पर आयोजित की जाती हैं। जिसमें छात्राओ की प्रतिभागिता उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। इस अवसर पर मेजर (डॉ.) मनमीत कौर सोढ़ी ने भी छात्राओं को महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया यह भी अवगत कराया कि महाविद्यालय परिसर पूरी तरह से रैगिंग फ्री है इसलिए सभी निर्भय होकर कैंपस में समस्त गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकते हैं।

आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर प्रो संगीता कोतवाल ने महाविद्यालय में संचालित सभी विभागों के क्लब के बारे में पावर पाइंट प्रेजेंटेशन से जानकारी दी। महाविद्यालय में संचालित एनसीसी और एनएसएस संबंधी गतिविधियों से भी छात्राओं को परिचित कराया गया।

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसान धान बुआई का न करें इन्तजारः कृषि मंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- वैकल्पिक रूप से मिलेट्स व दलहन तिलहन की फसल लगाने की दी सलाह

जुलाई माह में अब तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विशेष कर उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में तथा बुन्देलखण्ड में औसत से काफी कम वर्षा हुयी है। इन क्षेत्रों में अभी भी 25 से 30 प्रतिशत खेतों में बुवाई होनी शेष है। इन मौसमी दशाओं तथा बोआई की स्थिति को देखते प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि धान की फसल लगाने का इन्तजार करने की जगह किसान मक्का, बाजरा, ज्वार तथा दलहन-तिलहन की फसल लगायें।

उन्होंने अपील की है कि इस वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और बाजरा तथा मक्के की बढ़ती मांग को देखते हुये प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत संकर मक्का सामान्य बीज वितरण पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। देशी मक्का, संकर मक्का एवं पॉपकार्न मक्का के प्रदर्शन पर 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बेबी कॉर्न मक्का पर 40,000 हजा रुपए प्रति हेक्टेयर एवं स्वीट कॉर्न मक्का पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी विकास खण्डों पर मक्का, बाजरा एवं ज्वार के हाइब्रिड बीज के निजी कम्पनियों के स्टॉल लगाये जा रहे हैं, इन बीजों पर भी 50 प्रतिशत अनुदान किसानों के खातों में भेजा जायेगा। विकास खण्ड के विक्रय केन्द्रों पर मिलेट्स में मडुआ, सांवा, कोदो, बाजरा के निशुल्क बीज मिनीकिट के साथ दलहन और तिलहन के बीज विशेषकर उड़द, मूंग, अरहर एवं तिल के बीज सामान्य वितरण कार्यक्रम में भेजे गये हैं, जो पीओएस मशीन से बीज पर मिलने वाले अनुदान को समायोजित कर मात्र 50 प्रतिशत कीमत के भुगतान पर किसानों को मिल जायेगा। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि मौसम को देखते हुए उन्हें अपने खाली खेतों में मक्का, मिलेट्स, दलहन और तिल की फसलों की बुवाई शुरू कर देनी चाहिये। इससे किसानों के खेतों में आच्छादन समय से पूरा हो सकेगा।

एचएल एग्रो ने कानपुर देहात में अपनी इकाई के विस्तार में किया 500 करोड़ का निवेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश में नए निवेश लाने के साथ ही मौजूदा निवेश के विस्तार के लिए योगी सरकार ने अपनी नीतियों में जो सुधार किया है उसका असर देखने को मिल रहा है। वैश्विक खाद्य एवं पेय उद्योगों के लिए संयंत्र आधारित कच्चे माल के उत्पादन, विपणन तथा आपूर्ति में विशेषज्ञता रखने वाली कम्पनी एचएल एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा.लि. ने कानपुर देहात में अपनी इकाई के विस्तार में ?499.99 करोड़ का नियोजित निवेश किया है। इस निवेश के माध्यम से कंपनी उत्तर प्रदेश में अपनी मक्का स्टार्च एवं तरल ग्लूकोज इकाई को विस्तार दे रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुरूप, एचएल एग्रो ने अपने मौजूदा संयंत्र के परिसर में विस्तार की योजना बनाई है, जिसमें कनेक्टिविटी, कच्चे माल की उपलब्धता, एवं उपयोगिताओं आदि के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं। इन्वेस्ट यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोलते हुए एचएल एग्रो के प्रवक्ता एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अतुल रस्तोगी ने एक मजबूत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में राज्य की दूरदर्शी नीतियों पर जोर दिया एवं सराहना की। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, जिससे प्रारंभिक आशय दाखिल करने से लेकर इकाई के वाणिज्यिक संचालन तक निर्बाध निष्पादन की सुविधा मिली तथा विशेष रूप से राज्य में व्यापार एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई पूंजी सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहनों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के सकारात्मक एवं मददगार रवैये ने अनुभव को सहज बना दिया। ऐसा लगा जैसे हम किसी सामान्य सरकारी विभाग से निपटने के बजाय किसी सक्रिय भागीदार के साथ सहयोग कर रहे हों।

सामाजिक न्याय का प्रतीक थीं फूलन देवीः डॉ. राजपाल कश्यप

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लखनऊ स्थित दारूलशफा के प्रदेश कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप ने कहा कि फूलन देवी सामाजिक न्याय की प्रतीक थी जो आजीवन अन्याय के खिलाफ लड़ती रही। इस अवसर पर रामवृक्ष सिंह यादव पूर्व एमएलसी, श्यामकृष्ण गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, राजेन्द्र लोधी प्रदेश सचिव, मनोज पाल गौतम जिलाध्यक्ष, देवेश राजपूत, आकाश गौतम, अजय सिंह लोधी, राजेश पाल, गोविन्द रावत, ऋषि गौतम, मंसूर अली, गुरूद चौरसिया, डी.के. कश्यप, अवशेष कश्यप, हरीश चौरसिया आदि प्रमुख नेताओं ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने किया अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का औचक निरीक्षण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ व हज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका की जांच की। उन्होंने निदेशालय के विभिन्न अनुभागों में जाकर कार्यालय के साफ सफाई व्यवस्था को देखा। उन्होंने निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण जे. रिभा से विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी कार्मिक निर्धारित कार्यालय अवधि में अनिवार्य रूप से अपनी सीट पर उपस्थित रहे। सभी कर्मचारी सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित के कार्यों को ससमय पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न की जाए।

शिक्षकों ने दी चेतावनी, मांगे पूरी न हुईं तो होगा बड़ा आंदोलन

● मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र डीआईओएस को सौंपा

संवाददाता। गाज़ीपुर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन की बहाली और वित्तीय विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय और जिलाध्यक्ष शिवकुमार सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित 23 सूत्रीय मांग पत्र डीआईओएस भास्कर मिश्र को सौंपा। प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। मांग पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली, वित्त विहीन विद्यालय में कार्यालय शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण तथा निशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि दिलाए जाने की मांग की गई है। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष शिवकुमार सिंह ने कहा कि 23 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक पिछले लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षक आज मजबूरी में डीआईओएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मुताबिक अगर सरकार ने उनकी मांगों पर अब भी गौर नहीं किया तो वह कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे। धरना प्रदर्शन में शिक्षकों ने बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर अपनी ताकत का एहसास कराया।

सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल देते हुए मांगों को पूरी किए जाने की गुहार लगाई गई। इस प्रदर्शन में एक हज़ार से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। महिला टीचर्स भी शामिल थीं।

एसडीएम ने दो दर्जन स्कूली वाहनों का 3 लाख का किया चालान

सकलडीहा, चन्दौली। जिले में खटरा वाहनों से स्कूली बच्चों के ले जाने व बबुरी में हुई दुर्घटना को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रूप अख्तियार किया है। गुरूवार को डीएम निखिल टी फूंडे के निर्देश पर एसडीएम अनुपम मिश्रा ने एआरटीओ सर्वेश गौतम के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर दो दर्जन स्कूली वाहनों का विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए 3 लाख 32 हजार 250 रूपया का चालान काटा है। एसडीएम के इस कार्रवाई से स्कूल संचालकों में खलबली मची है। एसडीएम ने चेताया कि नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लापरवाह विद्यालय संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जायेगी।

बबुरी थाना क्षेत्र के गोगहरा कम्हरिया गांव के समीप बुधवार को एक निजी कान्वेंट बिद्यालय की बस पलट गई। जिसमें चालक सहित 13 बच्चे घायल हो गए।इस घटना से जनपद में खलबली मच हुई है।शासन की ओर से मामले का संज्ञान मे लेते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। आरोप है कि जिले में मानक के विपरीत डग्गमार वाहनों से सुबह शाम स्कूली वाहनों से बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है। जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती है। यही नही बच्चों को प्राइवेट से लेकर स्कूली वाहनों में ठूस कर भेजा जाता है। डीएम के निर्देश पर सकलडीहा एसडीएम अनुपम मिश्रा ने चहनिया सहित अन्य क्षेत्र के विभिन्न 24 स्कूली वाहनों से विभिन्न कारणों के तहत 3 लाख 32 हजार 250 रूपये का चालान किया गया है।

इस मौके पर चेताया कि बगैर हाई सिक्योरटी और फिटनेस वाहन चलने पर स्कूल प्रबंधक सहित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। यह अभियान अगले दिन लगातार अभियान चलाने की बात कही।इस मौके पर एआरटीओ सर्वेश ,अशोक यादव सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

बाढ़ आपदा से बचाव के दृष्टिगत की गई राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज

संवाददाता। प्रयागराज

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में गुरुवार को संगम क्षेत्र के वीआईपी घाट पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तत्वाधान में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। जिसके तहत कोई आपदा आती है तो कितना जल्दी उससे बचाव किया जा सकता है के बारे में मॉक एक्सरसाइज के माध्यम आम जनमानस एवं वार्डेन्स को जानकारी दी गयी। ईओसी बाढ़ द्वारा बताया गया कि अतिवृष्टि के कारण धूस्सा घाट पर जलस्तर बढ़ रहा है।

संगम किला के पास नाव पलट गयी जिसके बचाव के लिए एसडीआरएफ जल पुलिस पीएसी की टीम एवं आर्मी की टीम घटना स्थल के लिए रवाना कर बाढ़ पीड़ितों एवं बाढ़ से प्रभावित पशुओं एवं आमजनमानस को रेस्क्यू करके कैसे बचाव किया जा सकता है का रिहर्सल मॉकड्रिल किया गया। सेना के जवानों एवं गोताखोरों की मदद से खोज एवं बचाव कार्य सम्पादित किया गया। जिसके पश्चात प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं को मेडिकल कैम्प पर पहुंचाया गया एवं कैम्प पर उपस्थित चिकित्सकों द्वारा बाढ़ प्रभावित पशुओं एवं व्यक्तियों का इलाज का रिहर्सल किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनय कुमार सिंह कर्नल विकास खरे मेजर विनोद भलोटिया होमगार्ड टीम चीफ वार्डन अनिल कुमार उप नियंत्रक नीरज मिश्र एडीसी राकेश कुमार तिवारी जल पुलिस के नेतृत्व में एसडीआरएफ और उनकी टीम पीएसी चतुर्थ बटालियन पीएसी 42वीं बटालियन मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय से डॉ संजय बरनवाल और उनकी टीम मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय से डॉ प्रेम कुमार सिंह डॉ एम पी सिंह व उनकी टीम आपदा प्रबंधन सहायक अन्तिम कुमार पूर्व जल पुलिस निरीक्षक कड़ेदीन यादव आदि उपस्थित रहे।

एडीएम ने किया सदर तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय का निरीक्षण

● अनुपस्थित मिले उप निबंधक, कार्यालय में अव्यवस्था का आलम

सोनभद्र। सदर तहसील परिसर स्थित उप निबंधक कार्यालय का अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उप निबंधक आनंद शुक्ला अनुपस्थित मिले। कार्यालय में उप निबंधक के स्थान पर कार्यालय के लिपिक सिद्धार्थ सिंह व उनके साथ कम्प्यूटर आपरेटर उपस्थित रहे। सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि उप निबंधक स्थलीय जांच में कहीं गए हैं, उनके द्वारा जांच स्थल का नाम नहीं बताया गया। पांच मिनट बाद एआईजी स्टाम्प व 20 मिनट बाद उप निबंधक कार्यालय में उपस्थित हुए।

कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्था को देखकर एडीएम हतप्रभ रह गए। बताया कि निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उप निबंधक कार्यालय में बाहरी व अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश है। ऐसे लोगों से कार्यालय का कार्य कराया जाता है। जिसके कारण कार्यालय की गापनीयता व सूचिता प्रभावित होता है।

निरीक्षण के दौरान कार्यालय में जितेंद्र श्रीवास्तव, राकेश सिंह, सूरज, सौरभ, सोनू, कृष्णानन्द व अन्य अधिवक्ता व मुहर्रिर के साथ बैनामा आदि कार्य के लिए आए। क्रेता व विक्रेता उपस्थित पाए गए। इसमें से जितेन्द्र श्रीवास्तव व कृष्णानन्द प्राईवेट व्यक्ति मिले। उन लोगों द्वारा निबंधक कार्यालय की कुर्सियों पर बैठकर कार्यालीय कार्य संपादित करते मिले। पूछने पर जितेंद्र श्रीवास्तव कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। सूरज ने अपने को सिद्धार्थ सिंह का ड्राइवर बताया गया। एडीएम ने निरीक्षण की आख्या जिलाधिकारी को सौंप दी है।

मीरज़ापुर जिले में 10 अगस्त को चलेगा कृमि मुक्ति अभियान

● दो लाख चालीस हजार बच्चे खाएंगे एल्बेडोजोल

संवाददाता। मीरज़ापुर

बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 अगस्त को कृमि मुक्ति अभियान चलाया जायेगा। इस आशय की जानकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश यादव ने दी।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि उस दिन 1वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों व किशोरियों को पेंट के कीड़े की दवा एलबेडाजोल दिया जायेगा। इसके लिए पूरे जिले में लगभग दो लाख चालीस हजार बच्चों को चिन्हित किये जाने का काम शुरू हो चुका है। सरकारी स्कूलों व कालेजों के साथण्साथ प्राइवेट स्कूलोंए आंगनबाड़ी केन्द्रोए ईट भठ्ठो और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को यह दवा खिलाने व देने का काम स्वास्थ्य विभाग व बाल विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। जो बच्चे दवा खाने से छूट जाते है ऐसे छूटे हुए बच्चों के लिए एक सप्ताह का अभियान भी चलाया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर छोटे लाल वर्मा ने बताया कि यह अभियान विगत कुछ वर्षो से वर्ष में दो बार चलाया जा रहा है। इसके पूर्व लगभग नौ लाख बच्चों को उनके पेट से कीड़े निकालने की दवा खिलाई गई थी। इस बार 10 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग व बाल विकास परियोजना सेवा एवं पुष्टाहार विभाग सामजस्य स्थापित कर बच्चों को कीड़े की दवा खिलाने का कार्य करेगे।

उन्होंने बताया कि एलबेडाजोल एक कृमि नाशक गोली है। इसको लेने से बच्चों के पेट के कीड़े निकल जाते है। एक से दो वर्ष के बच्चों को आधी गोली पीसकर साफ पानी के साथ देने का परामर्श दिया जाता है। जबकि दो वर्ष से तीन वर्ष तक के बच्चों को एक गोली पीसकर दी जाती है। विद्यालयों में शिक्षको को यह सुझाव दिया गया है कि निर्धारित तिथि को बच्चे कुछ न कुछ घर से खाकर स्कूल आयें। इस विषय में अभिभावकों को भी जागरूक किया जाये।

स्थानांतरण के खिलाफ किया अभियंताओं ने प्रदर्शन

सोनभद्र। मनमाने तरीके से स्थानांतरण और स्थाईकरण के विरोध में बंधी प्रखंड द्वितीय राबर्ट्सगंज के अभियंताओं का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। अभियंताओं ने बांह पर काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रमुख अभियंता पर मनमानी कार्य करने का आरोप लगाया। अध्यक्षता सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग के अध्यक्ष इं. संजय विश्वकर्मा ने कहा कि प्रमुख अभियंता ने मनमानी तरीके से ट्रांसफर कर कर्मचारियों को परेशान किया है। यह किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। यह कार्यक्रम 27 जुलाई तक चलेगा। 27 को उत्तर प्रदेश के जल संसाधन एवं जल शक्ति मंत्री को पोस्टकार्ड भेजा जाएगा। 30 जुलाई को डीएम माध्यम से मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। प्रदर्शन में इं. राकेश कुमार, राम प्रवेश पाल, उमाशंकर गुप्ता, राम टहल, प्रेम प्रकाश, सूर्यमणि यादव, अनिल कुमार, विकास तिवारी समेत अन्य अभियंता शामिल रहे।

क्विक न्यूज

किशोर मगरमच्छ के हमले से हुआ घायल

सोनभद्र। घोरावल तहसील के मुर्तिया गांव के एक बंधी में मगरमच्छ ने किशोर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उम्भा गांव निवासी लवकुश गोड़ गुरुवार को मुर्तिया बंधी की ओर गया था। अपने मवेशियों को पानी पिलाने के बाद वह मवेशियों को बाहर निकाल रहा था। उस दौरान बंधी में रहे मगरमच्छ ने लवकुश को पानी में खींच लिया। उसका बाया हाथ बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उसके बाएं हाथ की हड्डियां कई जगह पर टूट गई। उसके सीने और पैर को भी जख्मी कर दिया। जिस समय उसे पानी में मगरमच्छ ने खींचा था, उसने शोर मचाया। साथी बच्चे शोर सुनकर लवकुश की ओर दौड़े। बच्चों ने देखा कि मगरमच्छ ने लवकुश के एक हाथ को पकड़ा है और दूसरा हाथ खाली है। तब बच्चों ने अपना दिमाग चलाया और वही पड़ी हुई एक प्लास्टिक की पाइप को उठाया और लवकुश के दाहिने हाथ की ओर फेंका और कहा कि पकड़ लो। पाइप को लवकुश पकड़ तो लिया लेकिन बच्चों ने खींचना चाहा लेकिन नहीं खींच सके। बच्चों ने तेजी से शोर मचाया। मौके पर ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंचे। किसी तरह से मगरमच्छ के चंगुल से लवकुश को मुक्त कराया गया। उसे लेकर घोरावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां पर उसकी हालत गंभीर देख चिकित्सक उपचार करने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

वांछित चल रहे 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोनभद्र। थाना रावर्ट्सगंज पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से वांछित चल रहे 08 वारण्ट से सम्बन्धित 7 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया। जनपद में चलाये जा रहे वारण्टी,वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना रावर्ट्सगंज पुलिस की गठित टीमों द्वारा न्यायालय द्वारा 08 गैरजमानती अधिपत्र मे 07 वांछित वारण्टियों मनोज पाण्डेय पुत्र रामप्रसन्न पाण्डेय नि0 चुर्क बाजार थाना रावर्ट्सगंज उम्र 32 वर्ष मुन्ना शाह पुत्र मजीद नि0 शिल्धरी थाना राबर्ट्सगंज उम्र करीब 56 वर्ष छोटू उर्फ प्रकाश पुत्र मनोज नि0 हिन्दुआरी थाना रा0गंज उम्र 22 वर्ष बंगाली मौर्या उर्फ शशिकान्त उर्फ स्व0 प्रदीप उर्फ जयराम नि0 नागनारहैरिया महुरिया थाना रा0गंज उम्र करीब 35 वर्ष यशवन्त पुत्र मुन्नू उर्फ अमरनाथ नि0 पुसौली थाना रा0गंज उम्र करीब 38 वर्ष शमशेर सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह सा0 करकी थाना करमा सोनभद्र हा0प0 क्वार्टर नं0 489 कांशीराम आवास थाना रा0गंज उम्र 32 वर्ष सोनू सोनार पुत्र नन्दू सोनार अम्बेडकरनगर थाना रा0गंज उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वारण्टी को न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी चुर्क रामसिंहासन शर्मा का0 दीपक मिश्रा हे0का0 सुनील कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मी सामिल रहे।

दुबई में डॉ आनंद प्रकाश को प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मान

प्रयागराज। दुबई के बुर्ज अल अरब में आयोजित भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर आर्गेनाईजेशन के अध्यक्ष डॉ आनंद प्रकाश सिंह को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। यह विशेष कार्यक्रम बरनेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया। जिसमें देश विदेश के तीन सौ से अधिक चिकित्सकों के साथ राजनीतिक स्वास्थ्य क्रिकेट और सिनेमा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को शोभायमान किया। डॉ आनंद प्रकाश सिंह ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान और समर्पण भाव के माध्यम से चिकित्सा जगत में एक विशेष स्थान बनाया है। डॉ आनंद प्रकाश सिंह एक प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो विगत 21 वर्षों से देश और विदेश के रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार करने में अपनी विशेषज्ञता और सफलता के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। उनके शोध अनुसंधान शिक्षा और रोगियों के प्रति उदारता और सेवा में अद्वितीय प्रतिबद्धता से उन्हें प्राईड आफ होम्योपैथी सम्मान के लिए चुना गया।

11 हजार शिवलिंग के निर्माण संग होगा महा रुद्राभिषेक

प्रयागराज। कर्तव्य पथ परिवार के तत्वावधान में आयोजित में मुंशी राम प्रसाद की बगिया नारायण वाटिका मुट्ठीगंज में शिव महापुराण की कथा के द्वितीय दिवस पर कथा का रसपान कराते हुए सदानंद महाराज ने कहा कि मन एवं चरित्र को पवित्र करती है। शिव महापुराण की कथा और मनुष्य का मनुष्यता ना बिगड़ जाए इसलिए कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कथा मनुष्य को राष्ट्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराती है और जन्म और मरण से मुक्त करता है और कहा कि शिव भगवान का स्वरूप है और शंकर भगवान का है स्वभाव और प्रयंकर भगवान का प्रभाव है जो जगत का कल्याण करते हुए व्यास ने कहा शिव महापुराण में 24000 श्लोक हैं जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर की व्याख्या करता है। कथा के मुख्य यजमान सपना आर्या रहीं। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि कथा स्थल नारायण वाटिका में 26 जुलाई को सुबह 9 बजे से 11 हजार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा

सकलडीहा में बिजली समस्या को लेकर विधायक ने किया घेराव

संवाददाता। सकलडीहा, चन्दौली

सकलडीहा विद्युत उपकेन्द्र से ग्रामीण और तहसील मुख्यालय की विद्युत आपूर्ति बीते दो सप्ताह से खराब है। शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी सिर्फ कोरा आश्वासन दे रहे है। व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता की शिकायत पर सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव उपकेन्द्र पर पहुंचकर अधिकारियों का घेरॉव किया। घंटों इंतजार के बाद भी एक्सीईन के नहीं आने पर विधायक ने नाराजगी जताया। चेताया कि दो सप्ताह के अंदर बिजली की विभिन्न समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी 9 अगस्त को विद्युत उपकेन्द्र पर धरना प्रदर्शन करेगे।

जिसकी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी और प्रशासन की होगा। व्यापारी नेता और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली उपकेन्द्र से ग्रामीण और तहसील मुख्यालय को विद्युत आपूर्ति होती है। इस समय सिंचाई का समय चल रहा है। इसके अलावा उमस और गर्मी से लोग बेहाल है। इसके बाद भी बिजली की अंधाधुन कटौती और ट्रांसफार्मर जलने व तार टूटने के साथ बार बार ब्रेक डाउन हो जाने से घंटों आपूर्ति ठप हो जाता है। शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी भुगतान नहीं होने व सामान का रोना रो रहे है।

व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता की ओर से बार बार समस्या बताने के बाद भी समाधान नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों की शिकायत पर विधायक सकलडीहा प्रभुनारायण सिंह यादव विद्युत उपकेन्द्र पर पहुंचकर विद्युत दुर्व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जताया। मौके पर घंटों इंतजार के बाद भी एक्सीईएन के नहीं आने विधायक ने मोबाईल ट्रांसफार्मर सहित अन्य समस्या दो सप्ताह में सही नहीं होने पर आगामी 9 अगस्त को आन्दोलन की चेतावनी दी। सुबह 7 बजे से चार बजे तक ब्लॉक मुख्यालय की विद्युत कटौती शुरू नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी। एसडीओ सतीश कुमार ने बताया कि ब्रेक डाउन के कारण आपूर्ति बंद थी।

भाषा के जरिए संवाद की कला के बारे में सीखा

प्रयागराज। कार्यक्रम को लेकर तमाम योजना बनाई गई है। भाग्य लक्ष्मी की परख मदान शो में आंचल के रोल में अपनी शानदार अदाकारी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। अपने ग्रे किरदार के साथ वो इस शो में ऋषि रोहित सुचंती और लक्ष्मी ऐश्वर्या खरे की जिंदगी में ढेर सारा ड्रामा खड़ा कर रही हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए भाग्य लक्ष्मी रोज रात साढ़े आठ बजे सिर्फ जी टीवी पर आएगा। जहां पिछले कुछ सालों में उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। वहीं उनके आंचल के किरदार ने वाकई सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक क्लासिकल डांसर के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। जहां उन्होंने छोटे छोटे एक्स्प्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के जरिए संवाद की कला के बारे में बहुत कुछ सीखा। जहां वो एक डांसर के रूप में बड़ी हुईं। वहीं आगे चलकर एक्टिंग में उनकी दिलचस्प जागी और दो हजार छह में उन्होंने टेलीविजन में अपना सफर शुरू किया।

डीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम का किया औचक निरीक्षण

प्रयागराज। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय रिकार्ड रूम और परिसर का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिकार्ड रूम में रखी फाईलों को देखते हुए अव्यवस्थित ढंग से रखी फाईलों को व्यवस्थित ढंग से रखे जाने और अभिलेखों की निरंतर साफ सफाई कराते रहने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त की और कहा कि इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं लिए जाये और जहां अभिलेख रखे हैं। वहां पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न होने पाये यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने उप निबंधक सदर प्रथम को अपर जिलाधिकारी नजूल से मिलकर कार्यालय को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने अभिलेखों के साथ साथ विद्युत उपकरणों का भी ध्यान रखे जाने के लिए कहा है। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व विनय कुमार सिंह उप निबंधक सदर चतुर्भुज पाण्डेय उपस्थित रहे।

900 वर्ष प्राचीन सिद्ध संतों की तपोस्थली सिद्धपीठ हथियाराम मठ के 25वें महंत का मनाया गया 12वां निर्वाण दिवस

संवाददाता। गाज़ीपुर

अध्यात्म जगत में ख्यातिलब्ध सिद्धपीठ हथियाराम मठ के 25वें ब्रह्मलीन महंत महामंडलेश्वर स्वामी बालकृष्ण यति का 12वां निर्वाण दिवस गुरुवार को श्रद्धाभाव से मनाया गया। गौदान, शिवोपासना और समाधि पूजन के साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने संतो और विद्वतजनों के सद्विचारों संग महाप्रसाद ग्रहण किया।

सिद्धपीठ के पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नन्दन यति महाराज ने यजमान रणजीत सिंह के परिजनों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिवोपार्चन किया। तत्पश्चात समाधि पूजन और यजमान परिवार ने गौदान किया। ज्ञातव्य हो कि परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत पवाहारी स्वामी बालकृष्ण यति महाराज का वाराणसी के जागेश्वर आश्रम में श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर 27 जुलाई 2013 को तिरोधान हुआ था। वह करीब 900 वर्ष प्राचीन सिद्ध संतो की तपोस्थली सिद्धपीठ हथियाराम मठ के 25वें महंत रहे।

उनका आविर्भाव (जन्म) हिमालय के कूर्मांचल भूमि पर स्थित अल्मोड़ा के जोशी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, उज्जैन, मिर्जापुर और वाराणसी में हुई थी। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी द्वारा उन्हें वेदांताचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। स्वामी बालकृष्ण यति महाराज ने सन्यास ग्रहण कर नर्मदा तट एवं हिमालय में साधना किया। अट्ठाईस वर्षों तक फलाहार करते हुए उन्होंने तप साधना किया था। बाल्यकाल से ही अलौकिक प्रतिभा के धनी स्वामी बालकृष्ण यति ने कठिन साधना, हठयोग, समाधि तथा तपस्या से अध्यात्म जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। हरिद्वार के ज्वालापुर में शंकर आश्रम, इंदौर में विश्वनाथ धाम, हल्द्वानी में महालक्ष्मी अष्टादास का विख्यात मंदिर, वाराणसी , बलिया, मऊ के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार आदि प्रांतों व विदेशों में बड़ी संख्या में शिष्य हैं। धर्माध संदेश को लेकर उन्होंने कई बार विदेश दौरा भी किया था। नवरात्रि महोत्सव, शिवरात्रि महोत्सव तथा चातुर्मास महायज्ञ आदि को वह काफी महत्व देते थे। इस पीठ पर आसीन होने वाले संत यति सन्यासी कहे जाते हैं। इस गद्दी की परंपरा दत्तात्रेय, शुकदेव तथा शंकराचार्य से प्रारंभ होती है। मठ का प्रमाण सामान्य जनश्रुति, प्राचीन हस्तलिपि, लिखित पुस्तक तथा भारतीय इतिहास में मिलता है।

श्रीसिंह श्याम यति से इस पीठ की संत परंपरा प्रारंभ हुई थी। उन्होंने धर्म प्रचार के साथ अनेक शिक्षण संस्थाए भी संचालित किया था, जो आज वर्तमान पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नन्दन यति महाराज के संरक्षण में भव्य तरीके से पुष्पित पल्लवित होकर जनकल्याण में सहायक साबित हो रहा है।

विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन

अंबेडकर नगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने मानक विहीन स्कूली वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग को अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल प्रबंधक अपने बसों का समय से फिटनेस नहीं करा रहे हैं उन स्कूल बसों के पंजीयन के निलंबन एवं निरस्त करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूली वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग से एवं चरित्र सत्यापन का कार्य पुलिस विभाग से अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबंधन पूर्ण कराएं, निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं का परिवहन स्कूली वाहन में ना किया जाए, ऐसा पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की जाए, स्कूल प्रबंधन प्रत्येक बस का एक रूट चार्ट बनाएं जिसमें बच्चों को बैठाने एवं उतारने का स्थान नियत किया जाए जिसकी जानकारी प्रबंधक द्वारा अनिवार्य रूप से अभिभावक को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उपस्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया की स्कूल गेट के दोनों और सड़क पर रंबल स्ट्रिप व स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं जिससे कि विद्यालय से निकलने वाले छात्र-छात्राओं को तेज गति से आ रहे वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।

बैठक के माध्यम से अपर जिलाधिकारी ने सभी अभिभावकों से अपील किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए किसी भी दशा में स्कूटी,बाइक ना प्रदान करें मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा करने पर अभिभावक को जिम्मेदार मानते हुए दंडनीय अपराध माना गया।

चिकित्सक व एएनएम की तैनाती न होने से ग्रामीण नाराज

गाज़ीपुर। जनपद के रेवतीपुर सीएचसी अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगसर पर तीन साल से चिकित्सक व जच्चा बच्चा केंद्र पर ए एन एम की तैनाती न होने एवं अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने गुरूवार को हास्य कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के नेतृत्व में प्रदर्शन करने के साथ ही ताली थाली वादन कर स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान बोलते हुए कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार जहाँ ग्रामीण अंचलों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के प्रति गम्भीर होने का ढोंग दिखा रही है,वहीं स्वास्थ्य महकमा के लापरवाही के कारण लोगों को इस अस्पताल का लाभ वर्षों से नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने कहा कि यहाँ संविदा कर्मियों के भरोसे यह अस्पताल किसी तरह संचालित हो रहा है,यहाँ मरीज अब आना ही नहीं चाहते,यहाँ दवाओं एवं शल्य चिकित्सकीय सुविधाओं का घोर अभाव बना हुआ है। चेताया कि यहाँ जल्द चिकित्सक की तैनाती के साथ ही जच्चा बच्चा केंद्र व अन्य चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं,ताकि मरीजों को इस अस्पताल का लाभ मिल सके,उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु तरीके से बहाल नहीं होती है,तो ग्रामीण रेवतीपुर सीएचसी का घेराव,धरना प्रदर्शन के साथ ही ताडीघाट बारा नेशनल हाईवे को जाम कर देगें।जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की होगी।

बजट 2024

संतुलन के प्रयास

बजट 2024 विकास-केन्द्रित है, पर इसमें लोकरंजक तत्व हैं तथा 'राजग' सहयोगियों के सरोकारों को संबोधित करने के प्रयास हैं। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट 23 जनवरी, 2024 को पेश किया। इसका लक्ष्य भारत की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करते हुए सामाजिक समानता तथा राजग सहयोगियों के हितों की पूर्ति भी है। यह बजट आर्थिक विकास तथा राजनीतिक लाभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस बजट में ढांचागत संरचना, हरित ऊर्जा पहलों तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु आबंटनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। केन्द्रीय बजट 2024-25 मैक्रोइकोनामिक प्रगति तथा राजकोषीय स्थिरता पर केन्द्रित है। इसमें गरीबों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं जो सफलता के लिए प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन पर निर्भर होंगे। हालांकि, राजकोषीय घाटे की स्थिति सुधरी है और यह जीडीपी का 4.9 प्रतिशत हो गया है, पर काफी असमानतायें बनी हुई हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है, पर शहरी-ग्रामीण तथा आय असमानतायें बनी हुई हैं। इस बजट में अंतरिम बजट की तरह ही कृषि, ग्रामीण विकास, आवास तथा रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई को केन्द्र में रख कर आबंटन किया गया है। नए कदमों में पहली बार कर्मचारियों को सीधे भुगतान तथा सेवायोजकों को प्रोत्साहन शामिल हैं ताकि वे नौकरियों की संख्या बढ़ाएं। लेकिन बजट में लगभग 5.08 प्रतिशत मुद्रास्फीति को समुचित रूप से संबोधित करने के प्रयास नहीं हैं। विनिर्माण को सहायता देने के लिए सरकार ने एमएसएमई के

लिए क्रेडिट गारंटी तथा मुद्रा लोन की सीमायें बढ़ाने के साथ अन्य पहलें भी की हैं। 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर'-डीपीआई के माध्यम से कृषि व्यवहारों को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक पार्कों के विकास के साथ ही 'प्राकृतिक खेती' को सहायता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद बजट की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन तथा व्यापक आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने में निहित है।

केन्द्रीय बजट 2024 में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए नौजवानों के कौशल संवर्धन की समग्र योजना पेश की गई है। इसके अंतर्गत पांच साल में 20 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-आईटीआई का उच्चीकरण कर इनमें उपयुक्त उन्मुखीकरण हेतु व्यवस्थायें की जाएंगी। इनके पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा डिजाइन उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। बजट के सकारात्मक तत्वों में ढांचागत संरचनाओं में भारी निवेश शामिल है जिससे रोजगारों का सृजन होगा तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बजट में कुछ चुनौतियां भी शामिल हैं। खर्च की महत्वाकांक्षी योजनाओं से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है जिससे मैक्रोइकोनोमिक स्थिरता व मुद्रास्फीति नियंत्रण की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। बजट में प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में अनेक प्रकार के विलंब व अक्षमतायें दिखी हैं। 2024 के बजट में एक लोकरंजक दृष्टिकोण भी है जिसका उद्देश्य अपने सहयोगी-नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू की चिन्ताओं को संबोधित करना है। इसके लिए उदारता से धन आबंटन किया गया है। ढांचागत विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण तथा सामाजिक कल्याण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने के माध्यम से यह बजट सरकार द्वारा उन लोगों का समर्थन पुन: प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उससे थोड़ा असंतुष्ट हो गए थे।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार

भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या व उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिले चुनावी झटके के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूलाधारों पर आत्मावलोकन की आवश्यकता सामने आई है।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या व उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिले चुनावी झटके के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूलाधारों पर आत्मावलोकन की आवश्यकता सामने आई है। सिद्धार्थ मिश्रा ने 'हिंदू परंपरा' में ईश्वर के बारे में चर्चा करते हुए किसी आंदोलन से अलग रहते हुए कहा है कि भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, वे हमेशा सत्य बोलते हैं तथा 'त्रिकालदर्शी' हैं, यानी वे अतीत, वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में भगवान शंकर अपनी पत्नी देवी सती से कहते हैं, 'होइहै सोई जो राम रचि राखा', अर्थात वही होगा जिसका निर्धारण पहे ही भगवान राम ने कर रखा है। भगवान शंकर देवी सती से कहते हैं कि राम 'परम ब्रह्म' हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते हैं। भगवान राम के अनुयाइयों के लिए इस चौपाई का अर्थ राम के देवत्व और उनकी महिमा से है।

इस चौपाई के प्रारम्भ के बाद तुलसीदास कहते हैं, 'को करि तर्क बढ़ावै शाखा', अर्थात निरर्थक चर्चा के माध्यम से उनके निर्णय पर विवाद करने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद यह चौपाई इस कथन के साथ समाप्त होती है कि 'अस कहि लगे जपन हरिनामा, गई सती जहं प्रभु सुखधामा।' इस कथन का अर्थ मूलत: यही है कि जो लोग राम की शरण में जाते हैं उनको उसी प्रकार शांति प्राप्त होती है जिस प्रकार भगवान शंकर की पत्नी देवी सती को प्राप्त हुई थी।

हालांकि, भगवान राम में गोस्वामी तुलसीदास के विश्वास में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि मनुष्यों को उसके अपने 'कर्म' के आधार पर फल प्राप्त होता है और राम की 'रचना' पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो लोग भगवान राम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करने का प्रतीक मानते हैं, उनको अपने 'कर्म' का आत्मावलोकन करना चाहिए जिसके कारण भगवान राम की 'रचना' सामने आई है। ऐसे तत्वों को हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में पराजय से झटका लगा है और यह भी एक प्रतीक है। इसका विस्तार भगवान राम के क्षेत्र अवध और उसके आगे तक हुआ है। हालांकि, इसके अनेक अन्य सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक व सांगठनिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि 'रामजन्मभूमि आंदोलन' ने 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की अवधारणा को पुनर्जीवित करने और इसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सैकड़ों सालों से प्रतीक्षित भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भगवान राम में लोगों की आस्था और मजबूत होनी चाहिए थी और इसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय जनता पार्टी-भाजपा को मिलने वाले चुनावी लाभ के रूप में सामने आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। प्रख्यात अंग्रेजी कवि टी.एस. इलियट ने अपनी लोकप्रिय कविता 'हालो मैन' में लिखा है, 'दुनिया इसी प्रकार समाप्त होती है, किसी विस्फोट के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत हल्की सी आवाज से'। इसी कविता के प्रारंभ में इलियट ने लिखा था, 'बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रियेशन, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पांस फाल्स द शैडो', अर्थात अवधारणा और रचना के बीच तथा भावनाओं और प्रतिक्रिया के बीच खाली स्थान होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि रामजन्मभूमि आंदोलन की समाप्ति चुनावी रूप से किसी विस्फोट के बजाय एक हल्की सी आवाज के रूप में क्यों हुई।

इस वर्ष जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इस शताब्दी का महत्वपूर्ण आयोजन था। अनेक राज्यों में भगवान राम के प्रतीकों वाली फहराती ध्वजाओं तथा लोकप्रिय बालीवुड परंपराओं के अनुसार इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों ने संदेहवादियों को भी विश्वास दिला दिया था कि यह आंदोलन हमारी संस्कृति और प्रकृति की आत्मा है। यह आयोजन असाधारण कैमरा कवरेज तथा एकदम सटीक कार्यक्रम के साथ आमतौर से निराशाजनक परिवेश में संभावित 'राम राज्य' के उदय की व्यापक उम्मीदों से भरा था। भगवान राम के शासन यानी 'राम राज्य' को शासन का आदर्श रूप माना जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस आयोजन ने भाजपा को अच्छा चुनावी लाभ नहीं दिलाया। पार्टी के रणनीतिकार इस नैतिक रूप से निराशाजनक चुनावी धक्के से हतप्रभ रह गए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकारों के लिए 'अवधारणा और रचना तथा भावनाओं व प्रतिक्रिया के बीच खाली स्थान' का पता तब तक नहीं चला जब तक वे 'वीआईपी रूट' और लाखों लोगों द्वारा भगवान रामलला के 'दर्शन' की प्रतिध्वनियों से बाहर नहीं निकले। राम राज्य का अर्थ समाज की उस आदर्श स्थिति से है जिसकी इच्छा भगवान राम ने की थी। इसमें पूर्ण सद्भावना, न्याय, धर्म व समृद्धि शामिल हैं जहां लोग शांति और प्रसन्नता से रह सकें।

महात्मा गांधी ने इस व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सत्य ही राम राज्य है जिसमें राजाओं और निर्धनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे। भगवान रामलला के दर्शनों की लाइनों में खड़े गरीब रामभक्तों से पूछें कि क्या आदर्श राज्य आ गया है। रामजन्मभूमि मंदिर में पूरी 'दर्शन' प्रक्रिया के प्रबंधन पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि यह संभवत: 'राम राज्य' के माडल के अनुकूल न हो। मंदिर प्रवेश से गर्भ गृह तक लाल सैंडस्टोन का बिना कारपेट से ढका मार्ग भयानक गर्मी में भक्तों के लिए बहुत कष्टदायक है। यदि गर्म पत्थरों की फर्श पर कारपेट बिछा दिए जाते तथा रास्ते में भयानक गरमी में राहत देने के लिए कारगर एयर कूलर तथा लाइन में लगे लोगों की प्यास बुझाने के लिए वाटर कूलर लगा दिए जाते तो बहुत अच्छा होता। इससे स्पष्ट होता कि मंदिर प्रशासन यहां आने वाले रामभक्तों व श्रद्धालुओं की 'देखभाल' करता है और यह उसके प्रबंधन दायरे से बाहर भी नहीं था।

लेकिन विडंबना है कि मंदिर प्रबंधन तथा वहां व्यवस्था देखने वाले लोगों की ओर से देखभाल के ऐसे कदम नहीं उठाए गए अथवा वे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नाकाफी थे। सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर अपनी संरचना और वास्तु के दृष्टिकोण से भव्य है और दावा किया जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक उसे किसी प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मंदिर के भीतर का पूरा परिवेश 'सेवा' के बजाय 'सुरक्षा' के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावित लगता है। ऐसे में प्रशिक्षण विहीन निजी सुरक्षा गार्डों की भीड़ एक और समस्या खड़ी करती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई जानकारियों पर इन सुरक्षा गार्डों के असभ्य जवाबों से मंदिर आंदोलन के बारे में अनेक लोगों की बची-खुची श्रद्धा को भारी धक्का लगता है।

लेकिन इन कष्टों व असुविधाओं के बावजूद रोज लाखों भक्त देश के सभी कोनों से भगवान रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। इनके लिए अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने तथा उनको उपयुक्त जानकारियां देने के प्रयास किए जाने चाहिए। बालीवुड की सुपरहिट फिल्म 'नील कमल' में प्रख्यात गीतकार साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां बहुत मशहूर हैं-'मेरे रोम रोम में बसने वाले राम'। इसका अर्थ है कि भगवान राम का सभी मनुष्यों में वास है।

सालों से गाया जाने वाला यह गीत अनेक रामभक्तों की भावनाओं को उजागर करने वाला है। लेकिन यदि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालु राम भक्तों के कष्टों का निवारण नहीं होता है तथा मंदिर प्रशासन का उनके प्रति सेवा भाव जाग्रत नहीं होता है तो इससे 'राम मंदिर आंदोलन' से जुड़े लोगों के प्रति करोड़ों रामभक्तों में श्रद्धा की भावना नहीं जाग्रत होगी।

निश्चित रूप से इन परेशानियों के बावजूद देश-विदेश के करोड़ों भक्तों की भगवान राम के प्रति आस्था में कमी नहीं आएगी, पर वह मंदिर प्रशासन तक विस्तार नहीं लेगी।

आम बजट: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

प्रियंका चतुर्वेदी
(लेखिका शिवसेना नेत्री व राज्यसभा सांसद हैं)

नव निर्वाचित गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। भारत की वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया, और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के लोगों से बहुत सारे वादे किए गए थे और उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं - बेरोज़गारी, महंगाई, स्थिर आय - कोई उम्मीद कर सकता था कि आम चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा कुछ सबक सीखेगी और सही रास्ता अपनाएगी। हालाँकि यह देखना निराशाजनक था कि जन की बात को नज़रअंदाज़ करने की वही गलती हुई, मैडम मंत्री ने भी प्रधानमंत्री की तरह मन की बात भाषण दिया।

यह केंद्रीय बजट होना था, लेकिन अब इसे आसानी से प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना की घोषणा कहा जा सकता है, जिसमें उन राज्यों के लिए बड़े वित्तीय पैकेज निर्धारित किए गए हैं जो उनके गठबंधन सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे हैं और जिनके समर्थन की उन्हें अपनी सरकार को निर्बाध रूप से चलाने के लिए ज़रूरत है - बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी। जबकि बिहार के लिए 59000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, यह आंध्र प्रदेश के लिए 15000 करोड़ था।

हालांकि, विशेष दर्जे की उनकी मांग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। अन्य राज्यों के हितों की अनदेखी करके राजनीतिक रूप से प्रेरित राज्य बजट आवंटन करना भविष्य की सरकारों के लिए गलत मिसाल कायम करता है। ये फंड आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं। गठबंधन द्वारा संचालित महाराष्ट्र, एक ऐसा राज्य जो केंद्र को सबसे अधिक कर देता है, को कई विपक्षी-शासित राज्यों के अलावा (प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना) से कोई विशेष आवंटन नहीं मिला।

यह शर्म की बात है कि केंद्र ने समानता के सिद्धांत की खुलेआम अवहेलना की है और राज्यों के बीच भेदभाव करना चुना है। महाराष्ट्र नए हवाई अड्डों, समर्पित व्यापार / स्मार्ट सिटी, राजमार्गों और सड़कों जैसे उपहार शहर की मांग करता है, लेकिन इन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। महाराष्ट्र के प्रति भाजपा की असली नफरत एक बार फिर उजागर हुई है। विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्य ने अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की आगामी बैठक का बहिष्कार करके इस भेदभाव पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। बजट में वित्त मंत्री ने 20-30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम पेश किया और भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक कंपनी को अपने सीएसआर से निर्धारित 5000 रुपये प्रति माह के वजीफे पर 20,000 प्रशिक्षुओं को काम पर रखना होगा।

इसका यह भी मतलब है कि स्नातक/स्नातकोत्तर जो रिकॉर्ड 9.2त्न बेरोजगारी दर का हिस्सा हैं और सार्थक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से संतुष्ट होना पड़ेगा, जो यह संबोधित नहीं करता है वह अत्यधिक कुशल युवाओं के लिए रोजगार या उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना है। यह कॉर्पोरेट अग्निवीर कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित करना नहीं है जो बेरोजगारी है बल्कि युवाओं की दुर्दशा का मजाक उड़ाना है। इसी तरह, वित्त मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात की, लेकिन लिंग वेतन अंतर को दूर करने, उन्हें अधिक नौकरियां दिलाने, कर छूट के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित करने या पारिवारिक बजट चलाने में मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने में मदद करने वाली कोई भी पेशकश नहीं की।

संबल एक छत्र योजना है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि शामिल हैं। 2020-21 में, जब ये योजनाएं अलग थीं, संबल के तहत शामिल केवल चार के लिए बजट अनुमान 640 करोड़ था, जो कि 24-25 के लिए बजट अनुमान में आवंटित राशि (629 करोड़ रुपये) से अधिक है।

वित्त मंत्री और पूरी सरकार राजकोषीय विवेक बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन यह एक क्लासिक मामला है कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन धैर्य खत्म हो गया, आम जनता के पास पर्याप्त बचत नहीं है, निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और उपभोग वृद्धि अब तक की सबसे कमजोर है।

तथ्य यह है कि 2023-24 में निजी अंतिम उपभोग वृद्धि केवल 4 प्रतिशत थी, जबकि कुल जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक थी, जो इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सरकार एक बार फिर किसानों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दे पाई है। यदि इंटरनेट सेवाओं को बंद करना और किसानों को विरोध करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले का उपयोग करना पर्याप्त नहीं था, तो केंद्रीय बजट में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी या छूट या कम ब्याज दरों के माध्यम से कृषि ऋण के लिए किसी भी तरह की सहायता का कोई उल्लेख नहीं है। अरबपतियों द्वारा हजारों करोड़ की शादियां करने और बेरोजगार युवाओं द्वारा नौकरियों को लेकर मोहर लगाने जैसी स्थितियों के साथ, केंद्रीय बजट बड़े पैमाने पर धन असमानता को संबोधित करने से चूक गया है।

जबकि युवाओं के रोजगार के लिए पैकेज पेश किए गए हैं, बजट में आबादी के सबसे गरीब और सबसे अमीर वर्गों के बीच की खाई को कम करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में आय में असमानता को इंगित करने के बावजूद, जिसमें शीर्ष 10 प्रतिशत की आय का एक तिहाई हिस्सा है, किसानों और मजदूरों के उत्थान या धन करों में वृद्धि के उपाय अनुपस्थित हैं। वित्त मंत्री द्वारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स घटाने की घोषणा एक तरह से धोखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स 20त्न से घटकर 12.5त्न ??हो गया है, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति, सोना और अन्य गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा और अधिक राशि पर कर लगेगा, जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ेगा और संपत्ति, सोना और शेयरों में निवेश लाभहीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना भाजपा के आवश्यक सहयोगियों को पूरा करती है।

जनता, विपक्ष और अधिकांश राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। जबकि देश के 90 प्रतिशत लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करना इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन के बाद भी इसे जारी देखना निराशाजनक है। हालांकि, कोई भी उम्मीद कर सकता है कि संसद में विपक्षी सदस्यों का बढ़ता प्रतिनिधित्व और उत्साह इस सत्र में केंद्रीय बजट में उपयोगी विचार-विमर्श और परिवर्धन का कारण बन सकता है।

आप की बात

उमर अब्दुल्ला से सवाल

उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सहयोग के बिना तो हमारे यहां अमरनाथ यात्रा तक संभव नहीं है और अमरनाथ यात्री तो मुस्लिमों के कंधों पर भी यात्रा करते हैं। ऐसे में किसी को उनका धर्म नहीं दिखाई देता है। उनकी बातें ठीक हैं, लेकिन हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि आपके राज्य में आज भी अनेक हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदारी आप जैसे कश्मीरी राजनेताओं की नहीं है? आज भी मौका मिलते ही कश्मीर में हिंदुओं व सेना के जवानों को कौन गोलियां मार कर उनकी जान ले रहा है? अक्सर आप जैसे नेता आतंकियों के बेकसूर और बेगुनाह होने की बात करते तथा पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी करते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज हिंदू-मुस्लिम संबंध भारी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कुछ मुस्लिम अपनी पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं? क्या ऐसा कर वे हिंदुओं के बिजनेसों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? जब सभी स्थानों पर नाम प्रदर्शित करना सामान्य बात है तो मुस्लिम दूकानदार अपना नाम लिखने से क्यों बचना चाहते हैं?

- **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

मोदी का निरर्थक विरोध

राष्ट्रहित और जनहित में मोदी सरकार कोई भी काम करे, विपक्ष हर वक्त उसकी आलोचना के लिए एक पांव पर खड़ा रहता है। हालांकि विपक्षियों को संवैधानिक अधिकार है कि वे सरकार की खामियों को बतायें और उसमें सुधार हेतु सुझाव दें किन्तु सदैव संसद में शोर-शराबा मचाना ही उसका उद्देश्य रहा है। इस बार संतुलित बजट आया है, पर इसके बावजूद विपक्ष इसका विरोध करते हुए बजट सत्र में बहस में भाग भी नहीं ले रहा है। इस पर राज्यसभा के उप-सभापति ने कहा है कि इस प्रकार संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करने वाला विपक्ष खुद लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। विपक्ष ने बजट पर अनेक सवाल उठाए, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देने खड़ी हुईं तो विपक्ष ने उनकी बात सुने बिना वाकआउट कर दिया। इससे लगता है कि विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसके लिए सदन, संविधान और लोकतंत्र की गरिमा उसके लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान नेताओं को बुला कर उनको ऐसे समय सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, जब सर्वोच्च न्यायालय इससे संबंधित एक मामले पर फैसला दे चुका था।

- **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

ममता की रणनीति

घुसपैठियों के माध्यम से अपना वोटबैंक बढ़ाने के ममता के कुत्सित प्रयासों में अभी भी कमी नहीं आई है। इसका ताजा प्रमाण हाल में दिया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि बंगलादेश के शरणार्थियों के लिए बंगाल के दरवाजे खुले हैं। उनका यह बयान भारत सरकार को चुनौती के साथ यह भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को अपनी निजी जागीर मानती हैं। ममता को समझना चाहिए कि किसी विदेशी को शरण देना या न देना विशुद्ध रूप से केन्द्र सरकार का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक के पीछे इतनी अंधी और स्वार्थी हो गई है कि उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए देश हित को भी ताक पर रख दिया है। ये वही ममता है जिन्होंने अटल बिहारी सरकार में देश से रोहिंग्याओं को निकालने के लिए संसद में सबसे पहले मांग की थी। लेकिन विडंबना है कि आज वे बंगाल की सीमाओं पर बंगलादेशियों के स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ लिए खड़ी हैं। देश के सभी लोगों तथा सभी राजनीतिक दलों को ममता बनर्जी की इस रणनीति का विरोध करना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि मोदी के विरोध में कुछ भी करने को तैयार विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर ली हैं।

- **नरेन्द्र टोंक,** मेरठ

जलभराव से संकट

दिल्ली के पटेल नगर में जलभराव के साथ ही गेट में करंट आने पर गाजीपुर के एक युवा की मृत्यु हो गई। इसकी गंभीरता से जांच जरूरी है। आखिर इस मौत का कौन जिम्मेदार है? जलभराव की स्थितियों में अक्सर करेंट उतर आने से खतरा और बढ़ जाता है। इस मानसूनी मौसम में दिल्ली में जलभराव की घटनायें अनेक स्थानों पर सामने आई हैं। जलभराव के कारण अनेक स्थानों पर कुल मिलाकर दो बच्चों के डूबने सहित कुल 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि, दिल्ली के उप-राज्यपाल गंभीर दिखाई देते हैं और आप सरकार की मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती हैं, लेकिन समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाता है। प्रत्येक वर्ष बारिश के दिनों में अंडरपास में पानी भर जाता है, गाड़ियां डूब जाती है और यात्रियों को आने-जाने में कठिनाई होती है। जलभराव होने पर मोटर पंप लगा कर पानी निकाल दिया जाता है लेकिन एक भारी बारिश के बाद फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। आवश्यकता है कि देश की राजधानी तथा महत्वपूर्ण आयोजनों का स्थल दिल्ली में जलभराव का स्थाई समाधान निकाला जाए।

- **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा

संवाददाता। अमेठी

थाना जगदीशपुर में हुई लूट की घटना का अनावरण करते हुए एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को वर्तमान एसओ जगदीशपुर धीरेन्द्र कुमार यादव व तत्कालीन एसओ जगदीशपुर राकेश कुमार सिंह मय हमराही व एसआई अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी मय हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त देवराज सिंह निवासी पूरे दुंदा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 44 वर्ष व शुभम मिश्रा निवासी पटना पवारा पट्टी थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 19 वर्ष को स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यूपी 32 एफआर 9006 एवं मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 सी 6683 के साथ जामो मोड़ सुल्तानपुर हाइवे के पास से समय करीब 11 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया व 1 बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया। तलाशी से अभियुक्त देवराज के कब्जे से 30 हजार रुपए, शुभम के कब्जे से 22 हजार रुपए व बाल अपचारी के कब्जे से 90 हजार रुपए बरामद हुए व बाल अपचारी के पास एक बैग से 1 स्मार्ट वाच, 1 ब्लूटूथ, ओप्पो का 1 मोबाइल फोन, 1 इयर फोन बरामद हुआ।

बताते चलें कि 22 जुलाई को थानाक्षेत्र जगदीशपुर जनपद अमेठी अन्तर्गत एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक सर्वेश कुमार शुक्ल अपने साथी/जानने वाले अनिल मिश्र पुत्र कामता प्रसाद मिश्र निवासी पूरे लबड़ी मजरे शेषपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ एसबीआई बैंक जगदीशपुर से 3,80,000 रुपये लेकर कार से जा रहे थे कि तभी रास्ते में समय करीब 05 बजे शाम को ग्राम महमदपुर व खौपुर के बीच में अनिल मिश्र व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा सर्वेश कुमार शुक्ल को चाकू से वार कर घायल अवस्था में कार से उतार कर 3,80,000 रुपये लेकर भाग गये थे ।

एआरटीओ व बीएसए कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ कार्यालय में कई जगह गंदगी पाई गई जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय परिसर में पर्याप्त साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही पत्रावलियों के रखरखाव को सुव्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा एआरटीओ कार्यालय में सभी पटल सहायकों से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली गई तथा कहा कि कार्यालय परिसर में दलाल व बिचौलियों का बोलबाला ना रहे, डीएम ने स्पष्ट कहा कि जन सामान्य के कार्य को सीधे तौर पर किया जाए उसमें किसी दलाल व बिचौलियों की संलिप्तता न रहे। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालय परिसर में पत्रावलियों के रखरखाव, साफ-सफाई की व्यवस्था को देखा तथा दिशा निर्देश दिए।

सरकारी दफ्तरों में अचानक हुई जांच के दौरान 20 अनधिकृत व्यक्ति गिरफ्तार

संवाददाता। संतकबीरनगर

जिला मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में सक्रिय अनाधिकृत व्यक्तियों एवं अवांछित तत्वों के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर के निर्देश पर एडीएम जय प्रकाश एवं अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने संयुक्त जिला अस्पताल सहित तीन सरकारी कार्यालयों पर औचक छापेमारी की जिससे कार्यालयों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कार्यालयों में अनधिकृत रूप से घूमते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस उक्त अवांछित तत्वों को गिरफ्तार करके कोतवाली ले गयी।

उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस ने बीएनएस के तहत कार्रवाई की। एडीएम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से यहां बताया कि वे मयफोर्स सबसे पहले एआरटीओ कार्यालय पहुंचे। जहां पर कार्यालय के अन्दर एवं परिसर में अनधिकृत रूप से घूमते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई लेकिन न तो किसी के पास कोई जवाब था और न ही कोई कागज था।

उन्होंने बताया कि यहां से कुल 11 लोगों को पकड़ा गया और उन्हें कोतवाली भेजवा दिया गया। इसके बाद उप निबंधक खलीलाबाद कार्यालय पर पहुंचकर छापेमारी की गई तो यहां पर भी वहीं स्थिति मिली। जिन लोगों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई वे कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। यहां पर कुल 06 लोगों को पकड़ा गया।

इस दौरान संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने काम में व्यस्त रहे। छापेमारी के दौरान यहां भी थोड़ी बहुत अफरा-तफरी का माहौल रहा। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय से होकर संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर अस्पताल के एक कक्ष में एक युवक मरीज से कुछ बात करते पकड़ा गया जिससे पूछताछ की गई तो वह भागने लगा। जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद एक और युवक को यहां पर पकड़कर पूछताछ की गई तो वह आनाकानी करने लगा और कुछ इधर-उधर की बातें करने लगा। उससे अस्पताल आने का कारण पूछा गया तो वह कुछ नहीं बता पाया।

ट्रक व डीसीएम की टक्कर में डीसीएम चालक की मौत, चार घायल

बछरावां, रायबरेली। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बछरावां मौरावा मार्ग पर ट्रक व डीसीएम की आमने-सामने टक्कर हो गई। डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत तथा चालक के परिवार में दो महिलाएं एवं दो मासूम घायल हुए हैं। घटना बृहस्पतिवार की है। बछरावां मौरावां हाईवे पर इंचौली गांव के पास डीसीएम व ट्रक की आमने-सामने से टक्कर हो गई।

हादसे में डीसीएम चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डीसीएम पर सवार उसके परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार किया गया हैस विदित हो कि सुरेश पुत्र देवी प्रसाद निवासी शुक्लागंज कानपुर डीसीएम पर पानी की बोतल का भाड़ा लादकर अयोध्या जा रहा थास अयोध्या दर्शन को लेकर उसने डीसीएम पर अपना परिवार भी बैठा लियास दोपहर में अयोध्या से वापस लौटते समय बछरावां मौरावां मार्ग पर इचौली गांव के पास मौरावां की ओर से आ रहे ट्रक से डीसीएम की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में डीसीएम चालक की घटनास्थल ही पर दर्दनाक मौत हो गई । वही उसकी पत्नी पूजा उम्र लगभग 31 वर्ष , गुनगुन उम्र लगभग 29 वर्ष पत्नी गोपुलाल , दिव्यांशी उम्र लगभग 2 वर्ष पुत्री सुरेश, आयुष उम्र 2 माह पुत्र दीपक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। जहां उनका उपचार किया गया है।

थाना अध्यक्ष ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालयों में अनुबंधित वाहनों से ही भेजें: जिलाधिकारी

- जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन

संवाददाता। संतकबीरनगर

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने जनपद में विद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे वाहनों के सम्बन्ध में विभिन्न बिंदुओं पर एआरटीओ से जानकारी लेते हुए कहा की वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए वाहनों का फिटनेस सही करा ली जाय, जितने भी अनफिट वाहन है स्कूल में उनको नोटिस दिया जाए और अगर एक हफ्ते में फिटनेस न करायें तो उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा की 15 साल से पुराने वाहन अपना पंजीयन निरस्त करायें जो की अस्तित्व विहीन हो।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि हर क्लास में एक नोडल रोड सेफ्टी कप्तान हों जो बच्चों को रोड रूल्स के बारे में जानकरी दें। 18 वर्ष से कम आयु के छात्र अपने निजी वाहन से स्कूल न आयें और उनको स्कूलों में आने की अनुमति न दी जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया की ड्राइवर और परिचालक का चरित्र सत्यापन अवश्य हो और अभिभावक इस बात को खुद भी सुनिचित करें।

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को वाहन चालक का स्वास्थ्य फिटनेस की जाच करने हेतु निर्देशित किया तथा कहा की चालक के पास वैध आईडी अवश्य हो। जिलाधिकारी ने बैठक के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों से अपील किया है कि अपने बच्चों को अनुबंधित वाहन/बस से ही विद्यालय में भेजे, अनाधिकृत रूप से चल रहे डग्गामार वाहनों अथवा टैक्सी से न भेजें। कोई भी वाहन अनाधिकृत रूप से बच्चों को न ले जाए, सारे वाहनों का स्कूलों से अनुबंध होना आवश्यक है। कोई भी वाहन अनाधिकृत रूप से बच्चों को न ले जाए, सारे वाहनों का स्कूलों से अनुबंध होना आवश्यक है।

छत से लटकता हुआ मिला सामाजिक कार्यकर्ता का शव

लालगंज, रायबरेली। कस्बे के रामलीला मैदान निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिये भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल प्रारम्भ कर दी है। बताया गया है कि कस्बे के रामलीला मैदान निवासी मो. रफीक उर्फ बबलू का शव घर की दूसरी मंजिल पर पंखे के हुक से बिजली के केबल के सहारे लटकता पाया गया। घटना के समय परिजन घर के अन्य हिस्सो में मौजूद थे। जब उन्हे इसकी जानकारी हुई तो सभी स्तब्ध रह गये। परिजनो के चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। परिजनो ने बताया कि बबलू अपनी बीमारी व अन्य घरेलू समस्याओं के चलते काफी समय से अवसाद में चल रहे थे। जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया।

प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पार्टी कार्यालय में की बैठक

अयोध्या। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, एमएलसी अवनीश पटेल ने मिल्कीपुर विधान सभा के सभी मंडल अध्यक्षों तथा प्रभारियों के साथ पार्टी कार्यालय सहादतगंज में बैठक की। बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया।

बैठक में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बूथ समिति के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लोगों से लगातार सम्पर्क व संवाद करते रहें। मंडल के पदाधिकारी शक्ति केन्द्र तथा बूथ के कार्यकताओं से समीक्षा करते रहें। विगत चुनाव में जो बूथ कमजोर थे उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मतदाता किन्हीं कारणों से नाराज हैं उनसे मंडल और जिले के पदाधिकारी सम्पर्क करें। विगत चुनाव में विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाकर चुनाव में जीत दर्ज की गई।

विपक्ष के इस झूठ के बारे में कार्यकर्ता जनता से चर्चा अवश्य करें। मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा बूथ विजय से ही चुनाव विजय होती है। विगत चुनाव में जिस प्रकार से झूठ के बल पर चुनाव को प्रभावित किया गया उसका पर्दाफाश कार्यकताओं को करना है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय कुकरगांव में डीएम ने बच्चों से किया संवाद

संवाददाता। उरई, जालौन

प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को जिलाधिकारी शासकीय योजनाओं, परियोजनाओं की हकीकत को परखने के लिए जनसुनवाई के बाद निकलते हैं। इसी क्रम में सुबह लगभग 11.30 बजे जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय कुकरगांव का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले मिडडे मील को देखा, मेन्यू के अनुसार भोजन बनाया गया था। इसके बाद कक्षा में पहुंचे यहां पर पर्यावरण विषय पर शिक्षक मोहम्मद शाहिद बच्चों को पढ़ा रहे थे।

जिलाधिकारी ने बच्चों से पूछा कि वृक्ष हमें क्या देते हैं तो सटीक जवाब बच्चों ने दिया कि आक्सीजन, वृक्षों की पत्तियों में क्या पाया जाता है तो बच्चों ने कहा कि क्लोरोफ्लि। इसके बाद उन्होंने छात्रा महक, सृष्टि अनन्या से पहाड़ा सुनाने को कहा तो छात्राओं ने पहाड़ा सुना दिया। दूसरी कक्षा में डीएम पहुंचे तो वहां पर शिक्षक बच्चों को महान व्यक्तित्व के बारे में समझा रहे थे। भगवान राम महान क्यों थे इस पर पढ़ाया जा रहा था।

जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को भगवान राम के महान होने के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। लगभग एक घंटे तक उन्होंने बच्चों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया।

बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, से दूर रहना चाहिए। बच्चे किसी भी विषय को रटें नहीं बल्कि उसको समझें और याद करें। बाद में जल संरक्षण का महत्व भी बताया। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक पाए जाने पर बीएसए चंद्रप्रकाश से कहा कि थोड़ी और मेहनत की जाए। इसके बाद उन्होंने पौधरोपण का सत्यापन किया।

पीस पार्टी ने फूलन देवी का बलिदान दिवस मनाया

संतकबीरनगर। पीस पार्टी कार्यालय पर गुरूवार को फूलन देवी का बलिदान दिवस मनाया गया। जिसमें मुख्य अतिथि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अयूब सर्जन तथा विशिष्ट अतिथि फूलन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप अरविन्द सिंह रहे। इसके साथ ही अन्य प्रदेश स्तरीय नेतागण मौजूद रहे। सभी ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजलि दी और शिक्षित संगठित होकर न्याय के लिए संघर्ष करने का आहवान किया। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अयूब सर्जन ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी ने अन्याय व अत्याचार को उखाड़ फेंकने के लिए डटकर लड़ाई लड़ी और शोषितों, वंचितों तथा पिछड़ों खासकर महिलाओं के हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम किया। वह दलितों गरीबों की आवाज थीं। उन्होंने कहा कि फूलन देवी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फूलन देवी ने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष किया।

मप्र से होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर कसी जाएगी लगाम: पुलिस अधीक्षक

उरई, जालौन। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश की सीमा से आकर अपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि जनपद जालौन की सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है ऐसे में अवैध खनन व अन्य अपराधों से जुड़े माफिया सीमा जुड़ी होने का गलत लाभ उठाने का प्रयास करते है। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा कि हिंसक घटनाओं को रोकना हमारी प्राथमिकता है। राजस्व से जुड़े हुए मामलों में उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें मजिस्ट्रेट जांच करवाई जायेगी। उसी जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। राजस्व से जुड़े हुए विषयों में उच्च न्यायलय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा व वैधानिक कार्यवाही संबंधित अधिकारी की जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरांत ही दर्ज की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रंजिशन झूठी तहरीर देकर पुलिस को गुमराह करने वालों पर भी शिकंजा कसा जायेगा। पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जायेगी। उन्होंने अपराध जैसे कृत्यों से जुड़े लोगों को चेतावनी दी कि वह शांतिपूर्ण नागरिक की तरह जीवन यापन करें। जो भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जायेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव उप्र शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने हेतु जनपद के पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र 30 सितम्बर 2024 तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताएं निर्धारित की गई है जिसमें भारत का मूल नागरिक हो। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो। गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत न दिया जा चुका हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हो, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस 5 जनवरी पर गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिसके अन्तर्गत चयनित व्यक्ति को एक लाख रूपये का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र दिये जाने की व्यवस्था है।

लो वोल्टेज व कटौती से उपभोक्ता परेशान

ऊंचाहार। लो वोल्टेज व अघोषित बिजली कटौती और बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान उपभोक्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर नारेबाजी की।और विभाग के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाये। तहसील क्षेत्र के रसूलपुर विद्युत उपकेंद्र का गुरुवार की दोपहर दर्जनों उपभोक्ताओं ने घेराव कर जमकर हंगामा काटा और विद्युत विभाग के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाये।उपभोक्ताओं का कहना है कि बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की जा रही है।लो वोल्टेज की वजह से न ही नलकूप चल रहे है और न ही घरों में लगे बिजली के उपकरण कार्य कर रहे है।उपभोक्ताओं का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसके बदलवाने के एवज में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मोटी रकम माँगी जाती है।उपभोक्ताओं ने वीडियो के माध्यम से विधायक से गुहार लगाई है।उपभोक्ताओं के हंगामे से उपकेंद्र पर मौजूद कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है।

33 करोड़ की लागत से निर्मित रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज 21 दिन में धंसा

संवाददाता। कालपी, जालौन

अति व्यस्त रोड जो दो जिला मुख्यालय उरई - हमीरपुर मार्ग में 33 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले जोल्हूपुर रेलवे क्रॉसिंग परियोजना का काम 6 वर्ष गुजर जाने के बाद हुआ पूरा जहा आये दिन जाम लगा रहता था जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी पैदा हो रही थी जिससे 6 जुलाई को वाहनों का आवागमन चालू हो गया था लेकिन अल्प समय में ही उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जोल्हूपुर मोड़-हमीरपुर फोरलेन सड़क में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए जोल्हूपुर रेलवे क्रासिंग में फोरलेन ओवरब्रिज निर्माण कार्य की मंजूरी वर्ष 2017 में मिली थी। उप्र राज्य सेतु निगम तथा रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2018 में काम शुरू कराया गया था। तीन वर्ष के अंदर कार्य पूरा होना था, लेकिन 6 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बाद काम पूरा हो गया जिससे 6 जुलाई को ओवर ब्रिज से वाहनों के निकलना शुरू हो गया था जिससे जाम से पूर्ण रूप से निजात मिल गई थी लेकिन उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिलीप, मुन्ना सिंह, जंबू सिंह, जगराम सिंह आदि ग्रामीणों ने जानकारी देते हुये उसकी गुण बत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं उनका कहना है कि मात्र बीस दिन में ही रोड केई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है को उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं ये है योगी राज।

जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश कुमार तथा अवर अभियंता आरके सचान ने क्षेत्रीय विधायक विनोद चतुर्वेदी को आश्वासन दिया था कि 31 मई 2024 के अंदर टू लेन ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो गया था तथा सभी हल्के भारी वाहन गुजरने लगे थे फ्लिहाल रेलवे के द्वारा ओवर ब्रिज में रेलिंग का कार्य चल रहा था। आश्वासन के बावजूद भी अधिकारी काम को समय से पूरा नहीं कर सके थे इसके बाद बनने के अल्प समय में ही रोड की यह दशा देखकर लोगों में जिम्मेदारों की कथनी करनी में सवाल खड़े हो गए हैं।

गैर सम्प्रदाय की लड़की भगाने में सहयोगी दो को पुलिस ने भेजा जेल

जालौन, उरई। गैर संप्रदाय के लड़के द्वारा भगाई गई लड़की के आरोपी का सहयोग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 61 (2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। आरोपियों के जेल भेजने की जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी राम सिंह कोतवाल वीरेंद्र कुमार ने बताया की 3 जुलाई को नगर की एक लड़की को गैर संप्रदाय के लड़के द्वारा भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का सहयोग करने वाले जीशान पुत्र निसार मोहल्ला नारोभास्कर व मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल निवासी नारोभास्कर को उस समय गिरफ्तार किया जब वह औरैया रोड स्थित चुंगी नंबर 4 के पास प्रताप पुरा रोड के पास खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे कोतवाल वीरेंद्र पटेल, एसएसआई शीलवंत सिंह, चौकी इंचार्ज कुलवंत, सिपाही ऋषि, तथा महिला सिपाही संध्या ने उक्त दोनों आरोपियों को घेरते हुए पकड़ लिया। और उक्त आरोपियों पर पंजीकृत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा।

संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता। उरई, जालौन

गुरुवार को संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भेंट कर उन्हें शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की 8 सूत्रीय समस्याओं का मांग पत्र सौंपते हुये उनके जल्द निराकरण कराने की मांग की। शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि उक्त समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान न किया गया तो अन्यथा की स्थिति में संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा आंदोलन को बाध्य होगा।

बीएसए को दिये गये ज्ञापन में कहा कि बीटीसी 2001, बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004, उर्दू बीटीसी 2005 एवं सभी शिक्षक, कर्मचारी जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी किया गया वह सभी शिक्षक, कर्मचारी के पुरानी पेंशन बहाली विकल्प पत्र जमा कराये जायें। ब्लाक में विकल्प पत्र जमा नहीं कराये जा रहे हैं जबकि प्रदेश के सभी जनपदों में विकल्प पत्र लिये जा रहे हैं। शिक्षकों के एक दिन के वेतन कटौती स्पष्टीकरण बगैर किसी कारण ब्लाक में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा रहे और न ही कार्यालय से उन्हें बहाल किया जा रहा है। वह कार्यालय में ही लंबित पड़े रहते हैं एक दिन के वेतन कटौती आदेश बहाल किये जायें। पूर्व में जिले के कई शिक्षकों की अस्थाई वेतन वृद्धि पत्रावली एवं प्रतिकूल प्रविष्ट पत्रावलियां लंबे समय से कार्यालय में लंबित पड़ी हैं उन्हें बहाल किया जाये।

शिक्षामित्र, अनुदेशक के उपस्थिति पत्र ब्लाकों से माह की एक निश्चित तारीख तक बीएसए कार्यालय उपलब्ध करायें जायें। ताकि उन्हें समय से मानदेय उपलब्ध हो सके। सत्र प्रारंभ के चार माह बीत जाने के बाद भी पाठ्य पुस्तकें शत प्रतिशत वितरित नहीं की गयी। कक्षा 1 व 2 में कोई भी पाठ्य पुस्तक वितरित नहीं की गयी ऐसी स्थिति में निपुण विद्यालय बनाना कहां तक संभव है अत: पाठ्य पुस्तकें प्राथमिकता से शत प्रतिशत वितरित करायी जाये। गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा कॉपी भुगतान अभी तक नहीं कराया गया उसका भुगतान तत्काल कराया जाये।

राज्यमंत्री ने की महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा दिये निर्देश

● सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध हो मूलभूत सुविधायें: राज्यमंत्री

● सैम-मैम बच्चों का चिन्हीकरण कर करायें कार्यवाही: राज्यमंत्री

● बच्चों व गर्भवती महिलाओं को समय से उपलब्ध हो पोषण आहार

राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने विभाग की सॅचालित योजनाओं की सर्किट हाउस में समीक्षा करती हुयी

कानपुर देहात। महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। राज्यमंत्री द्वारा सभी सीडीपीओ से कुपोषित बच्चों की संख्या, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थितिए नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की प्रगति व अन्य भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने सभी सीडीपीओ को अपने ब्लाक अन्तर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं/लाभों को उपलब्ध कराया जाये, उनको बेहतर शिक्षा दी जाये। सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समय से शत प्रतिशत पोषण आहार वितरण करने, सैम.मैम बच्चों के चिन्हीकरण करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीएमकेयर, वन स्टॉप सेन्टर, निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिये। उन्होंने बेटी बचाओंए बेटी पढ़ाओं योजना के अधिक से अधिक प्रचार करने के भी निर्देश दिये। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ, सुपरवाईजर, ब्लाक क्वाडिनेटर, बाल संरक्षण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

कारगिल विजय दिवस पर भाजयुमो ने निकाला मशाल जुलूस

फतेहपुर। सन् 1999 मे भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ जो कि 60 दिनो तक चलने के उपरान्त 26 जुलाई को भारत विजय के साथ समाप्त हुआ। कारगिल विजय की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व मे आम जन मानस द्वारा मसाल जुलूस का आयोजन किया गया। भारतीय जवानो के सम्मान मे वर्मा चौराहे से पटेल नगर चौराहे तक भारत माता कि जय के नारो के साथ विजय ज्योति के रुप मे मसाल जुलूस परणित किया गया। जिला अध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने बताया कि कश्मीर मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता भारत शांति पुर्ण ढंग से हल करने का घोषणा पत्र का उलंघन करते हुए पाकिस्तान ने अपने सैनिको और अर्ध सैनिक बलो को छिपा कर नियन्त्रण रेखा के पार भेजनें लगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बाद प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेई ने आपरेशन विजय के नाम से 02 लाख सैनिको को कारगिल क्षेत्र मे भेजा।

कार्यकर्ता विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें: असीम अरुण

● भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक में राज्यमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत

राज्य मंत्री का स्वागत करते सागर अग्रवाल लकी।

कन्नौज। भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक में व्यापारी बंधुओं से कल प्रस्तुत हुए बजट पर सार्थक चर्चा हुई। जिसमें पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। गुरुवार को जिला कार्यालय पर व्यवसायिक प्रकोष्ठ भाजपा की आयोजित बैठक में राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भाजपा सरकार के बजट से विकसित भारत का सपना साकार होगा। हर वर्ग एवं हर क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार चौमुखी विकास कार्य करवा रही है। आम आदमी से लेकर किसानों, नौजवानों एवं बेरोजगारों के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी सरकार के सपनों को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन प्रदेश मंत्री/सह संयोजक व्यवसायिक प्रकोष्ठ भाजपा सागर अग्रवाल लकी, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, संतोष चतुर्वेदी एवं व्यापारी नेताओं ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं दी हैं उनको कैसे जन-जन तक पहुंचाएं, इसपर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होनें कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने वाली भाजपा की नीतियों में सभी व्यापारी बंधुओं ने विश्वास जताया। इस दौरान जिला महामन्त्री संजय गुप्ता, जिला उपाध्याय आनंद गुप्ता व ऋषि यादव, नगर अध्यक्ष गौरव गोयल, अखिलेश पांडेय, धीरेंद्र गुप्ता, अंकित गुप्ता, नरेश भदौरिया सहित सैकड़ो व्यापारी गण मौजूद रहे।

सड़क के बीचोबीच खड़े विद्युत पोल से चौपहिया वाहनों का आवागमन ठप

संडीला (हरदोई)। ट्रांस्फॉर्मर रखने के लिए खड़े किए गए दो खंभे ट्रांस्फॉर्मर हटने के बाद भी सड़क के बीचोबीच यथावत खड़े हैए जिसके कारण इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर चौपहिया वाहनों का आवागमन बंद है और लोग परेशान हैं। नगर के मोहल्ला मलकाना दमादपुरवा में मोहल्ला माकूम कुआं से दादा मियां की मज़ार होते हुए सेंट थेरेसा बाईपास से जुड़ता है। इस संपर्क मार्ग पर डॉ0 फैसल के घर के निकट लगभग 50 वर्ष पूर्व विद्युत आपूर्ति के लिए दो खंभे बीच सड़क पर गाड़ कर चबूत्रा बनाया गया था। लगभग दस वर्ष पहले इस स्थान से ट्रांस्फार्मर विद्युत विभाग द्वारा हटा लिया गया और चबूत्रा तोड़ दिया गया लेकिन खंभे ज्यों के त्यों खड़े रहे। इस दौरान इस संपर्क मार्ग पर वाहनों का आवागमन इसलिए होता रहा क्योंकि इस क्षेत्र में स्व0 आबाद मियां के तालाब और खेतों के कारण वाहन किनारे होकर निकल जाते थे लेकिन

विगत 5 वर्षों में इस जगह पर भी अंधाधुंध मकान बन गए और यह संपर्क मार्ग काफ़ी सकरा हो गया। चूंकि बीचोबीच में दोनों खंभे खड़े हैं इसलिए एम्ब्यूलेंसए कारए ट्रैक्टर ट्रॉली आदि का आवामन बंद हो गया। अब स्थिति यह है कि सेंट थेरेसा बाईपास तक जाने के लिए क्षेत्र का पूरा चक्कर लगाना पड़ता हैए जिसके कारण धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। सड़क के बीचोबीच खड़े इन दोनों खंभों को लेकर नगर पालिका और विद्युत विभाग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। विद्युत विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि इन खंभों को हटाने के लिए पूरी लाइन हटानी होगी।

चेकडैम धांधली की जांच करायी जायेगी उच्चाधिकारियों से: सिचाई राज्य मंत्री

● सीडीओ ने कहा जांच टीमे पहले ही हो चुकी है गठित रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार ● अट्ठाइस चेकडैमों की प्रक्रिया हो रही है पूरी आज आवेदनों की टेक्नीकल जांच हुई झांसी में

हमीरपुर। लघु सिचाई विभाग के चेकडैम असमय ध्वस्त होने के मामले में प्रदेश सरकार के सिचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने साफ कहा है कि इस मामले की वह उच्चाधिकारियों से जांच करायेगे। वही सीडीओ ने कहा कि चेकडैम की जांच के लिये पहले ही करीब छह टीमों का गठन कर दिया गया था उनकी शीघ्र ही रिपोर्ट मांगी गयी है।

जानकारी के मुताबिक लघु सिचाई विभाग के अभियंताओ द्वारा चेकडैम के नाम पर किसानो के साथ धोखाधड़ी करने व लाखो रुपये ठिकाने लगाने का मामला अब शासन तक पहुच गया है। वही सरीला क्षेत्र के बंधौली व चंडौत गांव के मजदूरों ने बताया कि दबंग ठेकेदारों ने चेकडैम तो उनसे बनवा लिया था मगर उनकी मजदूरी आज तक नही दी है इसके लिये वह उच्चाधिकारियों से शिकायते की है मगर उसका कोई असर नही हुआ है। बंधैली के शैलेंद्र ने बताया कि वह चेकडैम में मेट था उसके साथ के कई मजदूर काम किया मगर ठेकेदार हजारो रुपये हड़प कर गया। इसी प्रकार व्रजमोहन का कहना है कि वह भी मजदूरी के लिये दर दर भटक रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चेकडैम वनाकर क्षेत्रीय किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है क्योकि किसी भी चेकडैम से आज तक सिचाई के नाम पर एक बूद पानी नही निकला है सिर्फ कागजो में ही सिचाई चलती रही है। वही सिचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद का कहना है कि मामला गंभीर है वह इस मामले की जाच करायेगे। और दोषियों को कतई बख्शा नही जायेगा ।सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि चेकडैम् की जांच के लिये पहले की टीमों का गठन किया जा चुका है मगर उनकी रिपोर्ट नही आयी है। शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट मांगी जायेगी। इसके बाद कार्यवाही की जायेगी। बही अपना दल के नेता महेंद्र राजपूत ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। कहा है कि यदि जांच करा ली जाये तो करोडो रुपये की धाधली सामने आ जायेगी। इधर विभाग मे 28 टेंडरों की प्रक्रिया चल रही है ठेकेदारो ने ई टेंडर डाल दिये है। टेक्नीकल जांच के लिये अधिशासी अभियंता गुरुवार को झांसी गये थे वहा से खानापूरी करने के बाद बाद मे वित्तीय जांच होगी इसके बाद ये सभी चेकडैम बनने शुरु हो जायेगे। जो पुराने ध्वस्त हो गये उनकी चिंता किसी को नही है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

तीन दिन से गायब किसान का शव उतराता मिला

राठ (हमीरपुर)। तीन दिन से गायब किसान का शव धसान नदी में उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मझगवां थाने के लिधौरा गांव निवासी दसइयां ने बताया कि हम उसके पिता 61 वर्षीय गोरेलाल अहिरवार 23 जुलाई को भैंस चराने के लिए गए थे। शाम को भैंस वापस आ गई। लेकिन वह घर नहीं लौटे। तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं हो सकी। बुधवार को सारा दिन ढूंढा न मिलने पर थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराई। गुरुवार सुबह गांव से 3 किलोमीटर दूर धसान नदी के किनारे उनका शव उतराते मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसने बताया कि भैंस को पानी पिलाते समय उनका पर फिसल मझगवां थानाध्यक्ष नंदलाल प्रजापति ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की जानकारी हो सकेगी।

क्विक न्यूज

तेज़ रफ़्तार कार की चपेट में आकर युवक की मौत, वृद्ध घायल

संडीला (हरदोई)। अनियंत्रित गति से आ रही एक कार ने बाइक से गिरे युवक को रौंद दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। एक वृद्ध व्यक्ति इस हादसे में घायल भी हुआ है। मल्लावां संडीला मार्ग पर सुबह यह दुर्घटना हुई। ग्राम चंदौली थाना माधवगंज निवासी 25 वर्षीय मनोज कुमार अपनी बाइक से आ रहे थे। जब वह गौसगंज के पास पहुंचे तो साइकिल से आ रहे गौसगंज निवासी अली हुसैन से उनकी बाइक टकराकर अनियंत्रित हो गयी और सड़क पर जा गिरे जबकि अली हुसैन सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी में गिरे। इसी बीच अत्यंत तेज़ गति से आ रही कार ने सड़क पर गिरे मनोज कुमार को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे वे मरणासन्न हो गए। उन्हें उठाकर लोग अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी। मृतक मनोज कुमार किसी विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत थे। साइकिल सवार अली हुसैन को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की एफ़आईआर दर्ज की गयी है। अभी तक कार का कोई पता नहीं मिला है।

वृद्ध को साड़ ने हमला कर मार डाला

राठ (हमीरपुर)। नहर बाईपास पर टहलने के लिए निकले वृद्ध को सांड ने हमला कर मार डाला। कस्बे के दीवानपुरा मोहल्ला प्रभु दयाल (80) मंगलवार की शाम करीब पांच बजे वह नहर बाईपास पर टहलने गए थे। लौटते समय अन्ना सांड ने हमला बोल दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जहां से मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया गया। जहां उनकी मौत हो गई। स्वजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं कस्बे के पठानपुरा मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय निधि पुत्री वीरेंद्र सिंह का बुधवार को जन्मदिन था। वह शाम को केक खरीदने जा रही थी। तभी सांड ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

कन्टेनर में पीछे से घुसी डीसीएम, चालक की मौत

फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी टोल प्लाजा के समीप एनएच-2 में आगे जा रहे कन्टेनर के अचानक रूकने पर पीछे से आ रही डीसीएम घुस गई। जिसमें 50 वर्षीय चालक की मौके पर मौत हो गई। बाराबंकी जनपद के थाना फतेहपुर भड़ने हवा मजरे संदूहपुर निवासी सियाराम का पुत्र दिनेश डीसीएम चालक था। बताते हैं कि बुधवार की रात आगे जा रहे कन्टेनर ने बड़ौरी टोल प्लाजा के समीप अचानक ब्रेक लगा देने पर पीछे से आ रही डीसीएम घुस गई। जिसमें दिनेश की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

सड़क पार कर रहे चालक को वाहन ने रौंदा, मौत

फतेहपुर। राजस्थान प्रांत के जिला जयपुर थाना बेवार गांव आदर्श विद्या मंदिर अजमेर रोड बाईपास निवासी रमजान अली का पुत्र अब्दुल हमीद ट्रक चालक था। थरियांव थाना क्षेत्र के उसरैना के पास ट्रक खड़ा कर उतरकर सड़क पार रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उसे रौंद दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस घायल को उपचार के लिए सदर अस्पताल ला रही थी तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।

अधेड़ ने जहर खाकर दी जान

फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी स्व. रामशंकर का पुत्र रमेश काफी दिनों से मानसिक तनाव में था। बीती शाम उसने जान देने के इरादे से जहर खा लिया। कुछ देर बाद जब उसकी हाल बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे तत्काल उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकीय उपचार के बाद हालत ठीक न होने पर उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

कूलर में उतरे करंट से युवक की मौत

फतेहपुर। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छीछा में बुधवार की शाम कूलर में उतर रहे करंट की चपेट में आ जाने से 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छीछा गांव निवासी चंद्रभान का पुत्र महेश सिंह बुधवार की शाम खाना खाकर कमरे में सोने चला गया। तभी कूलर चालू करते समय करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चौकीदार का पुत्र युवती को भगाकर ले जाने में गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। युवती को ले जाने के मामले में आरोपी चौकीदार के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए चालान कर दिया। राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी 17 वर्षीय युवती को ले जाने में ग्राम गांधी के पुत्र सकटे के पुत्र नागेश के खिलाफ मुकदमा धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने युवती को गाजीदाबाद से दबिश के दौरान बरामद किया था।

16.36 करोड़ की संपत्ति सपा नेता जग्गू यादव की कुर्क

फर्रुखाबाद। डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत सपा नेता जग्गू यादव की 16 करोड़ 36 लाख 9 हजार 497 रूपये इकसठ पैसे की अबैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। तहसीलदार सदर श्रद्धा पाण्डेय, थानाध्यक्ष मऊदरवाजा अमित गंगवार व थाना कादरी गेट के पुलिस बल के साथ गैंगेस्टर के आरोपी देवेन्द्र उर्फजग्गू यादव की सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही की गई, जिसमे बाग लकूला में लगभग 28 आवासीय प्लाट व कृषि योग्य भूमि को मुनादी कराकर कुर्क किया गया । जग्गू वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। जग्गू व उसके भाई सपा नेता योगेंद्र यादव उर्फचन्नू को पूर्व में जिला प्रशासन ने वर्ष 2017 व 2021 में जिला बदर किया था। भूमाफिया भी घोषित किया जा चुका है। कोतवाली फतेहगढ़ में 12 जून 2024 को गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। जग्गू यादव को बीते 13 जून 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

जरदोजी कारीगर की पत्नी की संदिग्ध मौत

संवाददाता। फर्रुखाबाद

जरदोजी कारीगर की पत्नी को संदिग्ध हालत में निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के स्वजनों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पंहुची लेकिन सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही। शहर कोतवाली के मोहल्ला बाग रुस्तम निवासी कासिम जरदोजी कारीगर है। उसकी पत्नी रानी की दोपहर अचानक हालत खराब हो गयी स उसका पति कासिम रानी को निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर गया जहाँ मृत घोषित कर दिया। रानी की मौत की सूचना पर उसके भाई आमिर पुत्र यामिन निवासी बंगशपुरा कोहना ने आरोप लगाया की कासिम की किसी अन्य महिला के साथ नजदीकी हैं, लिहाजा कासिम पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया ।

मृतका के दो पुत्र हैं ससूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मऊदरवाजा अमित गंगवार, शहर कोतवाल जेपी शर्मा आदि पुलिस बल के साथ पंहुचे। शहर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डेढ़ घंटे उलझा रहा सीमा विवाद थाना मऊदरवाजा व शहर कोतवाली पुलिस के बीच सीमा विवाद फंस गया। दोनों थानों की पुलिस अपने-अपने सीमा में घटना न होने की बात करती रही। बाद में सभासद नौशाद मंसूरी के लिखित देने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

एआरटीओ कार्यालय पहुंची जिलाधिकारी कर्मचारियों को लगाई फटकार

● बिचौलियों से दूर रहने की दी हिदायत, दुकानें बंद कर दलाल हुए फरार

संवाददाता। फतेहपुर

एआरटीओ ऑफिस में दलाल और बाहरी व्यक्तियों से काम कराए जाने की आ रही शिकायतों की हकीकत जानने के लिए गुरुवार को डीएम सी. इंदुमती अचानक एआरटीओ कार्यालय जा पहुंची जहां उन्होंने विधिवत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एआरटीओ को कड़ी चेतावनी देते कहा कि किसी भी हालत में बिचौलियों के माध्यम से कार्य न किए जाएं। साथ ही पटल में कोई भी बाहरी व्यक्ति काम करते नहीं मिलना चाहिए। डीएम के निरीक्षण की खबर मिलते ही दलालों ने दुकानों के शटर गिराकर फरार हो गए।

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रिकार्ड रूम, कार्यालय के पटल सहायकों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं कार्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्यालय परिसर के आसपास अवैध दुकानों एवं दलालों का मामला संज्ञान में आने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए एआरटीओ को तत्काल निर्देशित किया कि बिचौलियों के माध्यम से कोई भी कार्य न हो, जिससे आम जन मानस का कार्य सुगमता से हो। किसी भी पटल पर प्राइवेट लोगों से कार्य न कराया जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अविनाश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक धीरेन्द्र प्रताप, पुलिस क्षेत्राधिकारी, एआरटीओ प्रशासन पुष्पांजलि मित्रा गौतम, प्रवर्तन सहित संबंधित उपस्थित रहे।

दुकानों की जांच कर मांगी रिपोर्ट: निरीक्षण के दौरान डीएम ने एआरटीओ को निर्देश दिया किया कि कार्यालय परिसर के आसपास जितनी भी दुकाने संचालित है, उनकी गम्भीरता के साथ जांच कराएं। स्पष्ट किया कि जांच कराते हुए तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं यह भी निर्देश दिए कि कार्यालय में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं, उनका सूचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण हो।

नये रिकार्ड रूम के लिए निर्देश: निरीक्षण के दौरान डीएम को रिकॉर्ड रूम में पर्याप्त जगह न पाए पर उन्होंने नया रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर पत्राचार करते हुए संबंधित रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए। कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का परमिट, रजिस्ट्रेशन, वाहनों का फिटनेस, बीमा आदि का कार्य समय से किया जाए।

अगस्त से कानपुर सेण्ट्रल-अलीगढ़ फास्ट मेमू चलेगी

● रूरा व झींझक में होगा ठहराव

● यात्रियों में नई मेमू के सॅचालन पर हर्ष की लहर

संवाददाता। कानपुर देहात

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सौगात प्रदान करते हुये 1 अगस्त से कानपुर सेण्ट्रल-अलीगढ मेमू फास्ट ट्रेन के सॅचालन की घोषणा की है। जनपद के रूरा व झींझक स्टेशन पर ही ठहराव होने पर यात्रियों में इस नई ट्रेन के सॅचालन पर हर्ष की लहर दौड गयी है। जनसम्पर्क कार्यालय उ0म0रे0 प्रयागराज द्वारा वुधवार को जारी विज्ञप्ति में 04189/04190 कानपुर-अलीगढ फास्ट मेमू विशेष गाडी(अनारक्षित) के सॅचालन का निर्णय लिया गया है, यह विशेष फास्ट मेमू 1 अगस्त को कानपुर सेण्ट्रल से सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर अलीगढ के लिये रवाना होगी, जनपद के रूरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 7 बजकर 54 मिनट पर आयेगी, झींझक में यह विशेष ट्रेन 8 बजकर 14 मिनट पर आकर रूकेगी, कानपुर से चलने के बाद यह ट्रेन पनकी धाम, रूरा, झींझक,फफूँद, भरथना, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूँडला, हाथरस के बाद अलीगढ 12 बजकर 40 मिनट पर पहुँचेगी, वापसी में यह विशेष मेमू अलीगढ से दोपहर एक बजकर चालीस मिनट पर कानपुर के लिये

रेलवे प्रशासन द्वारा नई गाडी के सॅचालन की समय सारिणी

रवाना होगी, झींझक स्टेशन पर 5 बजकर 50 मिनट पर, रूरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 6 बजकर 11 मिनट पर आयेगी, कानपुर सेण्ट्रल पर यह ट्रेन शाम को 7 बजकर 45 मिनट पर पहुँचेगी। इस विशेष ट्रेन के सॅचालन से भारी सॅख्या में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा की उम्मीद जतायी जा रही है। 8 डिब्बों की यह ट्रेन 31 जनवरी तक 158 फेरे लगायेगी। इस यात्रीगाडी के सॅचालन की घोषणा पर रूरा चैयरमैन रामजी गुप्ता, व्यापारी नेता श्याम मोहन दुबे, आशीष गुप्ता मोनू, सरदार गुरमीत सिंह, शैलेन्द्र तिवारी, झींझक चैयरमैन सोनू तिवारी, रवीन्द्र शुक्ला भोले, अजय शुक्ला, राघवेन्द्र शुक्ला सहित अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है।

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के अस्वस्थ होने से छाई मायूसी

गुरसहायगंज (कन्नौज)। नगर के मोहल्ला रामगंज निवासी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर का विगत दिन पूर्व अचानक स्वास्थ्य बिगडनें से उनके समर्थकों व शुभचिंतकों में मायूसी दिखाई दे रही है। वहीं विद्यायिका पुत्र एवं समर्थकों ने लखनऊ स्थित हास्पिटल पहुंचकर हाल जाना। बताते चलें कि बीते मंगलवार की सुवह पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर की अचानक तबीयत बिगड गयी।

परिजनों नें आनन फानन में नगर के एक निजी चिकित्सक के यहां दिखाया जहां स्वास्थ्य लाभ न होनें पर लखनऊ स्थित मेदांता हास्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनके स्वास्थ्य लाभ में निरंतर सुधार हो रहा है। ज्ञात हो कि पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर नें अपनी मृदुभाषिता व लोकप्रियता के सहयोग से जनपद में समाज के लोगों को भाजपा के पक्ष में लामबन्द करनें में सफलता हासिल

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर का फाईल फोटो।

करनें का कार्य किया है। उनकी तबीयत बिगडनें की खबर पर विद्यायिका पुत्र एवं राहुल राठौर, शशांक वर्मा, रानू ठाकुर, अशोक चौरसिया, मोनू वर्मा सहित नागरिकों नें लखनऊ स्थित मेदांता हास्पिटल पहुंचकर उनके हाल लिये। साथ ही उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

शिक्षामित्रों ने श्रद्धांजलि सभा कर निकाला कैंडल मार्च

● मांगों पर विचार न हुआ तो 05 सितंबर को लखनऊ में होगा धरना प्रदर्शन

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने दिवंगत शिक्षामित्र साथियों को जहां भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल तक कैंडिल मार्च निकाला। बैठक करके शिक्षामित्रों ने समस्याओं पर चर्चा करते हुए अपने हक व अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सभी का हौसला बढ़ाया। जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी के नेतृत्व में नहर कालोनी के सामने स्थित एक गेस्ट हाउस में में शिक्षामित्र एकत्र हुए। सर्वप्रथम शिक्षामित्रों ने दिवंगत साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, जिस पर तमाम शिक्षामित्रों ने मौत को गले लगाया। तब से लेकर अब

तक लगभग 12000 शिक्षामित्रों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है, तब से अब तक हजारों शिक्षामित्र आर्थिक तंगी का सामना करते हुए मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। फिर भी 2017 से अब तक सरकार ने शिक्षामित्र की कोई सुधि नहीं ली। जिला महामंत्री रवीन्द्र प्रकाश पटेल ने बताया कि शिक्षामित्र संघ ने तमाम आंदोलन किए, कई बार शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा को भी रखा। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी अपनी पीड़ा से अवगत कराया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा एवं जिला संयुक्त मंत्री ओम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगर मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी पांच सितंबर को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए हम सब बाध्य होंगे। इस मौके पर अदीप सिंह, अजय सिंह, अनूप तिवारी, आशुतोष द्विवेदी, माया, रेनू, सुचिता पांडेय, राजेश सिंह, शैलेन्द्र वर्मा, मीनू सिंह, सुनील मिश्रा, ओम पटेल, आशुतोष द्विवेदी, अखिलेश गुप्ता, सर्वेश चन्द्र मिश्र, भानु प्रताप सिंह, अनिल श्रीवास्तव, कैलाश, आशीष पटेल, विशाल शुक्ला, शैलेन्द्र सिंह, विष्णु दुबे, संतोष यादव उपस्थित रहे।

नीट परीक्षा की शुचिता में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नीट-यूजी, 2024 के पूरे परिणाम में गड़बड़ी हुई थी और परीक्षा की शुचिता में प्रणालीगत उल्लंघन हुआ। शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को विवादों में घिरी परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा दोबारा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था और आदेश बुधवार रात को अपलोड किया गया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए 14 पृष्ठ के अंतिम आदेश में कहा गया, वर्तमान चरण में, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के पूरे परिणाम में गड़बड़ी हुई है या परीक्षा की शुचिता में कोई प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। करीब 40 याचिकाओं पर विस्तृत और तर्कपूर्ण फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा, शहर-वार और केंद्र-वार जो डेटा पेश किया गया है और वर्ष 2022, 2023 और 2024 के डेटा की तुलना से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रश्नपत्र प्रणालीगत रूप से लीक हुआ है और इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। पीठ ने कहा कि इस वर्ष दोबारा परीक्षा कराने का आदेश परीक्षा में शामिल हुए 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणामों से भरा होगा। आदेश में कहा गया कि इस तरह की कार्वाई से प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, पूरी प्रक्रिया कई महीनों के लिए पीछे चली जाएगी तथा इसका मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पीठ ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता को भी प्रभावित करेगा और हाशिए पर पड़े समुदायों तथा कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भौतिक विज्ञान के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए आईआईटी दिल्ली के तीन विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुझाए गए उत्तर को सही मानते हुए अपनी मेरिट सूची को संशोधित करने के लिए भी कहा। इसने इस बात की पड़ताल की कि क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ था और क्या उल्लंघन ऐसी प्रकृति का था जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित हुई। इसने यह भी पड़ताल की कि क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। पहले के निर्णयों के अनुसार, यदि धोखाधड़ी के लाभार्थियों को वास्तविक सफल अभ्यर्थियों से अलग करना संभव नहीं है, तो पुन: परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस विवाद को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी, जिसने 20 लाख से अधिक छात्रों के करियर को प्रभावित किया। आदेश में कहा गया, यह तथ्य कि नीट (यूजी) 2024 का पेपर झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में लीक हुआ, विवाद का विषय नहीं है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि जांच जारी है और अब तक की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के अनुसार, हजारीबाग तथा पटना के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले लगभग 155 छात्र प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के लाभार्थी हैं। पीठ ने दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस बात के सुस्थापित परीक्षण से निर्देशित है कि क्या दागी छात्रों को उन छात्रों से अलग करना संभव है जो बेदाग हैं। इसने कहा, यदि जांच में वर्तमान चरण में संदिग्धों के अलावा लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या की संलिप्तता का पता चलता है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी चरण में गलत काम में संलिप्त पाए जाने वाले प्रत्येक छात्र के खिलाफ कार्वाई की जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि कोई भी छात्र, जिसके बारे में यह पता चलता है कि उसने धोखाधड़ी की है, इस निर्णय के आधार पर भविष्य में प्रवेश जारी रखने के लिए निहित अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। न्यायालय ने केन्द्र के इस कथन पर गौर किया कि उसने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। पीठ ने कहा, समिति इस न्यायालय द्वारा अपने अंतिम निर्णय और आदेश में जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगी, जो उन क्षेत्रों के संबंध में हों, जिनकी उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (1)नीट (यूजी) और एनटीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया को उचित रूप से मजबूत किया जाए और (2) वर्तमान वर्ष के दौरान सामने आए मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। परीक्षा की शुचिता पर संदेह तब पैदा हुआ जब कुल 67 छात्रों ने एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के एक केंद्र से छह छात्र शामिल थे। एनटीए द्वारा एक जुलाई को संशोधित परिणामों की घोषणा के बाद शीर्ष रैंक साझा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) दी थी।

सीयूईटी-यूजी परीक्षा की अंतिम कुंजी जारी नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे : एनटीए

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बृहस्पतिवार को संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-स्नातक (सीयूईटी-यूजी) की अंतिम कुंजी जारी कर दी। इसी के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। एनटीए ने सात जुलाई को सीयूईटी-यूजी 2024 की वैकल्पिक कुंजी जारी की थी जबकि करीब एक हजार विद्यार्थियों की शिकायत वाजिब होने पर उनकी दोबारा परीक्षा 19 जुलाई को ली गई।

एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अंतिम कुंजी जारी कर दी गई है और परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर जारी हंगामे की वजह से सीयूईटी-यूजी 2024 के परिणाम घोषित करने मे देरी हुई है।

सीयूईटी के परिणाम पहले 30 जून को घोषित किए जाने थे लेकिन एनटीए ने नीट-यूजी, यूजीसी-नेट और सीएसआईआर-यूजीसी-नेट में कथित अनियमितता एवं प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की वजह से एनटीए ने नतीजे घोषित करने में देरी की। सीयूईटी-यूजी के तहत 15 विषयों की परीक्षा कलम-कागज के माध्यम से हुई जबकि अन्य 48 विषयों के लिए परीक्षा कंप्यूटर माध्यम से हुई। इस साल 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा के लिए 13.4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

नीट पर न्यायालय का फैसला कांग्रेस की ओछी राजनीति की हार : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला छात्रों की हार नहीं बल्कि कांग्रेस के गैरजिम्मेदाराना रवैए और ओछी राजनीति की हार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पर्चा लीक और भ्रष्टाचार की जनक है। प्रधान ने एक्स पर लिखा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि परीक्षा की शुचिता में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं पाया गया है। कांग्रेस को भारत सरकार पर तो नहीं पर कम से कम माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है? नीट मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला विद्यार्थियों की हार नहीं कांग्रेस के गैरजिम्मेदाराना रवैए, कुतर्क और ओछी राजनीति की हार है।

शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से राजस्थान में जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब हुए पेपर लीक को लेकर सवाल किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए, कहा, राजस्थान में भाजपा सरकार आने से पूर्व खटा-खट हुए पेपर लीक क्या खरगे जी के संज्ञान में नहीं हैं? अपनी सरकार में हुए पेपर लीक पर खरगे जी ने मुंह में दही क्यों जमा रखी थी। कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जनक है।

प्रधान ने कहा, देश की जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार नकारा है। लगातार तीसरी बार हार कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। राजनीतिक रोटियां सेकने और तेजी से फिसलती हुई अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस के पास झूठ, आधा सच और अराजकता एकमात्र सहारा है। नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विवादों से भरी इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी शुचिता के व्यवस्थागत उल्लंघन के कारण यह दूषित हुई है।

यह फैसला राजग सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के लिए राहत की बात है, जो पांच मई को आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे बड़े पैमाने पर कदाचार के आरोप में सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे। प्रधान ने आरोप लगाया, खरगे जी, ना तो आपको, ना आपके नेता राहुल गांधी, ना आपकी पार्टी को विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता है। आपको केवल अपने और एक परिवार के भविष्य की चिंता है।

कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, रासुका के तहत सांसद को जेल में रखना आपातकाल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि एक निर्वाचित सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में रखा जाना अघोषित आपातकाल है जिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा कि चन्नी जेल में बंद चरमपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे थे और इससे साबित होता है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग 1975 के आपातकाल की बात करते हैं लेकिन इस समय देश में आर्थिक आपातकाल और अघोषित आपातकाल लगा है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा, यह आपातकाल ही है कि पंजाब में 20 लाख मतदाताओं द्वारा निर्वाचित एक संसद सदस्य को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध रखा गया है। वह यहां अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रख सकते। यह भी आपातकाल है।

चन्नी ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद खडूर साहिब लोकसभा से निर्वाचित हुए अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद के अंदर दिए गए कांग्रेस सांसद चन्नी के बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने पीटीआई वीडियो से कहा, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानियों को आज चन्नी से खुला समर्थन मिला। इसका मतलब है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। यह भारत की अखंडता पर हमला है। मेरा कहना है कि कार्वाई होनी चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या पार्टी खालिस्तान के विचार का समर्थन करती है जिस विचार की वजह से 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन क्यों करती है? याकूब, अफजल, 26111 के जिहादी और अब के आतंकवादी? भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने चन्नी को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की। उन्होंने पीटीआई वीडियो से कहा, आज चन्नी, जिनकी चवन्नी की हैसियत नहीं है, आतंकवादियों के समर्थन में बोल रहे हैं और उन्हें महिमामंडित कर रहे हैं। वह कनाडा से राष्ट्र-विरोधी तत्वों के इशारे पर काम कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा में विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा

विपक्षी सदस्यों ने नीतीश कुमार सरकार में अविश्वास जताया

पटना। बिहार विधानसभा में बृहस्पतिवार को उस समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ सरकार में अविश्वास व्यक्त करते हुए सदन के बीचों-बीच समानांतर कार्यवाही संचालित करने का प्रयास किया। एक दिन पहले सदन के भीतर महिला विधायकों के प्रति मुख्यमंत्री के अपमानजनक व्यवहार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए विधानसभा तक मार्च निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को विपक्षी महिला विधायक काली पट्टी बांधे हुई थीं। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने प्रश्नकाल चलाने का फैसला किया और कर्मचारियों के लिए रखे गए फर्नीचर को पलटने की कोशिश कर रहे विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा, ए विधानसभा के कर्मचारी हैं। यदि आपके कृत्यों के कारण कोई घायल होता है, तो मैं कड़ी कार्वाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। सदन के बीचों-बीच बैठे विपक्षी सदस्यों ने भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम को कुर्सी पर बैठाया गया और उन्हें सदन का अध्यक्ष कहकर संबोधित करते हुए समानांतर कार्यवाही संचालित करने का असफल प्रयास किया।

प्रश्नकाल समाप्त होने तक विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच डटे रहे लेकिन बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है और वे सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कई स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा, यह अजीब बात है कि जिन लोगों ने ए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उन्होंने सदन में उपस्थित रहने की भी जहमत नहीं उठाई। विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति के बीच शून्यकाल का संचालन किए जाने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी।

इस बीच, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में भी महिला विधायकों के प्रति मुख्यमंत्री के व्यवहार का मुद्दा विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाया गया, जिसके कारण आज की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद सभापति अवधेश कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बिहार विधान परिषद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री और उनके करीबी सहयोगी एवं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार का आरोप है कि विपक्ष की महिला विधायकों को कुछ भी पता नहीं है या वे कुछ भी नहीं समझती हैं। ललन मुझ पर बजट को समझने में असमर्थ होने का आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि मैं किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, इन दोनों नेताओं को ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। भोजनावकाश के बाद भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही शाम चार बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पूर्व मंत्री और राजद नेता कुमार सर्वजीत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया, "22 जुलाई को सत्र के शुरू होने के बाद से विपक्ष के विधायकों को एक मिनट भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वह विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरना दे रहे विपक्षी सदस्यों में शामिल थे। बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्षी सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया, "अध्यक्ष कुछ सदस्यों को उनकी बारी से इतर बोलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। जब उनकी बारी आई तो वे (विपक्षी सदस्य) हंगामा करते हुए सदन से बाहर चले गए।

झारखंड के दो विधायक दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए

रांची। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया। यह आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आया। झामुमो और भाजपा ने क्रमश: हेम्ब्रोम और पटेल के खिलाफ दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी। हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी। पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वह हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े थे। दोनों ही हालांकि चुनाव हार गए थे।

संथाल परगना, अररिया, किशनगंज, कटिहार सहित कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए: सांसद

भाषा। नई दिल्ली

भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना और बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने तथा हिंदुओं के गांव खाली होने का दावा करते हुए सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने कहा कि साल 2000 में बिहार से झारखंड के अलग होने के समय संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 36 प्रतिशत थी जो आज 26 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 10 प्रतिशत आदिवासी कहां खो गए, कहां गायब हो गए। सदन कभी इसकी चिंता नहीं करता। झारखंड की सरकार भी कोई कार्वाई नहीं करती।

दुबे ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके क्षेत्र में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। उन्होंने कहा, हिंदू, मुसलमान का सवाल नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा में 267 बूथ पर मुसलमानों की आबादी 117 प्रतिशत बढ़ गई। पूरे झारखंड में 25 विधानसभाओं मे मुस्लिम आबादी 110 से 123 प्रतिशत तक बढ़ी है।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड के पांकुर में पिछले दिनों दंगा हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और माल्दा से आए लोगों ने तथा बंगाल पुलिस ने स्थानीय हिंदुओं को भगाया। उन्होंने कहा, हिंदुओं के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड यह बात कह रहा हूं। एक भी बात गलत है तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। दुबे ने कहा कि बंगाल से आए लोगों ने जुल्म किया और झारखंड पुलिस ने कोई कार्वाई नहीं की।

उन्होंने कहा कि इन सब घटनाक्रम को देखते हुए झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के माल्दा और मुर्शिदाबाद तथा बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बना देना चाहिए और यहां राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू की जानी चाहिए, अन्यथा यहां से हिंदू खाली हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इससे भी पहले सदन की एक समिति क्षेत्र में भेजी जाए जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्यों को रखा जाए। दुबे ने यह दावा भी किया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल में एक आदेश में कहा है कि उक्त क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि विधि आयोग की 2010 की 235वीं रिपोर्ट को लागू किया जाए जिसमें सिफारिश की गई है कि धर्मांतरण और दूसरे धर्म के लोगों से शादी के लिए अनुमति जरूरी है।

एनएचएआई के सामने कोई वित्तीय संकट नहीं: नितिन गडकरी

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा और उसने टोल राजस्व आदि के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी जिन्होंने पूछा था कि क्या एनएचएआई भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। गडकरी ने कहा, एनएचएआई किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनएचएआई ने 15,700 करोड़ रुपए के बैंक ऋण का पूर्व भुगतान इनविट मुद्रीकरण प्राप्ति के माध्यम से कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई का ऋण 3.35 लाख करोड़ रुपए है।

गडकरी ने कहा कि सरकार ने एनएचएआई को वित्त वर्ष 2023-24 से धन जुटाने के लिए अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस प्रकार ऋण में कमी शुरू हो गई है। गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने टोल राजस्व और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बेहतर प्रवाह के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने के लिए एक योजना तैयार की है। उन्होंने कहा, इनविट मोड के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग केवल ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) म्यूचुअल फंड के स्वरूप वाली सामूहिक निवेश योजना है, जिसमें निवेशक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश कर पाते हैं।

पेज 1 का शेष

पीएम का दौरा...

15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

ममता...

एक सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हमें बांग्लादेश की ओर से ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है। यह अनिवार्य रूप से रिपोर्टों में वर्णित तर्ज पर है। उन्होंने कहा, मैं यह रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची - सूची एक - संघ सूची - आइटम 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो संघ को किसी भी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, एकमात्र विशेषाधिकार हैं केंद्र सरकार।

बलिया...

अजय कुमार पाण्डेय, वीरेन्द्र सिंह यादव, अरविन्द्र यादव, उमाशंकर चौधरी, जवाहिर यादव, धर्मेन्द्र यादव, विकास राय, हरेन्द्र यादव, सलाम अंसारी, आनन्द कुमार ठाकुर और दिलीप कुमार यादव को भी गिरफ्तार किया। डीआईजी ने बताया कि दलालों का अपराध करने का तरीका यह था कि बक्सर से आने वाले ट्रकों से पूर्व से सुनियोजित ढंग से बात तय कर लेते थे कि कितने बजे स कितने बजे तक यह ट्रक उप्र के थाना नरही क्षेत्र से गुजरेंगे एवं बलिया में इन ट्रकों के प्रवेश करते ही प्रत्येक ट्रक से करीब 500 रुपए वसूला जाता था। एक रात्रि में ही अनुमानित 1000 ट्रक बक्सर से बलिया में प्रवेश करते थे। इस प्रकार एक रात्रि में ही इन संगठित गैंग के द्वारा अनुमानित पांच लाख रुपए का अवैध धनोपार्जन किया जाता था, जिसे स्थानीय पुलिस एवं दलालों में बांटा जाता था। दलालों से 37360 रुपए, 14 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइल एवं 2 नोट बुक बरामद हुए हैं। इन दो नोट बुक में विगत रात्रि एवं उससे पूर्व के कई दिन एवं रात्रियों में पास कराए गए ट्रकों का विवरण अंकित है। इस विवरण से सूचना विकसित कर इस संगठित गिरोह द्वारा किए जा रहे इस अवैध वसूली के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उसके हिसाब से पैसा थानाध्यक्ष नरही को देते थे, यह भी तथ्य संज्ञान में आया है। बलिया के नरही थाना क्षेत्र के भरौली तिराहे से कुछ ट्रक थाना नरही के ही कोरण्टाडीह चौकी होते हुए जनपद गाजीपुर में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ ट्रक रसड़ा थाना क्षेत्र की तरफ चले जाते है एवं कुछ ट्रक नरही से फेफना होते हुए बलिया चले जाते हैं। गिरफ्तार आरक्षी हरिदयाल सिंह तैनाती नरही थाना जनपद बलिया की मौके पर की गयी पूछ-ताछ में यह बात भी प्रकाश में आयी कि जो ट्रक भरौली तिराहे से थाना नरही के कोरण्टाडीह चौकी होते हुए गाजीपुर जाते हैं, उनसे चौकी कोरण्टाडीह के सामने भी उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा कुछ दलालों के माध्यम से संगठित रुप से अवैध वसूली की जाती थी। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए एडीजी और डीआईजी द्वारा द्वारा भरौली तिराहा से एक ट्रक में बैठकर चौकी कोरण्टाडीह जाया गया, तो चौकी कोरण्टाडीह के सामने ही स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध वसूली करते स्थानीय पुलिस के एक सिपाही सतीश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया एवं एक प्राइवेट व्यक्ति अशोक मौके से फरार हो गया। यह प्राइवेट व्यक्ति चौकी इन्चार्ज कोरंटाडीह का निजी कार्यकर्ता था।

बजट पर...

जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। विपक्षी सदस्यों के विरोध पर बिड़ला ने कहा कि सदन और संसदीय परंपरा का बहुत सम्मान है। रिजिजू ने कहा कि बुधवार को बजट पर शुरू हुई चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने बजट पर कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ राजनीति में लगे रहे। रिजिजू ने कहा, उन्होंने लोगों के जनादेश का अपमान किया है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को गाली दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को सदस्यों को निर्देश देना चाहिए कि वे संसद में हंगामा न करें और बजट सत्र के दौरान सभ्य और संवेदनशील बहस करें। बिरला ने अपनी ओर से कहा कि सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें सदन का सम्मान और गरिमा भी सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे।

राज्यों के पास...

रॉयल्टी वह भुगतान है जो उपयोगकर्ता पक्ष बौद्धिक संपदा या अचल संपत्ति परिसंपत्ति के मालिक को देता है। प्रविष्टि 49 के अंतर्गत, राज्यों को भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार है, जबकि प्रविष्टि 50 राज्यों को खनिज विकास पर कर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन यह खनिज विकास से संबंधित संसद द्वारा कानून के तहत लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन है।प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 राज्य को खदानों एवं खनिजों पर कर लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। पीठ ने कहा, एमएमडीआर अधिनियम में राज्य की कर लगाने की शक्तियों पर सीमाएं लगाने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। एमएमडीआरए के तहत रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है।

तकनीक...

और साक्षात्कारों के साथ-साथ प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) सहित सालाना 14 परीक्षाएं आयोजित करता है। 2023 में, 1.01 मिलियन से अधिक लोगों ने सीएसई के लिए आवेदन किया था, जिसमें लगभग 590,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। सीएसई भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का कार्य करता है।

उप्र पुलिस...

सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की निशुल्क बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 एक जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

रील बनाने...

यह एक सतत प्रक्रिया है और जितना अधिक आप इसे करते रहेंगे, उतना ही लोग हतोत्साहित होंगे। कुमार ने कहा, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास हर एक कोने की जांच करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। अगर मेट्रो में प्रतिदिन 67 लाख यात्री सफर करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है। हमारे पास सीसीटीवी है, जिसके माध्यम से हम परिसर में कुछ भी होने पर पता लगा सकते हैं। डीएमआरसी ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर भी लगाए हैं, जिनमें यात्रियों से रील न बनाने और दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न न करने को कहा गया है।

राष्ट्रपति भवन...

बयान के अनुसार, अशोक शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सभी कष्टों से मुक्त या किसी भी दुख से रहित है तथा इसके अलावा, अशोक का तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। बयान में कहा गया, भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। इसके अनुसार, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। मंडप भाषा में एकरूपता लाता है और अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बरकरार रखते हुए अंग्रेजीकरण की संस्कृति के निशान को मिटाता है। हॉल का उपयोग विदेशी देशों के मिशन के प्रमुखों द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत करने और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राजकीय भोज की शुरुआत से पहले आने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए परिचय के औपचारिक स्थान के रूप में किया जाता है।

कठुआ हमले में आतंकियों के दो मददगार गिरफ्तार

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले में संलिप्तता के लिए आतंकवादियों के दो कथित मददगारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी गतिविधियों से निपटने को लेकर जारी प्रयासों के तहत आतंकियों के दो मददगारों को गिरफ्तार किया है। जिले के दूरस्थ मछेड़ी इलाके में हथियार बंद आतंकवादियों द्वारा आठ जुलाई को घात लगाकर किए गए हमले में एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित सेना के पांच जवान शहीद हुए थे और पांच अन्य लोग घायल हुए थे। प्रवक्ता ने बताया, इन व्यक्तियों ने पुलिस से महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर छिपाई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बिलावर के कलना धानू परोल के रहने वाले लायाकत अली उर्फ पावू और मल्हार के बौली मोहल्ला के रहने वाले मूल राज उर्फ जेनजू के रूप में हुई है। प्रवक्ता के अनुसार, दोनों ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।उन्होंने बताया कि मल्हार थाने में अली और राज के खिलाफ और इग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षिका की भूमिका में आईं नजर

बच्चों से ग्लोबल वार्मिंग रोकने पर किया संवाद

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कार्य करते हुए दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवसर वह शिक्षिका की भूमिका में नजर आईं और विद्यार्थियों से ग्लोबल वार्मिंग और इसे रोकने के तरीकों पर संवाद किया। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया और उन्हें अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा सके। कक्षा के 53 विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात करूं क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

संवाद की शुरुआत में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से उनकी अभिलाषा और पसंदीदा विषयों के बारे में पूछा तथा यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि विद्यार्थी वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने को इच्छुक हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, पूरी दुनिया में वैज्ञानिक, जनता, प्रशासक और शासक बहुत बड़ी समस्या पर संगोष्ठी, सम्मेलन और सभा कर रहे हैंअ क्या आप जानते हैं वह समस्या क्या है? इस पर तुरंत विद्यार्थियों ने जवाब दिया, जलवायु परिवर्तन , ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि छह ऋतुएं होती हैं लेकिन हम केवल चार महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, इन चारों में से सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। दिन-ब-दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों, पक्षियों और पेड़ों पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश के कई हिस्से सूखे की मार झेल रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा, बच्चे यह भी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमें और पेड़ लगाने चाहिए। हमें पानी की बर्बादी को रोकने और उसके संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। हमें वर्षाजल को जमा करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरत से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि और अधिक पेड़ लगाने, जंगलों को बचाने और वायु प्रदूषण कम करने की जरूरत है तभी हम भविष्य मे इसे (ग्लोबल वार्मिंग) रोकने में सक्षम होंगे। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू एक पेड़ मां के नाम पहल का जिक्र करते हुए विद्यार्थियों से अपने जन्मदिन पर भी पेड़ लगाने को कहा। उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में आपके साथ संवाद कर खुशी हो रही है।मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग के असर के बारे में सचेत हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप बड़े होंगे तब ग्लोबल वार्मिंग निश्चित तौर पर कम होगी। ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने से पहले मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर भी आसीन थीं।

उत्तराखंड में बनेगा चारधाम डैशबोर्ड

देहरादून। उतराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बृहस्पतिवार को कहा कि चारधाम यात्रा के प्रभावी प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में जल्द ही डैशबोर्ड बनाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा तैयार किए जा रहे चारधाम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए रतूड़ी ने कहा कि डैशबोर्ड चारधाम से संबंधित सभी विभागों के मध्य सूचनाओं के प्रभावी आदान प्रदान व डेटा साझा करने का माध्यम बनेगा जिससे विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित होगा। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चारधाम डैशबोर्ड में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र), स्लिपिंग जोन (फिसलन वाले क्षेत्र), मुख्य मार्गों के अलावा वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें मलबे, भूस्खलन या यातायात जाम से बाधित सड़कों, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े अनिवार्य रूप से अपडेट किए जाएं तथा धामों में खराब मौसम या अन्य कारणों से हैली सेवा रद्द होने की पूर्व जानकारी अनिवार्य रूप से अपडेट की जाए। इसके अलावा, उन्होंने पशुपालन विभाग को चारधाम डैशबोर्ड में यात्रा मार्ग पर खच्चरों के लिए चारे, पीने के गर्म पानी, पशुचिकित्सकों की उपलब्धता की जानकारी भी नियमित रूप से अपडेट करने की हिदायत दी।

केंद्र का प्रस्ताव : इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरा, मेरठ से वीडियो कांफ्रेंस से करे सुनवाई

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कुछ मामलों की मेरठ और आगरा से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करने का प्रस्ताव भेजा है तथा उसे उम्मीद है कि इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। कानून एवं विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी पीठ मेरठ और आगरा में स्थापित हो, यह विषय लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ई-कोर्ट प्रोजेक्ट-तृतीय के माध्यम से ऐसा प्रयास कर रही है।

मेघवाल ने कहा, हमने (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के) मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ सुनवाई मेरठ से की जा सकती है, आगरा से की जा सकती है। उसका (पत्र का) जवाब अभी आया नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सकारात्मक उत्तर आने की संभावना है। मेघवाल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सरकार से जानना चाहा कि सरकार जब सर्किट बेंच या क्षेत्रीय पीठ बनाने पर विचार करेगी तो क्या वह देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ बनाने पर विचार करेगी? उन्होंने यह भी पूरक प्रश्न किया था कि क्या सरकार उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष और 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने पर विचार करेगी, वेतन एवं भत्तों के साथ? एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार निर्धारित प्रारूप में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। मेघवाल ने बताया कि 2018 से नियुक्त उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में से 21 अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं, 12 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, 78 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 499 सामान्य श्रेणी के हैं।

संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे की अवहेलना करता है केंद्रीय बजट: सांसद

नई दिल्ली (भाषा)। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान है और इसमें संघीय गणराज्य के ढांचे की अवहेलना की गई है।

भदौरिया ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, बजट में संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सरकार को बचाने का समर्थन मूल्य चुकाया गया है। उन्होंने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किए गए सहायता प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बजट को अंग्रेजी की वर्णमाला के केवल दो शुरुआती अक्षरों ए (आंध्र प्रदेश) और बी (बिहार) तक सीमित रखा गया है और अन्य अक्षरों यानी देश के अन्य प्रदेशों की अनदेखी की गई है। भदौरिया ने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सांसदों की सिफारिश पर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए जाने चाहिए। भाकपा (माले) के राजाराम सिंह ने बजट को किसानों, गरीबों और युवाओं का विरोधी बताया और कहा कि इसमें लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश का उल्लंघन किया गया है उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से थी, लेकिन इस सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। सिंह ने कहा कि बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान निकालने और गरीबी को मिटाने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल द्रमुक के सी एन अन्नादुरई ने बजट को लोकतंत्र-विरोधी बताया। कांग्रेस के शशिकांत सेंथिल ने कहा कि यह बजट केवल दो राज्यों के लिए प्रेमपत्र की तरह है, लेकिन यह वास्तविक प्यार नहीं है। उन्होंने बजट में तमिलनाडु की पूरी तरह अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट में मनरेगा का आवंटन कम कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने कहा कि वह बजट से निराश हैं, क्योंकि इसमें गरीबों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।

चूक का अहसास करने में सरकार को लगभग पांच दशक लग गए

संघ से जुड़े मामले में मप्र उच्च न्यायालय

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को अपनी इस चूक का अहसास करने में करीब पांच दशक लग गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरीखे विश्वप्रसिद्ध संगठन को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत तरह से शामिल किया गया था। अदालत ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के सरकार के हालिया फैसले के हवाले से यह तल्ख टिप्पणी की। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का निपटारा करते यह टिप्पणी की। गुप्ता ने 19 सितंबर 2023 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के साथ ही केंद्र सरकार के उन कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी थी जो संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने में बाधा बन रहे थे। पीठ ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय को निर्देश भी दिया कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर नौ जुलाई के उस कार्यालय ज्ञापन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाई गई है। अदालत ने इस ज्ञापन को देश भर में केंद्र सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों को 15 दिन के भीतर भेजने का निर्देश भी दिया। इंदौर में रहने वाले याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने पीटीआई-भाषा से कहा, मैं संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले से जाहिर तौर पर खुश हूं। मेरे पिता संघ की शाखा में जाते थे और सेवानिवृत्ति के बाद मैं भी संघ की गतिविधियों से जुड़ना चाह रहा था।गुप्ता ने बताया कि वह केंद्रीय भण्डारण निगम के अधिकारी के पद से 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा,"अब मेरे जैसे हजारों लोगों के लिए संघ से जुड़ने की राह आसान हो गई है।

राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया

नई दिल्ली (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को बताया कि प्रस्तावित नए युगे युगीन भारत संग्रहालय में न केवल राष्ट्रीय संग्रहालय बल्कि भारत के अन्य संग्रहालयों की कलाकृतियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।जनपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की वर्तमान इमारत के भविष्य के बारे में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मौजूदा इमारत पर निर्णय लिया जाना बाकी है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जवाहर सरकार ने यह लिखित सवाल पूछा था। उन्होंने सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय संग्रहालय को गिराकर केंद्रीय सचिवालय की साझा इमारतें बनाने के फैसले पर सरकार का वर्तमान नजरिया क्या है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई सभी प्राचीन वस्तुओं को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय में स्थानांतरित किया जा रहा है या उनका सिर्फ एक हिस्सा स्थानांतरित करने की योजना है।केंद्रीय मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय संग्रहालय की मौजूदा इमारत के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, प्रस्तावित संग्रहालय में न केवल राष्ट्रीय संग्रहालय बल्कि भारत के अन्य संग्रहालयों की कलाकृतियां भी शामिल किए जाने की संभावना है। तृणमूल सदस्य ने यह भी पूछा कि क्या सरकार या राष्ट्रीय संग्रहालय ने प्रस्तावित नए संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय की खातिर परामर्श परियोजना के लिए पेरिस के लौवर संग्रहालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं या ऐसी कोई बातचीत की है।

शेखावत ने कहा कि यह मंत्रालय दोनों देशों के बीच 2020 में हस्ताक्षरित आशय पत्र के आधार पर फ्रांस के संग्रहालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा, इस संबंध में मसौदा मंत्रिमंडल नोट पर अंतर-मंत्रालई परामर्श किया जा रहा है। एक बार पूरा होने के बाद, इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्तावित युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में आठ विषयगत खंड होंगे जो 5,000 वर्षों की भारत की कहानी प्रदर्शित करेगा। माना जा रहा है कि बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।एक अन्य सवाल में उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार को हाल में खोजी गई औपनिवेशिक काल की उस फाइल की जानकारी है जिसमें ब्रिटेन के शाही खजाने में मौजूद भारतीय आभूषणों का ब्योरा है, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ी वस्तुएं भी शामिल हैं।

वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी लौटने को तैयार नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी परिवार पुनर्वास योजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उइके ने कांग्रेस सदस्य फूलो देवी नेताम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी परिवारों की पहचान के लिए पड़ोसी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में सर्वेक्षण के वास्ते दलों का गठन किया था। उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद के कारण सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों से 2,389 परिवारों के कुल 10,489 आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं। सुकमा से 9,702अ बीजापुर से 579 और दंतेवाड़ा से 208 लोग विस्थापित हुए हैं। मंत्री ने कहा,"प्रभावित परिवार राज्य सरकार की पुनर्वास योजनाओं की जानकारी देने और सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उपलब्ध सुरक्षा के बावजूद अपने मूल गांवोंस्थान पर लौटने को तैयार नहीं हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जुलाई 2019 में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को 13 दिसंबर, 2005 से पहले वामपंथी उग्रवाद के कारण विस्थापित आदिवासी लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा था, ताकि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

सरकार ने अनचाहे कॉल, संदेशों पर अंकुश के मसौदे पर टिप्पणियां देने की समय-सीमा आठ अगस्त तक बढ़ाई

नई दिल्ली(भाषा)। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रचार-प्रसार संबंधी फोन कॉल और एसएमएस जैसे अनचाहे एवं अवांछित कारोबारी संचार पर लगाम लगाने से संबंधित दिशानिर्देशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर बृहस्पतिवार को आठ अगस्त कर दी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न महासंघों, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर तारीख बढ़ाई गई है। इस पहले टिप्पणियां प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी।

मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न सुझाव तथा टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर फिलहाल गौर किया जा रहा है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और नियामकों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए इन दिशानिर्देशों में व्यक्तिगत संचार को नहीं रखा गया है। इसमें कारोबारी संचार को प्रचार तथा सेवा संदेशों जैसी वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित किसी भी संचार के रूप में परिभाषित किया गया है। ए दिशानिर्देश कारोबारी संचार से जुड़े सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे। दिशानिर्देशों के मसौदे के मुताबिक, व्यक्ति की रजामंदी या पंजीकृत प्राथमिकताओं का ध्यान न रखने वाला कोई भी कारोबारी संचार अनचाहे और अवांछित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा अपंजीकृत नंबर या एसएमएस हेडर का उपयोग करना, कॉल न आने का विकल्प चुनने के बावजूद कॉल करना, डिजिटल सहमति न लेना, कॉल करने वाले और उद्देश्य की पहचान न करना और सहमति बंद करने का विकल्प न देने जैसी स्थितियां भी अनचाही और अवांछित कारोबारी संचार की श्रेणी में रखी जाएंगी। इनमें ऐसे संचार पर भी रोक लगाने का प्रावधान है जो ग्राहक वरीयताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के 2018 के नियम पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) पर पंजीकरण असरदार रहा है।

विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत ने उप्र सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली। (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। अंसारी ने उस मामले में जमानत का अनुरोध किया है जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न लोगों को जबरन वसूली के लिए धमकाया। अंसारी की पत्नी चित्रकूट जिला जेल में बंद अपने पति अंसारी से मुलाकात के लिए जाती थी। मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के एक मई के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फरवरी 2023 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंसारी की पत्नी औपचारिकताओं और निर्धारित पाबंदियों का पालन किए बिना अक्सर जेल में उनसे मिलने जाती थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह आरोप लगाया गया था कि अंसारी ने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और जबरन वसूली के लिए विभिन्न लोगों को धमकाया। यह भी आरोप लगाया गया कि अंसारी की पत्नी का चालक जेल अधिकारियों की मदद से जेल से अंसारी के भागने की साजिश रच रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंसारी की याचिका बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। शीर्ष अदालत ने अंसारी की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा और इस पर सुनवाई दो सप्ताह बाद करना निर्धारित किया। अब्बास अंसारी गैंगस्टर-नेता और कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अंसारी, विधानसभा के सदस्य होने के नाते एक जिम्मेदार पद पर हैं और उनका आचरण उच्च स्तर का होना चाहिए।

कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को संस्कृत का श्लोक पढ़ने से रोकने के आरोप में प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज

गुना (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्य के खिलाफ विद्यार्थियों को संस्कृत का श्लोक पढ़ने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने इस मामले में माफी मांग ली है। उन्होंने बताया कि कथित घटना 15 जुलाई को वंदना कॉन्वेंट स्कूल में सुबह की सभा के दौरान हुई, जब तीन विद्यार्थियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखमया का पाठ किया। आरोप है कि प्रधानाचार्य सिस्टर कैथरीन ने उनसे माइक छीन लिया और कहा कि स्कूल में ऐसे श्लोक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में घटना का विवरण दिया गया है। दो दिन बाद कथित घटना के बारे में पता चलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने स्कूल में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। एबीवीपी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि उनके आग्रह पर सिस्टर कैथरीन वहां पहुंचीं और इस मुद्दे पर माफी मांगी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानाचार्य ने कहा कि वह दिन केवल अंग्रेजी में बातचीत के लिए आरक्षित था और इसीलिए विद्यार्थियों को रोका गया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानाचार्य ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और अगर उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो उन्हें खेद है। अधिकारी ने बताया कि माफी मांगने के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और उन्हें हटाने की मांग करते रहे तथा वे दो घंटे से अधिक समय तक परिसर में रहे और मांग की कि स्कूल में रोजाना श्लोक का पाठ किया जाए। अधिकारी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) चंद्र शेखर सिसोदिया भी स्कूल पहुंचे और आश्वासन दिया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग से मुलाकात की

● एलएसी का पूर्ण सम्मान करने की जरूरत बताई

भाषा। वियनतियान (लाओस)

लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यहां अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तथा पिछले समझौतों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस महीने दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की।

जयशंकर ने यहां आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वांग से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, सीपीसी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना) पोलित ब्यूरो सदस्य और (चीन के) विदेश मंत्री वांग ई से आज वियनतियान में मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंबित होगी। दोनों के बीच वार्ता पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद जारी रहने के बीच हुई जो मई में अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर गया।

जयशंकर ने कहा, वापसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता पर सहमति बनी। एलएसी और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें वर्तमान मुद्दों पर उद्देश्य और तत्परता की भावना का रुख रखना चाहिए।

दोनों नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। भारत का कहना है कि जब तक सीमा क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध है तथा सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, हालांकि दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हटे हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था।

अलास्का के नजदीक रूस और चीन के बमवर्षक विमान देखे गएः उत्तर अमेरिकी एरोस्पेस कमान

बीजिंग। चीन और रूस के लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम चार बमवर्षक विमानों को अलास्का के नजदीक अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के ऊपर उड़ते देखा गया, जिसके जवाब में अमेरिका तथा कनाडा ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। अमेरिका एवं कनाडा की संयुक्त एरोस्पेस कमान ने एक बयान में यह जानकारी दी। रूस और चीन दोनों के दो-दो विमान थे। नार्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमान (एनओआरएडी) ने कहा कि चीन और रूस की सैन्य गतिविधि को खतरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। चीन और रूस ने बृहस्पतिवार को पुष्टि की कि उसने रूस को अलास्का से अलग करने वाले बेरिंग सागर के ऊपर संयुक्त रूप से हवाई गश्त की। कमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, एनओआरएडी उत्तरी अमेरिका के नजदीक प्रतिद्वंद्वी गतिविधियों की लगातार निगरानी करेगा।

जयशंकर ने आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की

वियनतियाने (लाओस)। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने बृहस्पतिवार को आसियान बैठक से इतर फिलीपीन के अपने समकक्षों एनरिक एम मनालो और नार्वे के एस्पेन बार्थ इडे से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद - प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। जयशंकर ने तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री बेंडिटो फ्रेटास और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सोक चेंदा सोफिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। जयशंकर और अन्य सभी नेता इस समय लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस) की राजधानी वियनतियाने में आसियान ढांचे के तहत आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं।

जयशंकर की दक्षिणी पूर्वी एशियाई समकक्षों के साथ बातचीत मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीति पर केंद्रित रही जबकि उन्होंने नार्वे के नेता के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा की। नार्वे के विदेशमंत्री के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, आज एस्पेन बार्थ इडे से मुलाकात अच्छी रही। भारत और नार्वे की स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार में साझेदारी जारी रहेगी। दोनों देशों की बेहतरी के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते (ईएफटीए) को क्रियान्वित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भू राजनीति स्थिति पर भी चर्चा हुई।

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि वह अपने मित्र फिलीपीन के एनरिक ए मनालो से मिलकर खुश हैं। उन्होंने कहा, दोनों लोकतंत्रों के बीच मजबूत होते हमारे सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी, विशेष रूप से कानून के शासन और आसियान की प्रमुखता बनाए रखने पर चर्चा की। फ्रेटास से मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, आसियान बैठक से इतर तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री बेंडिटो फ्रेटास से मुलाकात कर प्रसन्नता हुई। हमारी दिल्ली (भारत की राजधानी) से दिली (तिमोर लेस्ते की राजधानी) की दोस्ती विविधतापूर्ण और गहरी होनी जारी रहेगी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा प्राथमिकताओं पर एक दूसरे से अपने-अपने विचार साझा किए।

विदेश मंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा, कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सोक चेंडा सोफिया से मिलकर खुशी हुई। हवाई संपर्क, रक्षा और विरासत संरक्षण सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर गौर किया। इसे और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा से पहले नई दिल्ली में कहा कि जयशंकर की लाओस यात्रा इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि इस वर्ष भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा हो रहा है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में नौवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की थी।

कमला हैरिस शासन करने के योग्य नहीं : डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश में शासन करने के योग्य नहीं हैं। हैरिस के संभावित उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी पर यह तीखा हमला किया। राष्ट्रपति जो बाइडन (81) ने बीते सप्ताहांत में राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस लिए जाने के बाद कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया था।

हैरिस (59) अब संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की सबसे उदार निर्वाचित राजनीतिज्ञ हैं। वह एक अति-उदारवादी राजनीतिज्ञ हैं। वह बर्नी सैंडर्स से भी ज्यादा उदार हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने आरोप लगाया, अगर वह कभी सत्ता में आईं तो वह इस देश को बहुत तेज़ी से नष्ट कर देंगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हैरिस सीमा की सरदार थीं, लेकिन वह कभी सीमा पर नहीं गईं। ट्रंप ने कहा, अगर कमला आपसे जो बाइडन की मानसिक अक्षमता के बारे में इतनी बेशर्मी से झूठ बोलेंगी, तो वह आपसे किसी भी चीज़ के बारे में झूठ बोल सकती है। उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कुटिल जो बाइडन की तरह ही कमला हैरिस भी नेतृत्व करने के लिए अयोग्य हैं। वह एक साल में हमारे देश को नष्ट कर देंगी। उन्होंने कहा, इस नवंबर में अमेरिकी लोग उनसे कहेंगे, बहुत हो गया कमला, अब शुक्रिया। आपने बहुत खराब काम किया है। आपने जो भी किया है, उसमें आपका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। आप अति-उदारवादी हैं। हम आपको यहां नहीं चाहते।

मोदी की रूस यात्रा के समय को लेकर निराश अमेरिकाः अमेरिकी अधिकारी

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऐसे समय रूस की यात्रा करने को लेकर अमेरिका निराश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यहां नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। यह बात अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन सांसदों से कही, जिन्होंने भारत-रूस के बढ़ते संबंधों को लेकर चिंता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा की थी। यह यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से मोदी की पहली रूस यात्रा थी। भारत ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की अभी तक निंदा नहीं की है और लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान की वकालत की है।

दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने मंगलवार को यहां संसदीय बैठक में अमेरिकी सांसदों से कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा के प्रतीकवाद और समय को लेकर हमारी निराशा के बारे में आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हम अपने भारतीय मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं उस यात्रा के संदर्भ पर कुछ प्रकाश डालूं तो संभव है कि आप कुछ आश्वस्त हों। मॉस्को जाने से दो सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। लू ने कहा कि मॉस्को में रहने के दौरान मोदी ने क्या किया, इस पर अमेरिका सावधानीपूर्वक गौर कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने कोई नया बड़ा रक्षा सौदा नहीं देखा। हमने प्रौद्योगिकी सहयोग पर कोई बड़ी चर्चा नहीं देखी। इसके अलावा, आपने देखा होगा कि मोदी ने पुतिन के सामने टेलीविजन पर सीधे प्रसारण में कहा था कि यूक्रेन में युद्ध को युद्ध के मैदान में नहीं जीता जा सकता और युद्ध में बच्चों की मौत को देखकर उन्हें कितना दर्द हुआ था।

लू ने कहा, यह परोक्ष तौर पर कीव में बच्चों के अस्पताल पर बमबारी का संदर्भ है, जो उनके वहां रहने के दौरान हुआ था। महोदय, मैं इस यात्रा के बारे में आपकी चिंता को समझता हूं और हम उन चिंताओं को सीधे भारतीयों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। भारतीयों ने पिछले ढाई सालों में अरबों डॉलर की रक्षा खरीद को रद्द कर दिया है क्योंकि रूस अब आपूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं।

लू आठ जुलाई को कीव के ओहमाटडाइट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल पर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे, जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल दागी थीं। इस हमले में अस्पताल में भर्ती दो लोगों सहित कम से कम 42 लोग मारे गए थे। लू भारत और भारतीय अमेरिकियों के कॉकस के पूर्व सह-अध्यक्ष सांसद जो विल्सन के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और प्रशंसा करता हूं, को मॉस्को में युद्ध अपराधी पुतिन को गले लगाते हुए देखकर हैरान और दुखी हुआ, वह भी ठीक उसी दिन जब पुतिन ने यूक्रेन के कीव में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर जानबूझकर मिसाइलें दागी थीं।

रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे हीरो हैं, मैं उनसे नई दिल्ली में मिल चुका हूं, अमेरिकी संसद को संबोधित करने के लिए दो बार उनका स्वागत कर चुका हूं। साथ ही, मैं साउथ कैरोलाइना की गवर्नर निक्की हेली के साथ मैडिसन स्क्वायर गार्डन और न्यूयॉर्क शहर में मौजूद रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ था। ह्यूस्टन, टेक्सास में 40,000 लोग मौजूद थे और यह कुछ ऐसा था जिसे मैं जानता हूं। यह दुनिया के इतिहास में करोड़पतियों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। नौ जुलाई को पुतिन के साथ अपनी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और शांति प्रयास बम और गोलियों के बीच सफल नहीं होते। भारत रूस के साथ अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दृढ़ता से बचाव करता रहा है।

नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिला

काठमांडू। नेपाल में एक दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और यह जांच टीम को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दुर्घटना में एक बच्चे सहित 18 लोग मारे गए थे। सौर्य एयरलाइंस का पोखरा जा रहा बॉम्बार्डियर सीआरजे-200 विमान बुधवार को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। घटना में विमान में सवार 18 लोगों की मौत हो गई और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में चालक दल के दो सदस्य, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी और चार वर्षीय एक लड़के सहित तीन लोगों का परिवार शामिल है। नागर विमानन प्राधिकरण के उपमहानिदेशक हंस राज पांडे ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और आवश्यक कार्वाई के लिए जांच टीम को सौंप दिया गया है। जांच टीम का नेतृत्व नागर विमानन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक रतीश चंद्र लाल कर रहे हैं और इसमें चार अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम को 45 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट और सिफारिश सौंपनी हैं। पांडे ने बताया कि शवों का पोस्टमॉर्टम करने के बाद उनकी पहचान की जा रही है और शुक्रवार तक शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति कैप्टन मनीष राज शाक्य काठमांडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के सूत्रों ने कहा, वह आईसीयू (गहन चिकित्सा कक्ष) में भर्ती हैं, लेकिन वह बोल पा रहे हैं। संबंधित विमान नियमित रखरखाव कार्य के लिए पोखरा जा रहा था लेकिन यह हादसे का शिकार हो गया।

चमत्कारिक रूप से बची पायलट की जान

काठमांडू। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में एक मात्र जिंदा बचा व्यक्ति विमान के पायलट कैप्टन मनीष राज शाक्य हैं जो विमान में आग लगने से पहले चमत्कारिक रूप से कॉकपिट के अलग होने से सुरक्षित निकलने में सक्षम हुए। मीडिया में बृहस्पतिवार को छपी खबरों में यह जानकारी दी गई। नेपाल में उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 18 लोगों की मौत हो गई। सौर्य एयरलाइंस के बॉम्बार्डियर सीआरजे-200 विमान में बुधवार को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आग लग गई। इसमें दो चालक दल के सदस्य, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी और एक बच्चा और उसकी मां सहित 19 लोग सवार थे। विमान ने नियमित मरम्मत सेवा के लिए पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। अधिकारियों ने बताया कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन ने उपचार के दौरान दम तोड़ा।

हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जब विमान रनवे से फिसलकर कंटेनर से टकराया तो कॉकपिट का अगला हिस्सा उसमें फंस गया जबकि विमान का बाकी हिस्सा जमीन के दूसरी ओर जाकर गिर गया। टीआईए सुरक्षा कार्यालय के प्रमुख और उप महानिरीक्षक राम दत्त जोशी ने बताया कि कैप्टन शाक्य (37) को हवाई अड्डा परिसर के भीतर मौजूद कंटनेर से बचाया गया। द राइजिंग नेपाल अखबार ने डीआईजी जोशी को उद्धृत किया, हमने कंटेनर के अंदर से कैप्टन शाक्य को बचा लिया। उन्होंने बताया कि चिकित्सक उनके दिमाग में लगी चोटों की जांच कर रहे हैं। इस समय काठमांडू चिकित्सा महाविद्यालय (केएमसी) में उनका इलाज चल रहा है।

घायल शाक्य का उपचार कर रहे चिकित्सकों के मुताबिक उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट और रीढ़ की हड्डी के दो स्थानों से टूटने से गंभीर खतरा नहीं है लेकिन उनके दिमाग में लगी चोटों की जांच की जा रही है। न्यूरोसर्जन डॉ.अमित थापा ने बताया कि वह शाक्य के दिमाग की एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। चिकित्सकों ने बताया कि कैप्टन शाक्य की सेहत में बुधवार के मुकाबले बृहस्पतिवार को सुधार देखने को मिला। उन्होंने बताया कि वह खतरे से बाहर हैं और बातचीत कर सकते हैं। वह तरल भोजन ले रहे हैं। केएमसी के सूत्रों ने बताया कि कैप्टन शाक्य आग से झुलसे नहीं है लेकिन उन्हें कई अंदुरुनी चोटें आई हैं और चिकित्सक उनकी टूटी हड्डियों की सर्जरी करने की तैयारी कर रहे हैं। विमान हादसे में मारे गए 18 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेपाल सरकार ने बृहस्पतिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।

बाइडन और कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे नेतन्याहू

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन से बहुप्रतिक्षित मुलाकात करने के लिए बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एवं मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी होने की संभावना है। इन तीनों नेताओं की मुलाकात को दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के 2020 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद नेतन्याहू पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं। नेतन्याहू का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब नौ महीने से गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध को बंद करने का रास्ता निकालने के लिए उन पर दबाव बढ़ रहा है। इस युद्ध में गाजा के 39 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि अब भी हमास के कब्जे में कई इजराइली बंधक मौजूद हैं।

बाइडन इजराइल और हमास के बीच संघर्षविराम होने और गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को तीन चरण में रिहा कराने के समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि वार्ता अंतिम चरण में है और कुछ मुद्दे बचे हैं जिनका समाधान किया जाना है। नेतन्याहू बाइडन से मुलाकात करने के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे।

आप आधिकारिक तौर पर ईरान के हाथों की कठपुतली बन चुके हैंः नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों से कहा

वाशिंगटन। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के खिलाफ कुछ संगठनों को आर्थिक सहायता और समर्थन देने के लिए ईरान की बुधवार को आलोचना की और कहा कि कट्टर दुश्मनों को हराने के लिए साहस और स्पष्टता दोनों की जरुरत होती है। नेतन्याहू के संबोधन का हजारों लोगों ने विरोध करते हुए देश की राजधानी वाशिंगटन में मार्च किया। नेतन्याहू ने कहा, हम सब जानते हैं कि ईरान इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को आर्थिक मदद दे रहा है, ए प्रदर्शन इस इमारत के बाहर भी हो रहे हैं ए बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं और पूरे शहर में हैं। खैर, मेरे पास इन प्रदर्शनकारियों के लिए एक संदेश है कि तेहरान के जो तानाशाह समलैंगिक व्यक्तियों को क्रेन से लटका देते हैं और अपने बाल न ढकने पर महिलाओं की हत्या कर देते हैं, वही अब आपको बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी पैसों से मदद कर रहे हैं। आप उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में अपने चौथे संबोधन के दौरान इजराइली प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया के देशों में आतंकवाद, अशांति, अराजकता और हत्या के पीछे ईरान का ही हाथ है। अमेरिकी संसद में बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन किसी भी विदेशी नेता द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा संबोधन है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का मानना है कि अमेरिका को सही मायने में चुनौती देने के लिए उसे पहले पश्चिम एशिया पर कब्जा करना होगा और इसके लिए वह हूती विद्रोहियों, हिज्बुल्ला और हमास सहित अपने कई छद्म संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल की जीत निकट है।

पाक अहमदियों के खिलाफ भेदभाव एवं हिंसा समाप्त करेः विशेषज्ञ

एजेंसी। लाहौर

संयुक्त राष्ट्र समर्थित स्वतंत्र विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के खिलाफ बढ़ते भेदभाव एवं हिंसा पर चिंता जताई और अधिकारियों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ए विशेषज्ञ मानवाधिकार परिषद के अधीन काम करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से नहीं बोलते हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि अहमदियों के प्रति भेदभाव और हिंसा की रिपोर्ट से उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता चला। अहमदी लोग मिर्जा गुलाम अहमद के अनुयाई हैं, जिन्होंने एक इस्लामी मसीहाई आंदोलन शुरू किया था जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। विशेषज्ञों ने कहा, हम पाकिस्तान के अधिकारियों से अपील करते हैं कि तत्काल स्थिति का समाधान करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में हुई दो घटनाओं का उल्लेख किया जिनमें अहमदिया समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उस समय कहा था कि उसने हमलावरों को गिरफ्तार किया है। विशेषज्ञों ने विज्ञप्ति में अहमदिया समुदाय के लोगों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने और उन्हें उनके धार्मिक उत्सवों में शामिल होने से रोकने के आरोपों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, अहमदिया को अधिकार है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का अनुपालन करें और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की संसद ने 1974 में अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया। तब से ही उन्हें लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अहमदिया के खिलाफ हिंसा एवं भेदभाव की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों द्वारा निंदा की जा रही है।

सभी धार्मिक समुदायों के सदस्यों से समान व्यवहार के महत्व पर भारत के साथ बातचीत जारीः अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि उसने सभी धार्मिक समुदायों के सदस्यों से समान व्यवहार के महत्व पर भारत के साथ चर्चा की है। कुछ राज्यों के ढाबा, होटल मालिकों को अपने भोजनालयों में नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करने संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा, हमने ऐसी खबरें देखी हैं। हमने उन खबरों को भी देखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई को उन निर्देशों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। मिलर ने कहा, इसलिए, वे (निर्देश) वास्तव में अब प्रभावी नहीं हैं। सामान्य तौर पर, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, दुनिया में कहीं भी सभी धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और सम्मान देने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। हमने सभी धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है।

अमेरिका बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी की संभावना से चिंतित हैः अधिकारी

वाशिंगटन। अमेरिका बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी की संभावना से चिंतित है। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने मंगलवार को संसदीय सत्र के दौरान सांसदों से कहा, हम बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी की संभावना से चिंतित हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बांग्लादेशी लोग इस मामले में बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे और वो इसे लेकर काफी सावधान हैं। सांसद बिल कीटिंग ने पूछा, रूस के संदर्भ में, बांग्लादेश में उस क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में, क्या आपने इस संबंध में कोई चिंताजनक बातें देखी हैं।

लू ने सवाल के जवाब में कहा, "मैं कहूंगा कि बांग्लादेश में सबसे प्रभावशाली देश वास्तव में रूस या चीन नहीं, बल्कि भारत है और बांग्लादेश एवं पूरे व्यापक क्षेत्र में हमारी नीतियों के बारे में भारत के साथ हमारी सक्रिय बातचीत होती है। सांसद यंग किम ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और ए देश अमेरिका के रणनीतिक साझेदार भारत के पड़ोसी हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की उपस्थिति भारतीय सीमा के साथ-साथ भारतीय महासागर में भी बढ़ रही है। सहायता और सहयोग न केवल दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि उनकी समृद्धि को बढ़ाने और क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहायक विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच यह बहुत तनावपूर्ण समय है। हमें उम्मीद है कि शांति बहाल होगी। मैं बांग्लादेश के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हूं। हम इस संकट को हल करने के लिए और शांतिपूर्ण तरीका खोजने के वास्ते उनके संपर्क में बने हुए हैं।

श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख फोंसेका ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की

कोलंबो। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख और लिट्टे के सफाए के लिए सैन्य अभियान के सूत्रधार फील्ड मार्शल सरथ फोंसेका ने औपचारिक रूप से आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की बृहस्पतिवार घोषणा की और भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का संकल्प जताया। देश में राष्ट्रपति चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। फोंसेका (73) ने एक एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं श्रीलंका के लोगों के सामने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करना चाहता हूं। 76 वर्षों से हम एक अयोग्य राजनीतिक समूह के नेतृत्व में हैं जिसने हमें दिवालियापन की ओर धकेल दिया है। श्रीलंका को विकसित करने के लिए हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। हमें आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। फोंसेका ने कहा, यह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मेरी औपचारिक और आधिकारिक घोषणा है। तमिल देश बनाने के लिए लिट्टे के अलगाववादी अभियान को परास्त किया था। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में महिंदा राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। फोंसेका ने कहा कि वह सभी श्रीलंकाई लोगों को देश को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ने को लेकर आमंत्रित कर रहे हैं।

चीन हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा हैः अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन। अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने दावा किया है कि चीन हिंद महासागर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रहा है, जिससे अमेरिका और दक्षिण एशिया में उसके मित्र देशों और सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी संसद में मंगलवार को सत्र के दौरान महिला सांसद यंग किम ने कहा कि वैश्विक व्यापार के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण मार्ग है जहां 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार और 40 प्रतिशत विश्व व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। विदेश मामलों की समिति में हिंद-प्रशांत के मुद्दों से संबंधित उपसमिति की अध्यक्ष यंग ने मंगलवार को कहा, हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को नहीं भूल सकते। अमेरिकी सांसद यंग किम ने कहा कि दक्षिण एशिया अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किम ने कहा कि इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, जिससे अमेरिका के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) हिंद महासागर में महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा कर रही है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रही है। हाल के वर्षों में हमने पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन के बंदरगाहों, जिबूती में सैन्य प्रतिष्ठानों और मालदीव के बुनियादी ढांचे में चीन के निवेश को देखा है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों तथा क्षेत्र में हमारे मित्रों और सहयोगियों के लिए खतरा बन रहा है। किम ने कहा, पिछले महीने मेरी उपसमिति ने हिंद-प्रशांत बजट, दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान जलडमरूमध्य पर चीन के आक्रमक रुख पर चर्चा की थी। सीसीपी भारत की नियंत्रण रेखा पर सीमा संघर्ष को भी बढ़ा रहा है और इसकी पनडुब्बियां और युद्धपोत नियमित रूप से हिंद महासागर में आवागमन कर रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संसाधन-समृद्ध दक्षिण चीन सागर को व्यापक रूप से वैश्विक संघर्ष के लिए संभावित केंद्र बिंदु के रूप में देखा जाता है। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं।

चीन ने प्रमुख नीतिगत दर और बैंक जमा पर ब्याज में की कटौती

बैंकॉक। चीन ने प्रमुख नीतिगत दर और बैंक जमा पर ब्याज में कटौती करके अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह कदम वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के बीच उठाया गया है, जिससे चीनी बाजारों में नुकसान बढ़ गया है। दोपहर तक हांगकांग का हैंगसेंग 1.4 प्रतिशत तथा शंघाई कम्पोजिट सूचकांक 0.4 प्रतिशत नीचे आ गया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने एक साल के मध्यम अवधि के पॉलिसी लोन के लिए ऋण दर में 20 आधार अंकों की कटौती करके इसे 2.3 प्रतिशत कर दिया है। सात-दिन के ऋण पर ब्याज दर घटाकर 1.7 प्रतिशत कर दी गई है। प्रमुख सरकारी बैंकों ने अपने वित्त पर दबाव कम करने के लिए जमा दरों में कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने इस सप्ताह की शुरुआत में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अन्य ऋण दरों में कटौती की थी।

अंकिता व्यक्तिगत स्पर्धा में 11वें स्थान पर, महिला टीम क्वार्टरफाइनल में

पेरिस। (भाषा)

पदार्पण कर रही तीरंदाज अंकिता भकत ने बृहस्पतिवार को यहां अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए पेरिस ओलंपिक महिला व्यक्तिगत रिकर्व क्वालीफिकेशन में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ 11वां स्थान हासिल किया, इससे देश ने चौथे स्थान पर रहकर टीम स्पर्धा में क्वार्टरफाइनल स्थान हासिल किया। अंकिता (26 साल) 666 अंक से भारतीय महिला तीरंदाजों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर रहीं, उनके बाद भजन कौर 559 अंक से 22वें और दीपिका कुमारी 658 अंक से 23वें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में भारत ने 1983 अंक से चौथा स्थान हासिल किया जिसमें दक्षिण कोरिया 2046 अंक से शीर्ष पर रहा। चीन उप विजेता जबकि मेक्सिको तीसरे स्थान पर रहा। टीम तालिका में शीर्ष चार टीम सीधे क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं जबकि पांचवें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीम राउंड 16 मुकाबले खेलेंगी।भारत का सामना क्वार्टरफाइनल में फ्रांस और नीदरलैंड के बीच मुकाबले के विजेता से होगा। अगर भारतीय महिला टीम क्वार्टरफाइनल की बाधा पार कर लेती है तो उसे सेमीफाइनल में मजबूत कोरियाई टीम से भिड़ना पड़ सकता है।कोरियाई टीम ओलंपिक में अपराजेय रही है, उसने तीन साल पहले तोक्यो में लगातार नौवां पदक जीता था। व्यक्तिगत वर्ग में कोरिया की लिम सिहयिओन ने 694 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर से तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि उनकी हमवतन सुहियोन नाम 688 अंक से दूसरे स्थन पर रहीं। चीन की यांग जियाओलेई 673 अंक से तीसरे स्थान पर रहीं। दीपिका पहली बार मिश्रित टीम स्पर्धा में नहीं खेलेंगी क्योंकि अंकिता भारतीयों में शीर्ष पर रहीं। अंकिता पुरुष क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहने वाले तीरंदाज के साथ मिश्रित टीम फाइनल्स में जोड़ी बनाएंगी। पुरुष क्वालीफायर दोपहर के सत्र में शुरू होंगे।

स्पेन की जीत से शुरुआत, अर्जेंटीना पहला मैच हारा

पेरिस।एपी यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने उज्बेकिस्तान को 2-। से हराकर ओलंपिक खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की लेकिन लियोनेल मेस्सी के बिना खेल रहे विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा।

उज्बेकिस्तान ने स्पेन को कड़ी चुनौती दी और इसलिए दर्शकों का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिला। पेरिस ओलंपिक खेलों का पहला गोल स्पेन के राइट बैक मार्क पबिल ने 29वें मिनट में किया। एल्डोर शोमुरोदोव ने पहले हाफ के आखिर में पेनल्टी के ज़रिए अपना 41वां अंतरराष्ट्रीय गोल करके बराबरी की, जिसका उज्बेकिस्तान के प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। स्पेन की तरफ से सर्जियो गोमेज ने 62वें मिनट में निर्णायक गोल किया।इन खेलों में मेस्सी के बिना खेल रहे कोपा अमेरिका चैंपियन अर्जेंटीना को अपने पहले मैच में मोरक्को से 2-। से हार झेलनी पड़ी। मोरक्को की तरफ से दोनों गोल स्ट्राइकर सौफ़्याने रहीमी ने किए। मोरक्को की जीत जब सुनिश्चित लग रही थी तब अर्जेंटीना की तरफ से दूसरे हाथ के इंजरी टाइम मे क्रिस्टियन मदीना ने बराबरी का गोल कर दिया। मोरक्को के प्रशंसक मैदान पर उतर आए जिससे खेल खत्म होने से कुछ समय पहले मैच स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 घंटे तक खेल रुका रहा और जब खेल शुरू हुआ तो उससे कुछ देर पहले वीडियो प्रणाली से अर्जेंटीना का गोल ऑफ साइड होने के कारण अमान्य करार दे दिया गया। अन्य मैचों में इजरायल ने कड़ी सुरक्षा के बीच खेले गए मैच में माली को।-। से बराबरी पर रोका जबकि मेजबान फ्रांस ने अमेरिका को 3-। से हराया।

दूसरे दौर में भिड़ सकते हैं जोकोविच और नडाल

पेरिस।(एपी) शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक खेलो की टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल के दूसरे दौर मे अपने चिर प्रतिद्वंद्वी राफेल नडाल से भिड़ सकते है। गुरुवार को जारी किए गए ड्रॉ के अनुसार जोकोविच अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के खिलाफ करेंगे जबकि नडाल का सामना हंगरी के मार्टन फुक्सोविक्स से होगा। इन मैच मे जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी दूसरे दौर मे एक दूसरे का सामना करेंगे।ओलंपिक की टेनिस प्रतियोगिता उसी स्थल पर खेली जाएगी जहा फ्रेंच ओपन होता है। नडाल ने अपने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब मे से 14 खिताब फ्रेंच ओपन केरूप मे जीते है। उन्होने 2008 मे बीजिंग मे एकल जबकि 2016 मे रियो मे मार्क लोपेज के साथ मिलकर युगल वर्ग मे स्वर्ण पदक जीता था।फ्रेंच ओपन चैंपियन कार्लोस अल्कराज़ का सामना पहले दौर मे लेबनान के खिलाड़ी हैदी हबीब से होगा।महिलाओ के वर्ग मे पोलैड की शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक पहले दौर मे रोमानिया की इरिना कैमेलिा बेगू से भिड़ेगी जबकि अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ का सामना ऑस्ट्रेलिया की अजला टॉमलजानोविच से होगा।

एंडी मरे ओलंपिक टेनिस एकल से हटे, पेरिस में सिर्फ युगल में खेलेंगे

पेरिस। (एपी) दो बार के ओलंपिक टेनिस स्वर्ण पदक विजेता एंडी मरे ने गुरुवार को पेरिस खेलो की एकल स्पर्धा से हटने का फैसला किया और वह डैन इवांस के साथ केवल युगल स्पर्धा मे हिस्सा लेगे। ब्रिटेन के 37 साल के मरे ने कहा कि ओलंपिक उनके करियर का अंतिम टूर्नामेंट होगे। उन्होने इस महीने विम्बलडन की एकल स्पर्धा से भी हटने का फैसला किया था और युगल स्पर्धा मे भी अपने बड़े भाई जैमी के साथ एक ही मैच खेला था।मरे ने गुरुवार को कहा, मैंने डैन के साथ युगल स्पर्धा पर ध्यान लगाने के लिए एकल से हटने का फैसला किया।

पहले मैच में ब्रिटेन की हर्से से और शरत कमल स्लोवेनिया के कोजुल से भिड़ेंगे

पेरिस। भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मनिका बत्रा महिला एकल के शुरूआती दौर में ब्रिटेन की अन्ना हर्से से भिड़ेंगी जबकि अनुभवी पुरुष खिलाड़ी अचंता शरत कमल स्लोवेनिया के डेनी कोजुल के सामने होंगे। बुधवार को ड्रा की घोषणा हुई। मनिका को 18वीं वरीयता मिली है और यह उनका लगातार तीसरा ओलंपिक है। वह 2021 तोक्यो ओलंपिक में एकल में राउंड 32 में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी थीं। पुरुष एकल में हरमीत देसाई का सामना पहले दौर में जोर्डन के अबो यमन से होगा जबकि 25 साल की श्रीजा अकुला (16वीं वरीय) महिला वर्ग में स्वीडन की खिलाड़ी क्रिस्टिना कालबर्ग के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों के चैम्पियन शरत कमल भारत के टेबल टेनिस दल की अगुआई कर रहे हैं जिसमें 41 साल का यह खिलाड़ी ओलंपिक में पांचवीं दफा खेलने उतरेगा।

भारत तैयार, इस बार दहाई के पार

भाषा। पेरिस

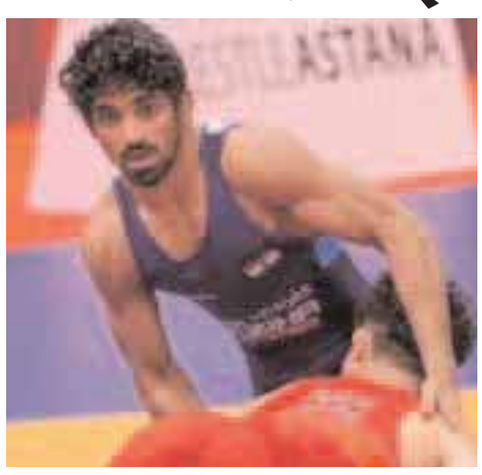

मंच सज चुका है और दुनिया भर के खिलाड़ियों की तरह भारत के 117 खिलाड़ी भी शुक्रवार से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जहां उनका लक्ष्य पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाना होगा। भारत ने तोक्यो ओलंपिक में सात पदक जीते थे जो उसका ओलंपिक खेलों में अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और भारतीय खिलाड़ी इसमें सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भले ही उन पर इसके लिए अपेक्षाओं का बोझ भी है लेकिन कुश्ती को छोड़कर किसी भी अन्य खेल के खिलाड़ी अपनी तैयारी को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं कर सकते हैं।

खिलाड़ियों को चाहे विदेश में अभ्यास करवाना हो या उन्हें सर्वश्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध करानी हो, किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और अब परिणाम देना खिलाड़ियों का काम है। लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि तोक्यो ओलंपिक के सात पदकों की संख्या की बराबरी करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को छोड़कर कोई भी अन्य खिलाड़ी पदक का प्रबल दावेदार नहीं है। भारत के 117 सदस्यों के दल में तीन खेलों एथलेटिक्स (29), निशानेबाजी (21) और हॉकी (19) के आधे खिलाड़ी शामिल हैं। इन 69 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। अन्य खेलों में भी कमोबेश यही स्थिति है और इस तरह से देखा जाए तो भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों पर होगी। भारतीय दल में हालांकि कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें अपना खेल का स्तर बढ़ाना होगा। इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश भी शामिल हैं जो निश्चित तौर पर अपना अंतिम ओलंपिक खेल रहे हैं। हॉकी टीम की ओलंपिक खेलों से पहले फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही जबकि मुक्केबाजों और पहलवानों को प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने का कम मौका मिला। निशानेबाजों ने भी ओलंपिक से पहले मिश्रित परिणाम हासिल किए। ट्रैक और फील्ड एथलीटों, विशेषकर अविनाश साबले ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में उनका प्रदर्शन उन्हें पदक के दावेदारों में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। स्टीपलचेज़र साबले लगातार अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर कर रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8:09.94 है, लेकिन सात अंतरराष्ट्रीय धावक हैं जिन्होंने उनसे बेहतर समय निकाला है। ऐसे में उनका फाइनल में पहुंचना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भारत की पदक की उम्मीदें नीरज तथा चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की फॉर्म में चल रही बैडमिंटन जोड़ी पर टिकी हैं। नीरज भले ही अभी तक 90 मीटर की दूरी तक भाला नहीं फेक पाए हैं लेकिन उन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। बड़ी प्रतियोगिताओं में वह अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं और उनके पास लगातार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी बनने का शानदार मौका है। इससे पहले पहलवान सुशील कुमार (2008 और 2012) तथा सिंधु (2016 और 2021) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही है उसे देखते हुए वह निश्चित तौर पर पदक की प्रबल दावेदार है। सिंधु भी लगातार तीसरा पदक जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी हाल की फॉर्म अच्छी नहीं रही और उन्हें मुश्किल ड्रॉ भी मिला है। हॉकी में भारत में पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीत कर 41 वर्ष के लंबे इंतजार को खत्म किया था लेकिन हाल में टीम के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है। पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलना और लय बनाए रखना टीम की सबसे बड़ी चिंता है।यही नहीं भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। ऐसे में टीम को छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है।। निशानेबाजी में भारत के 21 खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे जिनमें मनु भाकर और सौरभ चौधरी भी शामिल हैं जिन्हें पदक का दावेदार माना जा रहा है। इनके अलावा सिफत कौर समारा (50 मीटर थ्री पोजिशन), संदीप सिंह (10 मीटर एयर राइफल) और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (पुरुषों की 50 मीटर राइफल) ने भी निशानेबाजी में पदक का 12 साल का इंतजार खत्म करने का माद्दा दिखाया है। वर्तमान में भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग 2012 लंदन खेलों में 10 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक जीतकर पोडियम पर पहुंचने वाले आखिरी भारतीय निशानेबाज थे। कुश्ती में भारत ने पिछले चार ओलंपिक खेलों में पदक जीता है लेकिन इस बार भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण खिलाड़ियों की तैयारी अनुकूल नहीं रही हैं। इसके बावजूद अंशु मलिक, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत को भारत का सबसे अच्छा दावेदार माना जा रहा है। अंडर-23 विश्व चैंपियन रीतिका हुड्डा भी छुपी रुस्तम साबित हो सकती है। अन्य खेलों में तीरंदाजी और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने अपनी रैंकिंग के आधार पर खेलों में जगह बनाई है। तीरंदाजी में भारत लगातार ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा है लेकिन उसे अभी अपने पहले पदक का इंतजार है। पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू पिछले कुछ समय से चोट और खराब फॉर्म से जूझ रही हैं। मुक्केबाजी में निकहत जरीन और निशांत देव से उम्मीद की जा सकती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं। इनमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा (2008) और नीरज चोपड़ा (2021) ही व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत पाए हैं।

पदकों की हैट्रिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं पीवी सिंधु

पेरिस। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु लगातार तीसरे ओलंपिक खेलो मे पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए किसी भी तरह की कसर नही छोड़ रही है और उन्होने अपना यह लक्ष्य हासिल करने के लिए पिछले कुछ महीनो मे अलग-अलग तरीको से कड़ा अभ्यास किया है। सिंधु ने रियो ओलंपिक मे रजत और तोक्यो ओलंपिक मे कांस्य पदक जीता था। अगर वह पेरिस ओलंपिक मे पोडियम पर पहुंचने मे सफल रहती है तो फिर वह पदको की हैट्रिक पूरी करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। सिंधु पिछले कुछ समय से अच्छी फॉर्म मे नही चल रही है लेकिन उन्होने कहा कि पिछले आठ महीने प्रकाश पादुकोण के साथ बिताने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वह लगातार तीसरा पदक जीतने के लिए तैयार है। सिंधु ने पोर्ट डे ला चैपल एरिना मे अभ्यास सत्र के बाद कहा, निश्चित रूप से पदक जीतना मेरा लक्ष्य है। यह पहला हो या दूसरा या फिर तीसरा यह मायने नही रखता। मैंने दो पदक जीते है और मै तीसरे पदक के बारे मे सोच कर खुद पर दबाव नही बनना चाहती हूं। उन्होने कहा, जब भी मै ओलंपिक मे भाग लेती हूं तो वह मेरे लिए नया ओलंपिक होता है। इसलिए मै जब भी ओलंपिक मे खेलने के लिए उतरती हूं तो मेरा लक्ष्य पदक जीतना होता है।

आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने गोलों की क्लिप देखता हूं : सुखजीत

नई दिल्ली। दो साल पहले भारतीय हॉकी टीम में पदार्पण करने वाले फॉरवर्ड सुखजीत सिंह पेरिस में ओलंपिक में पदार्पण को लेकर कतई नर्वस नहीं है और आत्मविश्वास बढाने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय गोलों की क्लिप देखते रहते हैं। सुखजीत भारतीय टीम में शामिल उन पांच खिलाड़ियों (अभिषेक, राजकुमार पाल, जरमनप्रीत सिंह, संजय) में से हैं जिनके लिए पेरिस उनका पहला ओलंपिक होगा। तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। पंजाब के तरण तारण में जन्मे सुखजीत ने खानगी से पहले भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा , मैंने 2022 में भारतीय टीम में पदार्पण किया और एफआईएच प्रो लीग में स्पेन के खिलाफ पदार्पण मैच में ही गोल किया था। अब तक का सफर अच्छा रहा है और हर मैच में सर्वश्रेष्ठ करने की ही कोशिश रहती है। अब तक 70 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 22 गोल कर चुके सुखजीत ने कहा कि वह ओलंपिक के दबाव का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं।उन्होंने कहा , मुझे दबाव बिल्कुल नहीं लग रहा। हमने बड़े टूर्नामेंट खेले हैं तो दबाव का सामना करना बखूबी आता है। अपनी तैयारियों के दम पर बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलने का यकीन है।

एआईसीएफ के पूर्व प्रमुख संजय कपूर फिडे भारत क्षेत्र के अध्यक्ष चुने गए

नई दिल्ली। (भाषा) अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के पूर्व प्रमुख संजय कपूर को सर्वसम्मति से बृहस्पतिवार को फिडे भारत क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया। देश में खेल की शीर्ष संस्था ने यह जानकारी दी। अहमदाबाद में एआईसीएफ की आम सालाना बैठक (एजीएम) के दौरान यह घोषणा की गई। कपूर को चार साल के लिए क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया और फिडे अध्यक्ष अरकाडी दवोरकोविच ने उन्हें बधाई दी। कपूर की नई भूमिका भारत में शतरंज प्रशासन के लिए अहम पल है जिसमें उन्हें वैश्विक स्तर पर खेल के विकास और प्रगति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति पर कपूर ने कहा, फिडे भारत क्षेत्र का अध्यक्ष चुना जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।

तुषारा चोट के कारण भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला से बाहर

पालेकल। (भाषा) श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा अभ्यास के दौरान हाथ में चोट लगने के कारण भारत के खिलाफ तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। इस 29 वर्षीय खिलाड़ी के बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। श्रीलंका ने तुषारा की जगह एक अन्य तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल किया है।

सीन नदी पर ओलंपिक उद्घाटन के दौरान हो सकती है बारिश

पेरिस। (एपी) सीन नदी पर पेरिस ओलपिक के अनूठे उद्घाटन समारोह के दौरान मौसम की गाज गिर सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश का अनुमान जताया है। फ्रांस के मौसम विभाग मेटियो फ्रांस ने शुक्रवार की सुबह बारिश की भविष्यवाणी की है। दोपहर को मौसम साफ रहेगा लेकिन शाम को बारिश हो सकती है जिस समय उद्घाटन समारोह होना है। बारिश होने पर भी उद्घाटन समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत प्रबल दावेदार

महिला एशिया कप सेमीफाइनल

दाम्बुला। (भाषा) भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहां एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर मैदान में उतरेगी जिसमें शेफाली वर्मा की निगाहें आक्रामक प्रदर्शन करने पर लगी होंगी जबकि स्मृति मंधाना भी बड़ा स्कोर बनाने के लिए बेताब होंगी। शेफाली ने अभी तक 158 रन बनाए हैं जिससे वह टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। निगार सुल्ताना की टीम के खिलाफ शेफाली को अच्छी शुरूआत करानी होगी क्योंकि विपक्षी टीम के पास धीमी गति के गेंदबाजों की भरमार है।

भारतीय महिला टीम ने सभी तीनों मुकाबलों में प्रतिद्वंद्वी टीम को मात दी है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 78 रन से और नेपाल के खिलाफ 82 रन के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर जानती हैं कि एशिया कप में सेमीफाइनल और फाइनल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट के इस चरण में खतरनाक टीम हो सकती है। भारत के लिए शुरुआत काफी अहम होगी इसलिए शेफाली चाहेंगी कि उनकी सीनियर सलामी जोड़ीदार मंधाना भी अच्छा प्रदर्शन करें। बाएं हाथ की यह खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 45 रन की पारी के दौरान शानदार फॉर्म में थी। ग्रुप लीग चरण में भारतीय टीम यूएई और नेपाल से भिड़ी थी।

टी20 श्रृंखला:पंत और सैमसन में से एक का चयन बड़ी चुनौती

कोलंबो। (भाषा) भारतीय क्रिकेट टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसी एक का चयन करना चुनौतीपूर्ण होगा। छोटे प्रारूप से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़कर टी20 विश्व कप विजेता टीम के अधिकतर खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर आए हैं और ऐसे में पंत और सैमसन में से किसी एक का चयन करना आसान नहीं होगा क्योंकि यह दोनों ही आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में भले ही दो स्थान खाली हैं लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक को बल्लेबाज के रूप में उतारना भी आसान नहीं होगा। पंत ने टी20 विश्व कप में 171 रन बनाए जबकि सैमसन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला जबकि वह टीम का हिस्सा थे। भारत और श्रीलंका के बीच यह श्रृंखला भारतीय टीम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली श्रृंखला है जबकि टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। गंभीर के पिछले रिकार्ड को देखते हैं तो यह निश्चित है कि टीम संयोजन में उनकी बात को अधिक तवज्जो दी जाएगी। पंत जब दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में घायल होने के बाद टीम से बाहर थे तब विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन, सैमसन, जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल को आजमाया गया। अगर पंत और सैमसन के आंकड़ों पर गौर करें तो वह काफी हद तक समान नजर आते हैं। सैमसन ने अभी तक 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 133 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इनमें से 27 मैच उन्होंने 2020 के बाद खेले हैं जबकि उन्होंने 2015 में इस प्रारूप में पदार्पण कर लिया था।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।